

प्रापिकार ने प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₩ 49]

नद्वी विस्ती, सनिवार विसम्बर 4, 1982/अत्रहायण 13, 1804

No. 49)

NEW DELHI, SATURDA\ DECEMBER 4, 1982/AGRAHAYANA 13, 1904

इस क्रमा में भिन्न पृष्ठ संस्था दी जाती है जिससें कि यह अलग संकलन के रूप में एका जा सकें Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate complication

भाग II—सवड 3—अप-सवड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्राजय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और आधसूचनाइ Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

का॰ आ॰ 3975.—केन्द्रीय सरकार, विल्ली विशेष पुलिस स्थापन सिधिनियम, 1946 (1946 का 25) की घारा 3 हारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए निस्तिलिखन धपराधों को, ऐसे ध्रपराध पीपित करती है, जिनका श्रम्येषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया जाएगा, सर्थालु:→

- (क) भारतीय दंड मंहिता, 1860 (1960 वा 45) की धारी 367 के अर्धन दंडनीय ध्रपराध
- (का) का क (का) में विशिध प्रपराधों में से एक या एक से श्रविक श्रवराधों के सबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्न, दृष्प्रेरणाए और पश्यंत भीर इन्हीं तथ्यों से उद्भृत उमी संव्यवहार के दौरान किया गया श्रत्य कोई भवराध।

[संख्या 328/6/82/ए०वी०की०-11] एच० के० वर्मा, उप मंचिय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)
New Delhi, the 17th November, 1982

S.O. 3975.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25

of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

- (a) Offerces punishable under section 367 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860); and
- (b) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, one or more of the offences mentioned in clause (a) and any other offence committed in the course of the same transection arising out of the same facts

[No. 228/6/82-AVD-II] H. K. VERMA, Under Secy.

न्दास जांच आयोग

गोधी णानि प्रतिष्ठान ग्**र्व ध**न्य संगठनों के **बारे मे** संगोधन

नई विरुली, 25 नवम्बर, 1982

का॰आ॰ 3976.—इस धार्योग की नार्यविधि को विनियमित करने वासे प्रादेश के पैरा 3 की, जिसे तारीख 26 जुलाई, 1982 की प्रक्षित्वना सं 1/1/82-के वर्या॰ प्राई॰ के नहन जारी किया गया था, इस प्रकार पढ़ा जाये :—

'कार्यालय का पता 3 22-11-1982 मे, सनले मादेशों तह, इस प्रायोग का मुख्यालय कमरा नं 13, "सी" विंग, दूसरी मजिल, लांक नायक भवन, नजदीक खान मार्कीट, नई दिल्ली-110003 में होया भीर जब सक पते में कोई परिवर्तन अधिम् जिल न किया जाए तब सक सभी पतावि सिचन, कृदास जीन आयोग—गांधी गांति प्रसिष्ठान एवं भ्रम्य संगठमों के बारे में—कमरा नं॰ 21, "सी" विंग, दूसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नजबीक खान मार्कीट, नई विल्ली-110003 के पते पर भेजे लायें।"

भागोग के भादेश स।

[सं॰ 1/1/82-के॰सी॰माई॰] को॰ एम॰के॰ महरू, सचित्र

Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other Organisations

AMENDMENT

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 3976.—Para 3 of the Order regulating the procedure of this Commission issued vide Notification No. 1/1/82-KCI dated the 26th July, 1982 may be read as under:—

"Official Address.—3 Until further orders, the Head-quarters of the Commission will be at Room No. 13, 'C' Wing, IInd Floor, Lok Nayak Bhavan, Near Khan Market, New Delhi-110003, with effect from 22-11-1982 and all communications should be addressed to the Secretary to the Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other Organisations, Room No. 21, 'C' Wing, IInd Floor, Lok Nayak Bhavan, Near Khan Market, New Delhi-110003, till a change in address is notified."

[No. 1/1/82-KCI] B. M. K. MATTO, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 मन्नैल, 1982

माय-कर

का॰ आ॰ 3977.— सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रधिसुवित किया जाता है कि विहित प्राधिकार, प्रथति विज्ञान धौर प्रौद्योगिक। विभाग नई दिल्ला से निम्नलिखित संस्था को प्रायकर निमम, 1962 के नियम 6 के संध्य पठिंत प्रायकर प्रधिनियम, 1961 की धारा 35 की जपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए प्रस्य प्राकृतिक धौर भनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में "संगम" प्रयमं के प्रधान निम्नलिखित शतौं पर धनु-मोदित किया है धर्यात् :—

- (i) यह कि जैन वैज्ञानिक अनुसंघान धीर विकास प्रतिष्टान, नई वित्त्रों कृषि/पशुपालन/मास्स्यकी और श्रीविधि से भिन्न प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में बैज्ञानिक अनुसंघान के लिए प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) उक्त संगम प्राप्त वैज्ञानिक धनुसंघान संबंधी कियाकलापी की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 प्रप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए प्रधिकथित किए जाएं ग्रीर उसे सूचित किए जाएं।
- (iii) उक्त प्रतिष्ठान वार्षिक विवरणी ग्रीर लेखार्मो का वार्षिक विवरण प्रति वर्ष ग्रायकर ग्रायुक्त को ग्रेजेगा।

संस्था

जैन वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, नई विल्ली यह अधि-सूचना 26-12-1981 से 25-12-1983 तक वो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

> [सं॰ 4582/फा॰ सं॰ 203/193/80-माई टी ए(II)] भवन गोयल, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)
New Delhi, the 23rd April, 1982
INCOME TAX

- S.O. 3977.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of subsection (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Inome-tax Rules, 1962 under the category of "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:—
 - (1) That the Jain Foundation for Scientific Research and Development, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than Agricultural/Animal husbandry/Fisheries and medicines.
 - (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimate to them for this purpose by 30th April each year.
 - (iii) That the said Foundation will submit the Arnual returns and statement of Accounts to the Commissioner of Income-tax for every year.

INSTITUTION

Jain Foundation for Scientific Research and Development, New Delhi.

This notification is effective for a period of two years from 26-12-1981 to 25-12-1983.

[No. 4582/F. No. 203/193/80-ITA (ii)]
M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1982

अधिकर

कां आं 3978.—मायक्तर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अमुसरण में और मारत सरकार केराजस्व विभाग की विनांक 3-5-80 की मधिसूचना सं 3280 का मधिसंधन करते हुए, केम्ब्रीय सरकार एनद्बार। श्री एस० सी० गुप्त-II को, जो केन्द्रीय सरकार एनद्बार। श्री एस० सी० गुप्त-II को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपवित मधिकारी हैं, उक्त मधिनियम के मधीन कर वसूली भिष्ठ कारी की गवितयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

यह भिधिसूचना और एस॰ सी गुन्त-II द्वारा कर वसूली भिक्षकारी
 के रूप में कार्नभार ग्रहण करने की क्षार्रक से लागू होगी।

[सं॰ 4650 (फा॰ सं॰ 398/14/81-मा॰ क॰ द॰ (खंड 1)]

New Delhi, the 1st June, 1982 INCOME TAX

S.O. 3978.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3280 (F. No. 398/3/80-ITB) dated 3-5-80, the Central Government hereby authorises Shri S. C. Gupta-II being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri S. C. Gupta-II takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4650/F. No. 398/14/81-ITB (Pt. I)]

नई विख्ली, 3 जून, 1982

माय-कर

का० आ० 3979.—मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के भ्रानुसरण में भ्रीर भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-6-80 की भिध्नसूचना सं० 3498 (फा० सं० 398/15/80-आ० क० स० क०) का भ्रीधलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्रारा, श्री ए० ग्रार० पिपलबार को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपन्नित मिकारी है, उक्त भिधिनयम के ग्रंतर्गत कर वसूली मिधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकत करनी है।

2. यह मिश्रियना, श्री ए० घार० पिम्पलवार द्वारा कर वसूली मधि-कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4658/ फा॰ सं० 398/5/82-मा॰ क॰ **ब॰**]

New Delhi, the 3rd June, 1982

INCOME TAX

- S.O. 3979.—In pursuance of sub-clause (ili) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in pursuance of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3498 (F. No. 398/15/80-ITCC) dated 30-6-80, the Central Government hereby authorises Shri A. R. Pimpalwar, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri A, R. Pimpalwar takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4658/F. No. 398/5/82-ITB]

ग्राय-कर

कांश्यां 3980 --- भायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 13) की धारा 2 के खंड (44) के उप-खंड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की विनांक 30-6-81 की भिधिसूचना सं० 4066 (फा॰ सं० 398/20/81-भा॰ कंस॰ क॰) का भिधिसूचना करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतवृद्धारा भी डी॰ भार॰ नन्दा को ओ केन्द्रीय सरकार के राजपित स्थिक रो हैं, उन्त भिधिनियम के भन्तगैत कर वसूनी भिधिकारी की शिक्तयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

 यह मधिसूचना श्री डी० ग्रार० नग्दा द्वारा कर तसूनी मधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तल्दीख से लागू होगी।

[सं० 4660/फा॰ सं० 398/25/82-मा० क० व०]

INCOME TAX

- S.O. 3980.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 4066 (F. No. 398/20/81-ITCC) dated 30-6-81, the Central Government hereby authorises Shri D. R. Nanda, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery officer under the sald Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri D. R. Nanda takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4660/F. No. 398/25/82-ITB]

माय-कर

की बार 2 के सांव (44) के उपखंद (iii) के धनुसरण में तथा मारत

सरकार के राजस्व विधाग की दिनांक 30-6-79 की कि सूचना संदर्धा 2918 (फा० सं० 404/134/का० व० घ० उड़ सः/79-अ०क० स० क०) को अधिकान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन० पी० रामाराज को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपित अधिकारी है, उसते धीवनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शिवनयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकार कर तरही है।

 यह ग्राधिसूचना श्री एन० पी० रामाराव द्वारा कर वसूली श्रीव-कारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारेख से लागू होता.

[सं० 4662/ फा॰ सं० 398/21/82-ग्रा॰ क॰ व॰]

INCOME TAX

- S.O. 3981.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 2918 (F. No. 404/134/TRO-Orissa/79-ITCC) dated 30-6-79, the Central Government hereby authorises Shri N. P. Rama Rao being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri N. P. Rama Rao takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4662/F. No. 398/21/82-ITB]

नई विल्पा, 18 जून, 1982

ग्राय-कर

का० औ० 3982.— प्रायकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप खंड (iii) के म्रनुसरण में भीर भारत सरकार के राजस्व विभाग की विनाक 16 1 80 की प्रधिसुमना सं० 3133 (फा० सं० 404/22/क० व० भ्र०-प० बं०/79-प्रा० क० स० क०) का भिक्षंभन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतथ्डारा श्री बो०एस० बिस्वास की, जो केन्द्रीय सरकार के राजपवित भिक्षंभारी हैं, उक्त भिधितयम के ग्रन्सगैत कर वसूनी मिक्सारी की णक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती. है।

यह प्रशिस्ताना, श्री बी० एस० विस्तास द्वारा कर वसूली प्रधिकारी
 के कप में कार्यभार प्रहुण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 4702/फा० सं० 398/19/82-मा० क० य०]

New Delhi the 18th June, 1982 INCOME TAX

- 8.0, 3982.—In exercise of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3133 (F. No. 404/22/TRO-WB/79-ITCC) dated 16-1-80, the Central Government hereby authorises Shri B. S. Biswas, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri B. S. Biswas takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 4702/F. No. 398/19/82-ITB]

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1982

ग्राय-कर

का० आ० 3983.— प्रायकर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 2 के खंड (44) के उप खंड (iii) के धनुसरण में भीर भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 3-5-80 की धिंधसूचना सं० 3276 (फा० सं० 398/3/80-धा० क० स० क०) का प्रधिलंधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्दारा श्री राजेंड प्रसाद की, जी केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित घिष्कारी हैं, उक्त प्रधिनियम के धंसगत कर वसूली प्रधिकारी की प्रवित्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

 यह मिन्नसूचना, श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा कर बसूली प्रधिकारी क क्य में कार्यमार प्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

> [स॰ 4791 /फा॰ सं॰ 398/11/81-घा० म॰ ध॰] एन० घे० मनल धवर सन्विव

New Delhi, the 12th July, 1982 INCOME TAX

- S.O. 3983—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 3276 (F No. 398/3/80-ITCC) dated 3-5-80 the Central Government hereby authorises Shri Rajinder Prasad, being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri Rajindei Prasad takes over chaige as Tax Recovery Officer

[No 4791/F No 398/14/81-ITB] N K SHUKLA, Under Secy

नर्व फिल्लो, 21 अगस्त, 1982

ग्राय-कर

कां आ० 3984 — भायकर भिषित्यम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उप खंड (11) वे अनुसरण में भीर भारत सरकार के राजस्य विभाग की दिनांक 1-6-82 की अधिसूचना स० 4650 (फा॰ सं॰ 398/14/81 भा॰ क॰ ब॰) का अधिलधन करते हुए, कंन्द्रीय सरकार एतव्हारा श्रीमतो सुमति के॰ मेहना को, जो केन्द्रीय सरकार की राजपनित भिष्कारों हैं, उक्त अधितयम के भत्नीत कर अभूती अधिकारों की कक्तियों का असीन करने के लिए अधिकृत मर्सा है।

 यह प्रक्रिस्चना, श्रीमनी सुमति के मेहता द्वार। कर बसूली श्रीध-कारी के क्प में कार्यमार प्रहण किए जाने की तारीख से लागू हांगी!

[ধ০ 4 8 7 ৪/ फा॰ स॰ 3 9 ৪/ 1 4/ ৪ 1-সাংক্তৰ ০]

New Delhi, the 21st August, 1982 INCOME TAX

- 6.0. 3984—In pursuance of sub-clause (m) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 4650 (F. No. 398/14/81-ITB) dated 1-6-82, the Central Government hereby authorities Smt. Sumati K. Mehta, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. This Notification shall come into force with effect from the date Smt Sumati K Mehta takes over charge as Tax Recovery Officer

[No. 4876/F. No 398/14/81-ITB]

नई दिन्हीं, 13 मिलम्बर 1982

शाय-कर

का॰ मा॰ 3985 --- आयका प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपकार (10) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्य विभाग की विनांक 23-1-79 की अधिसूचना स० 2678 (का॰ स० 404/22क ॰ स० १००/पं०)/79-भा० क॰ स० क॰ का भिर्मिक करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसवृद्वारा श्री की भौमिक को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित भधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर सबुसी अधिकारी की सक्तियों का स्वीतर्ग करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

2 यह अधिसूचना, श्री ही॰ भौमिक द्वारा कर वसूली अधिकारी के इन्द्र में कृश्वैद्यार प्रहुण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[मं॰ 4909 /फा॰ सं॰ 398 19 82-मा॰ व॰ व॰]

New Delhi, the 13th September, 1982 INCOME TAX

- SO. 3985.—In pursuance of sub-clause (in) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 2678 (F No 404/22/TRO-WB/79-ITCC dated 23 1-79, the Central Government hereby authorises Shri D Bhowmick, being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act
- 2 This Notification shall come into force with effect from the date Shri D Bhowmick takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No 4909/F No 398/19/82-ITB]

नई दिल्ली, 12 ध्रन्तबर, 1982

प्राय-कर

कार आरं 3986 -- मायकर अधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खड़ (44) के उप खंड (11) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्य विभाग की दिनाक 10-8-1982 की मधिसूचना सर् 4863 (कार सर 398/8/81-अ व्वव्या) का प्रक्षिल्यन करते हुए, वेन्द्रीय सरक र एतद्द्रारा श्री बीर एनर के बर्मी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपित प्रधिनारी हैं, उक्त प्रधिनियम के अंतर्गत कर वसूसी प्रधि-कारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अपह प्रधिमुखना, श्री बी० एन० के० वर्मा द्वारा कर वसूली प्रधि-कारी के रूप में नार्यभार ग्रहण किए जाने की नार्रेख से लागू हार्ग।

> [म॰ 1945/फा॰ र्स॰ 398/8/81-धा॰ क॰ब॰] धार॰ सी॰ हांडा, उप सचिव

New Delhi, the 12th October, 1982 INCOME TAX

- 5 O. 3986.—In pursuance of sub-clause (m) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No 4863 (F No 398/8/81-11B) dated 10-8 82 the Central Government hereby authorises Shri B N K Verma, being a gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2 This Notification shall come into force with effect from the date Shri B N K Verma takes over charge as Tax Recovery Officer

[No 4945/F. No 398/8/81-ITB] R. C HANDA, Dy. Secy

मई बिल्ली, 25 प्रगस्त, 1982

माय-कर

का० आ० 3987 -- केन्द्रीय सरकार आय-वर श्रिष्ठिनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खड़ (V) द्वारा प्रवत्त शिक्तयों का प्रयाग वरने हुए, "श्री प्रधान।म स्वामी मृदिर भ्यास को निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के श्रतगंत श्राने वाली श्रवधि के लिए उनत धार। के प्रयोजन। श्रीधसूचित करती है।

[सं॰ 4878/फा॰ स॰/197/66/8 এ-সা॰ व॰ (ए॰ I)]

New Delhi, the 25th August, 1982 INCOME TAX

S.O. 3987—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sice Padmanabhaswami Temple Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85

[No 4878/F No 197/66 '82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 31 अगस्न, 1982

ग्राय-कर

का॰ आ॰ 3988 — केन्द्रोय सरकार, श्राय-कर श्रीविनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-म) के खंड (V) इरारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करने दुए, "श्री बाहुबन्ति ब्रह्मचर्याश्रम बाहुबन्ति" को निर्धारण वर्ष 1981-82 भीर 1982-83 के शंतर्गत प्राने वाली श्रवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ श्रीधसुन्तित करती है।

[सं० 4894/फा० सं० 197/30/81-म्रा०क (ए I)]

New Delhi, the 31st August, 1982 INCOME TAX

S.O. 3988.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Bahubali Brahmacharyashram Bahubali" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4894/F. No. 197/30/81-IT(AI)]

भाय-कर

का॰ आ॰ 3989 .--केन्द्रीय सरकार, ग्राय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 10 की उपघारा (23-ग) के खंड (V) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि कीग्रिगेणन ऑफ दि ब्रद्धसे ऑफ सेकेड हार्ट, पलायम कीटाइ" की निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 के ग्रन्तगंत ग्राने वाली श्रविध के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ ग्रिध-सूचित करसी है।

[स॰ 4895/का• सं॰ 197/106/79-का॰ क (ए र्ॉं)]

INCOME TAX

S.O. 3989.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Congregation of the Brothers of Sacred Heart, Palayam-kottal" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1977-78 to 1981-82.

[No. 4895/F. No. 197/106/79-IT(AI)]

स्राय-कर

का॰ आ॰ 3990 --- केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर घ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (V) द्वारा प्रवत्त धाक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि सोसाइटी औक धावर लेंडा खांक डोलर्स, वि सर्वेन्ट्स घाँफ मेरी" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के घंतर्गत घाने वाली घवधि के लिए उनत धारा के प्रयोजनार्थं घिस्चित करती है।

[सं० 4897/फा॰ सं० 197/195/81/ग्रा॰ क (ए J)]

INCOME TAX

S.O. 3990.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Society of Our Lady of Dolours. The Servents of Mary" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4897/F. No. 197/195/81-IT(A1)]

ग्राय-कर

का० आ० 3991 ...ं-केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर प्रधितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधार। (23-ग) के खंड (V) द्वारा प्रवस गिकायों का प्रयोग करने हुए, "प्राविद्यायोस आफ तिर्वेद्रम" की निर्धारण वर्ष 1982-83 के प्रयोग काने वाली प्रविधि के लिए उकत धारा के प्रयोजनार्थ प्रधिस्चित करती है।

[#০ 4৪৭৪/फে০ #০/197/৪5/৪০-সা০িক১(r:o I)]

INCOME TAX

S.O. 3991.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Archidiocese of Trivandrum" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1982-83.

[No. 4896/F. No. 197/85/80-IT(A])]

नई दिल्ली, 2 सिन्तम्बर, 1982

आय-कर

का॰ आ॰ 3992,---केन्द्रीय सरकार, भाय-कर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43)की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करने तुए, "कुन्डा कीनम डायोंसेस सोमायटी, कुन्डा कीनम" को निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के भंगाँत झाने वाली अविध के लिए उक्त धारा के प्रयोगनार्थ अधिस्थित करती है।

[#o 4900/फा॰सं॰ 197/93/80-प्रा॰सं॰ (एI)]

New Delhi, the 2nd September, 1982

INCOME TAX

S.O. 3992.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kumba Konam Diocese Society, Kumbakonam" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1979-80 to 1982-83.

[No. 4900/F. No. 197/93/80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 21 सिनम्बर, 1982

आय-कर

का॰ आ'॰ 3993 केन्द्रीय सरकार, आय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त गिक्षियों के प्रयोग करने हुए, "श्री वैदाल देशिकर देवस्थानम मायलापुर को निधीरण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली सर्विष के लिए उक्त धारा के प्रयोगना वं स्रधिन्धित करती है।

[सं॰ 4918[फा॰मं॰ 197/56/82/प्रा॰क॰ (ए I)]

New Delhi, the 21st September, 1982

INCOME TAX

S.O. 3993.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Vedantha Desikar Devasthanam, Mylapure" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4918/F. No. 197/56/82-IT(AI)]

आय-५र

का०आ० 3994 केर्न्द्राय सरकार, श्राय-कर श्रिष्ठित्यम, 1961 (1961 का 43) की घारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री श्रानखपुर न्यास" की निर्धारण वर्ष 1981-82 श्रीर 1982-83 के अंतर्गत भाने वाली श्रविध के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ श्रिधसुचित करती है।

[सं० 4919/फा०सं० 197/216/80-ब्रा०क० (ए-1)]

INCOME TAX

S.O. 3994.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); the Central Government hereby notifies

"Shri Anandpur Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

INo. 4919/F. No. 197/216/80-IT(AI)?

नई दिल्ली,30 सितम्बर 1982

आंग्र-कर

का॰ अ१९० - केन्द्रिय सरकार, माय-कर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त मिन्याक, प्रयोग करते हुए, "श्री ठाकुरजी लक्ष्मीनाम जी न्यास भुतस्तुन" को निर्वारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के मन्तर्गत भाने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनाम प्रधिन् चित्त करती है।

[र्सं० 4930/फा॰सं० 197/169/79 आ॰फ॰(ए॰l)]

भिलाप जैन, प्रवर सचिव

New Defhi, the 30th September, 1982 INCOME TAX

S.O. 3995.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Thakurji Laxmi Nath Ji Trust, Jhunjhunu" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 4930/F. No. 197/169/79-IT(AI)]

MILAP JAIN, Under Secy.

आधिक कार्य विभाग

(वें किंग प्रभाग)

नई विय्यो, 13 नवस्थर, 1982

का अगा 3996 - बैंकका से जिनियमन घिषिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रवक्त णिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतदद्वारा घोषणा करती है कि उक्त प्रधिनियम की धारा 10वा की उपधारा (1) और (2) के अपबंध बैंक प्रांप समिलनाडु लिमिटेड, निक्तेल बेली पर 4 मनस्मर, 1982 से 3 फरवरी, 1983 नक 3 महीने की प्रविध के लिए, प्रववा उक्त बैंक मे भगले पूर्णकालिक भध्यका की नियुक्ति होने तक, इनमें से जी पहले हो उस समय तक लागू नहीं हों।

[संख्या 15/21/82-बी०मी०-[[]]

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(Banking Division)

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 3996.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of subsections (1) and (2) of section 10B of the said Act, shall not apply to Bank of Tamilnad Ltd., Trunulveli, for a period of 3 months with effect from 4th November, 1982 upto 3rd February 1983, or till the appointment of the next wholetime Chairman of that bank whichever is earlier.

[No. 15/21/82-B.O. 111]

कां आं 3997.— बैककारी विलियमन प्रिधिनियम, 1949(1949 का 10) की धीरा 53 हारा प्रदत्त सकिनयों का प्रयाग करते हुए केस्वीय सरकार भारतीय रिजर्क बैंक की सिफारिश पर एतदब्रारा घोषणा करती है कि उक्त भविनयम की धारा 10 ख की उपधार, (1) भीर (2) के उपबंध मिराज स्टेट बैंक लिसिटेड मिराज पर 3 नवस्थर, 1982 से

2 मार्च 1983 तक 40 महीने की घवधि के लिए मचवा घगले घध्यक्ष के कार्यमार संमालने तक, इनमें से जो भी पहले ही उस समय तक लागू महीं होंगे।

> [म॰ 15/29/82-बी॰मो॰]]। एन॰डी॰ बहा, प्रतर मचिन

S.O. 3997.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of subsections (1) and (2) of Section 10B of the said Act, shall not apply to Miraj State Bank Ltd., Miraj for a period of 4 months with effect from 3rd November, 1982 upto 2nd March, 1983 or till the new Chierman assumes charge, whichever is earlier.

[No. 15/29/82 B.O. III] N. D. BATRA, Under Secy.

विवेश संशालय

नई दिल्ली, 12 नदस्बर, 1982

का॰ आ॰ 3998.—राजनियक एवं कोंमिली श्रविकारी (गपण एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खंड 2 की धारा (क) के श्रनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का हाई कमीगन, सुमाका, जान्विया में सहायक श्री विमल कपूर को तस्काल से कोंननी एजेन्द्र का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[ਜਂ∘ਈ 4330(2)823]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 3998.—In pursuance of the clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri Bimal Kapoor, Assistant in the High Commission of India, Lusaka, Zambia to perform the duties of Consular Agent with immediate effect.

[No. T. 4330 (2)/82]

का०आ० 3999.—राजनियक एवं कोंसली मिश्रकारी (भाष एवं भुक्त) मिश्रिनियम, 1948 (1948 का 41वां) के खंड 2 की धारा (क) के मनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, भारत का राजदूतावास, बहरीना में सहायक श्री जे०भार० मानकतला को तत्काल से कोंसली एजेंग्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं•टी 4330/2/82] बी॰ एस॰ निडर, ग्रदर मचित्र

S.O. 3999.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officer (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948) the Central Government hereby authorise Shri J. R. Manaktala, Assistant in the Embassy of India, Bahrain to perform the duties of Consular Agent with Immediate effect.

[No. T. 4330/2/82] B. S. NIDDAR, Under Secy.

बाणिषय मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवस्त्रर, 1982

का॰ प्रा॰ 4000.—केस्रीय सरकार, काफी प्रधिनियम, 1942 (1942 का 7) की घारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए, काफी बोर्ड साधारण सर्विष्य निधि नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात, :---

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काफी बोर्ड साधारण भविष्य निर्मित्र (संगोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपन्न में प्रकाशन की नारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मार्फा बोर्ड माधारण भविष्य मिधि नियम, 1965 में, नियम 8 में, उपनियम (३) के प्रचान निम्नलिखत उपनियम श्रंत स्वापित किया जाएगा, प्रवात —(4) उपनियम (1) में किसी बात के हाते हुए भी कोई मियाता, निधि में उम मास के निए जिसमें वह सेवा छोड़ता है तक सक मियाय नहीं करेगा, जब तक कि उसने उक्त मास के प्रारम्भ से पूर्व उक्त मास के लिए मियाय करने का मपमा विकल्प लेखा मधिकारी की लिखत, कप में संमुचिन न कर दिया हो।"

[फाइल सं॰ 1/17/82-प्लाट (बी)] बी॰एम॰एस॰ नेगी, प्रवर मखिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th November, 1982

S.O. 4000.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act. 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Board General Provident Fund Rules, 1965, namely:

1. (1) These rules may be called the Coffee Board General Provident Fund (Amendment) Rules, 1982.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Coffee Board General Provident Fund Rules, 1965. in rule 8, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Accounts Officer in writing his option to subscribe for the said month."

(File No. 1/17/82-Plant (B))
B. M. S. NEGI, Under Secy.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

रहरूरने का आवेश

नई विल्ली, 11 मधम्बर, 1982

का० आ० 4001----सर्वधी बैंक प्राप्त बड़ोदा, 10/12, बस्बई समाचार मार्ग, फोर्ट, सम्बद्द को (1) वन मिनोल्टा प्लेन पेपर कापियर मांडल, ई-पी-310 (2) बिजली के टाइपराइटर मॉडल 'हर्मेन' 808 दोनों फालतू पूजों भीर उपभोग्य सामग्री के साथ भागत के लिए 38,500/ रुपए सागत-बीमा-भाषा महय का एक श्रायान लाइसेंस रां॰ बी/ए/1091356. दिनांक 16.3.82 प्रदान किया गया था जो कि जारी होने की सारीसा से 1 ? मास के लिए वैध या। प्रव पार्टी ने उपर्युक्त प्रायान लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-गुल्क प्रयोजन भीर मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां प्रदान करने के लिए इस भाषार पर भावेदन किया है कि मूल प्रतियां उनसे खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। पार्टी ने श्रायान व्यापार नियत्रण नियमो के अनुसार भावश्यक शपय-पत्न/घोषणा भी भेजी है जिसके भन्मार उपयुक्त आयान लाइसेंस किसी भी सीम-गुल्क कार्यालय के पास पर्जाकृत नहीं कराया गया था भीर उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया या ग्रीर लाइसेंस मे भव 38,500 रुपए की राणि शेष है। शपय-पत्न घोषणा में यह भी कहा गया है कि यदि भाषान लाइसेम की उक्त सीमा-शुल्क प्रयोजन भीर मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां बाद में मिल गई या प्राप्त हूं। गई तो मे जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा दी जाएंगी । मैं संत्रूट हुं कि भाषात लाइसेंस की मूल सीमा-मुख्क प्रयोजन और भूद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई/मस्थानस्य हो गई हैं भीर निदेश देता है कि ब्रायेदक की मायान लाइसेंस की मनुलिपि सीमा-गुरूक प्रयोजन ग्रीर मुद्रा-विनिधय

नियंत्रण प्रतिया जारी की जानी चाहिएँ भ्रायास लाइसेंस की मूल सीमा-गुल्क प्रयोजन श्रीर मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिया एतदहारा, रह की जाती है।

> [मिसिल स॰ 12/183/81-82/एम एल एस/573] शकर चन्द, उप-मुख्य नियंत्रक, भ्रायात-निर्यां स कृते मुख्य नियन्नक, भ्रायात-निर्यां त

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

New Delhi, the 11th November, 1982

CANCELLATION ORDER

S.O. 4001.—M/s, Bank of Baroda, 10/12, Bombay Samachar Marg, Bombay were granted an import licence No. G/A/1091356 dated 16-3-82 for a C.I.F. value of Rs. 38,500 for import of (1) One Minolta Plan Paper Copier Model EP-310; (ii) Electric Typewriter Model 'Hertnes' 808, both with spares and consumables valid for twelve months from the date of issue. Now the party have applied for grant of Duplicate Customs Purpose and Exchange Control copies for the aforesaid import licence on the ground that the original one have been lost/misplaced by them. The party have furnished necessary affidavit/declaration as per I.T.C. Rules according to which the aforesaid import licence was not registered with any Customs House and was not utilised at all and the balance against the licence is Rs. 38,500. It has also been incorporated in the affidavit/declaration that if the said Customs purpose and Exchange Control copies of the import licence are traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. I am satisfied that the original Customs purpose and Exchange control copies of the import licence have been lost/misplaced and direct that Duplicate Customs Purpose and Exchange control copies of the import licence should be issued to the applicant. The original Customs Purpose and Exchange Control copies of the import licence where the applicant. The original Customs Purpose and Exchange Control copies of the import licence where the applicant.

[File No. 12/183/81-82|MLS|572]
SHANKAR CHAND, Dy. Chief Controller of
Imports and Exports
for Chief Contfoller of Imports and Exports

रामीण विकास संज्ञालय

नई दिल्ली, 12 नवस्बर, 1982

का आ 4002 -- के खीं स्मान्त रहा उपज श्रेणीकरण श्रीर (चिन्हाकन) प्रधिनियम, 1937 (1937 क. 1) की घारा 3 द्वारा प्रदक्त माक्त्यों का प्रयोग करने हुए अनिया श्रेणीकरण श्रीर चिन्हाकन नियम, 1964 का श्रीर संगोधन करना चाहती है। जैसा कि उकन धारा में अपिक्षत है, प्रस्तावित संगोधनों का निम्नितिखत प्रारूप उन मभी व्यक्तियों की जानकारों के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उकन प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियों जिसमें श्रीस्त्वना प्रकाशित की जाती है, जनता की उपलब्ध करा दी जाती है, 45 दिन के प्रचात विचार किया जोएंगा।

इस प्रकार विनिविष्ट भ्रवधि की समाप्ति के पूर्व निवसों के उक्त प्रारूप की बाबन जो भी भ्राक्षिप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारुप मियम

1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम घनिया श्रेगीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1982 है। 2 घनिया श्रेणीकरण श्रीर जिल्हांकन नियम, 1964 की घनुसूची

- (क) सारणी के स्तम्भ 4 के शीर्षक में नुकसान शब्द का लोप
 (कया जाएगा ।
- (ख) स्त्रम्म 5 मे 1 0, 2.0, 3.0 प्रको के स्थान पर अपक 2.0, 4.0, 6 0 प्रौर 6 0 प्रक रखे जायेंगे।
- (ग) पाद टिप्पणी 3 के स्थान पर निम्निश्वत पाद टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्—

3 काले किए हुए बीज के फल या विमन्त फल होते हैं जो ताह्यक रूप से नवासिटी पर प्रभाव बालते हुए, काले किए जाने हैं।

- टिप्पण (1) मूल गिम भारत के राजपन्न में काञ्मा० 2391, नारीक्ष 11-7-64 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
 - (2) पहला संलोधन भारत के र.जपस में कं.०आ.० 523, तारीख 10-2-68 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।
 - (3) दूसरा संगोधन भारत के राजपत्न में काञ्मा० 2842 सारीख 24-7-71 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

सिं० एफ० 10-4/82-ए एम०] डी०मेहना, निवेशक (विषणन)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 4002.—The following draft rules, further to amend the Coriander Grading and Marking Rules, 1964, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), are hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that said draft rules will be taken into consideration after forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions received from any persons with respect to the said draft rules, before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. These rules may be called the Coriander Grading and Marking (Amendment) Rules, 1982.
- 2. In the Cotidander Grading and Marking Rules, 1964 in Schedule II,
 - (a in the heading of column 4 of the table, the word "Damaged" shall be deleted;
 - (b) in column 5 for the figures '1.0", '2.0', '3.0' and '3.0' the figures '2.0', '4.0', '6.0' and '6.0' shall respectively be substituted;
 - (c) for the foot note 3 the following foot note shall be substituted, namely :--
 - "3. 'Elackened Seeds' are those fruits or split fruits which are blackened, materially affecting the quality."
- NOTE.—(1) Principle rules published vide S. O. 2391 of G.O.I. dated 11/7/64.
 - (2) 1st amendment published vide S. O. 523 of G.O.I. dated 10/2/68.

(3) 2nd amendment published vide S. O. 2842 dated 24/7/71.

[No. F 10-4/82-AM]
D. MEHTA, Director (M)
Dated.—11-11-82.

संचार मंत्रालय

(बाक सार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 नवस्बर, 1982

का ब्याव 4003. - स्थायी ब्रादेश संख्या 627, विमांक 9 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के ब्रनुसार डाफ-नार महानिवेशक वे पालमपुष्ठ/हांडयाला गुरु टेलीफीन केन्द्र मे दिनाक 16-12-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निरुच्य किया है।

[संख्यः 5-5/32-पी०एस०की०] धार०सी० घटाग्या, सहायकानदेशक (पी०एच०की००)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 17th November, 1982

SO. 4003.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-12-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Palampur/Jandiaia Guru Telephone Exchanges N. W. Circle.

[No. 5.5/82-PHB]

R. C. KATARIA, Assistant Director General (PHB)

अनुभवण संघटन

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1982

- का. था. 4004: -- केन्द्रीय सरकार, राज भाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, अनुश्रवण संघटन, संबार मंत्रालय के निम्नलिखित अनुश्रवण केन्द्रों को, जिनके कर्मचारी- वृन्द्र ने हिन्दी का कार्यशाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिमूचित करती है.--
 - 1. अन्थ्रवण केन्द्र, त्रिवेन्द्रम,
 - 2. अनुश्रवण केन्द्र, मंगलौर,
 - अगुश्रवण केन्द्र, नागपर ।

[संख्या 9-मौत/(10)/82] र. ग. देंअधर, निदेशक, (बेतार अनुश्रवण)

(MONITORING ORGANISATION)

New Delhi, 6th November 1982

S.O. 4004.—In pursuance of sub-rule 4 of the Official Languages (Use for official purpose of the union) Rule 1976 the Central Government pereby notify following Stations of

क्षेत्रफल

Monitoring Organisation of the Ministry of Communications, the staff whereof, have acquired working knowledge of Hindi.
1.Monitoring station Nagpur.
2. Monitoring station, Trivendrum.

- 3. Monitoring station, Manglore.

[No. 9-Mon (10)/82] R. G. DEODHAR, Director

(Wireless Mon.)

कर्जा मंत्रालय

(वैद्रोलियम विमान)

नई दिल्ली, 9 नवस्बर, 1982

शार्श्वका व 4005 च्यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहिल में यह कार्यश्यक है कि महरू दूराज्य में बंबई से पुणे तक पैट्रोलियम पदाचौ के परिवहन के लिये पाईप लाईन हिन्युस्पान पैट्रोलियम कारपोरेणन द्वारा विछाई जानी चाहिये।

भीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को विद्वाने के प्रयोजन के लिये एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित सूमि में उपयोग का अधिकार अजिन करना भावश्यक है।

भतः भव पैट्रोलियम भीर खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजेन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आयाय एतदब्रारा भोषित किया है।

बद्यार्ते कि उक्त भूमि में हिसबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिये चाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, हिन्दूस्थान पैटोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई पूर्ण पाईप लॉइन्स प्रोजेक्ट फयुझेल रिफायनरीज कॉरिडार रोड बम्बई को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

भीर ऐसा चाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह जाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विशेष व्यवस्मियी की मार्फत।

अनुसूचि पाईप लॉईन जांभूलमे कान्हे तक

नालुक: मावल, जिला पुणे,

गां व	क् सरा मम्बर	हिस्सा सम्बर	भोजनार	r
		गम्भाग	हैक्टर	ऐयर
 সামু ল	239 का भाग		00	60
11	240 ,,		0.0	60
1,	168 ,,)			
,,	169 ,,			
n	170 ,,			
1)	171 ,, }		0.0	19
1,	172 ,,	-	-	
,,	173 ,,			
1)	174			
·,	175 ,,			

पा व	वसरा नंकार	प्रिस्मा		··
		नम्बर	हेक्टर	ऐयर
जांमूल	256 का भाग) 268 ,, }		- 00	23
11	200 ,,		- 00	23
7.1	252 ,,			
,, ,,	253 ,, { 254 ,, }		0.0	12
17	255 ,,			
,,	241 ,			
v	ر 251 ا		0.0	20
r	261 ,,			
)†]†	262 ,, 274 ,,			
17	275 ,,		0.0	25
D	277 ,,)			
7)	291 ,,			
))))	292 ,, 296 ,,			
,1	297 ,,		0.0	-4
,	298 ,, } 299 ,, }	- 	00	•
,' ,'	- 300 ,,	→→		
,,	301 ,, 302 ,,			
)† 1r	303 "		•	
11	293 ,,)			
11	294 ,, }	<i>-</i> -	00	09
11	295 ,,)			
D	296 ,,] 297 ,,]			
n n	298 ,,	-4-		
n	299 ,, }		00	39
11	304 ,,] 307 ,,]			
) r	332 की भा ग) 		
,,	(1 ए 1(~)	j		
11	332 ,,(1ए2) 332(1 ए 3)		_	
1)	333 "	}	00	03
17	334 <i>n</i> 335 <i>n</i>			
n n	336 ,,	j		
***	342 ,, }			
11	351 ,, 352 ,,			
n n	353 ,, }		00	73
n	354 " J			
<u>"</u>	361 ,,]			
कान्हें "	224 ,, }		00	05
n	229 ,,]			
n	327 ,, \		00	02
n 	330 ,, 334 ,,		00	29
n	326 ,,]		00	14
n	53 ,,)			

1001 GI/82-2

			क्षेत्रफल		
博 , ,	स्वसमा नम्बर	हिस्सा न म्ब र	हेक्टर	 ऐवर	
—— —— का ^{क्} ट्टो	54 .,)				
n. 4.	55 ,,		0.0	41	
,,	56 ,,				
)1	257 ,, 258 ,,				
11 11	259 ,,	 			
17	260 ,, >				
"	261 ,, 262 ,,				
r))	263 ,,				
,,	264 ,,				
"	265 ,,				
"	266 " ၂				
11	267 का भाग 🗋 268 ,, ।	-+			
1) 11	268 ,, 269 ,, {				
"	270 ,,				
71	282 ")				
29	283 ,, }		0.0	13	
n	284/2 ,,]				
11	284 .,		00	0.4	
11	288 "	_	0.0	29	
"	292 "	_	-00	32	
n	293 ,,		00	22	
71 1)	312 " }		00	27	
"	311 "		00	43	
n	316 ,		00	08	
"	315 "		00	37	
,,	5 1 2 / 1, 2 ,,		00	19	
n	521 ,, }				
"	522 ,, { 523 ,, {		00	17	
n n	523 ,, 524 ,,		0.5	.,	
"	840 ,,		00	16	
11	536 ,,]				
ti	537 ,,				
"	538 ,, >		00	17	
11	539 ,, } 541 ,, }			4	
†7 17	532 का भाग 532 का भाग		00	10	
1)	535 ,,		00	01	
27	533 ,,	best-	00	43	
12	460 ,,		00	5	
,,	452 ,,		0.0		
,	453 ,,				
7)	494 ,,		00	0.4	
n n	456 ,,		= =		
n	457 ,,				
n	458 ,,]				
Jt.	449 ,,		00	34	

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 4005.—Whereas it appears to Central Government that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra though Pipe-line and that said Pipe-line is to be laid through the agency of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay.

And whereas it appears to Central Government that for laying pipe-line it is necessary to acquire the Right of User in respect of the lands appended to herewith in schedule.

Now therefore in exercise of the powers vested in them by virtue of Section 3 (i) of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) AO 1962 (50 of 1962) Central Government notify intention to sequire the Right of user in the lands referred to above.

Any person having his interest in the lands referred to above having any objection for laying the Pipe-line through above mentioned lands may prefer an objection within 21 days of the publication of this notification before the competent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bombay Pune Pipeline Project, Puels Refinery, Corridor Road, Bombay-74.

All persons having any objection may also state whether they want to be heard in person either himself or through any lawyer appointed by him.

SCHUEDULE

PIPELINE FROM: VILLAGE JAMBHUL TO KANHE

Taluka : Mawal, District : Pune (Maharashtra)

			AREA_		
Viflage	Gutt No.	Hissa No.	Н-	R	
Jambhul	239 PART	_	00	60	
1,	240 ,,		00	60	
,,	168 ,,	_			
	1697 ,,	_			
***	170	_	00	19	
**	171 [],				
**	172 } ,,	_			
11	173 [,,	_			
"	174] ,, 175] ,,				
**					
77	256] ,.	_	00	23	
**	268) ,,	_			
,,	252) "				
17	253 (,,		00	12	
34	254 } 255 }				
**	_				
**	241]	-	00	20	
19	$\overline{251}$				
"	261) "				
11	262	~	00	2.0	
1)	274 } ;; 275 ;;	_	00	25	
11	477 l	_			
"					
1)	291]	_			
"	292 296				
**	202	_	00	34	
77	299 ;;	_		•	
**	300 [,,				
71	301] ,,,				
1)	302				
••	303) ,,				
**	293 PAR	т —	00	00	
79 6 1	294 } ,,	_	00	09	
11	295] ,,				

Village	Gutt No.	Hissa	AR	EA
			н	R
Kanhe	296) "			
;; ;;	297 ,,		00	39
"	290 [,,	_		
"	304] 307] ,,	_		
,,	332γ (1 A	2 ,, Par	:)	
3)	332 i (1 A	3 Parı)	
"	332 ,, (1 333 ,,	A 3 Pa	rt) 00	03
13	334 >	_	00	0.5
<i>t</i>)	335 ,,	-		
"	442) ,,			
"	351) ,,			
1)	354 (353 }		0	73
"	354	-	v	7.5
	,, ز 361	-		
))))	224) "			
"	228 \ 229 (0	05
	3 27 J ,,		00	02
"	330 334) ,,	=	00	29
51	326 ,,		00	14
**	53		_	
,,	54			
)>	55 ,,			
•) -	56 ,,			
"	257 ,,	_		
	258 PART			
,,	259 260	_		
,, ,,	261]	_		
,,	262 ,,			
) ? •	263 } ,, 264 ,,	_	00	41
1	265]	_		
, ,	266 ,, 267 ,,	111111		
,	2687			
15	269₹ ;;	_		
•	270) ,,			
,	282 283 } ;;	_	00	13
,	284/2∫ ','		•	
•	284 ,,		00	04
•	288 ,,	_	00	29
•	292 ,,	_	00	32
•	293 ,	_	00	22
•	3127	_	00	27
•	314) ,,	_		
	311 ,,	_	00	43
ı	316 ,,	_	00	08
	316 ,,		00	37
	512/2]		00	19
	512/1] ,,	-		
	$\begin{bmatrix} 521 \\ 522 \end{bmatrix} ,$	_	00	17
	523 [_		
	524] ,,	-		
	540 ,,	A	00	16
.•	536) PART			
nhe	437 I			
nho	537 ,, 538 ≻		00	17
nhe	537 ", 538 } ", 539 ",		00	17
nho	537 " 538 } "	_	00 00	17 10

Village	llage Gutt No.		AREA	
		No.	H.	R
,,	535 ,,		00	01
>>	533 ,,		00	43
19	460 ,,	_	00	45
,,	452) ,, 453 ,, 454 ' ,, 455 } ,, 456 ,, 457 ,,			
**	453 { ,,	_		
13 1	454			
ນ ້	455 } ,,	-	00-	04
,,	456 ,,	_`		
,,	457 [,,	_		
,,	458 } ,,	-		
	449 ,,	_	0.1	34

[No. 12016/49/82-Prod.]

का ब्लाव 4008. ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह भाषश्यक है कि गुजरात राज्य में कानावाड़ा-2 से बांगड़ा-1 तक पैट्रीलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस भागोग द्वारा विछाई जानी चाहिए।

भीर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को विद्याने के प्रयोजन के लिए एतद्वावक धनुसूची में बर्णित भूमि में उपयोग का स्रविकार श्राजित करना भावश्यक है।

मतः घव पैट्रोलियम और खनिज फाइपलाइन (भूमि में उपयोग कें प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रिक्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना भागम एत्युद्वारा चोषित किया है।

बगर्ते कि उन्त भूमि में हिसबा कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन विछाने के लिए बाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तैल तथा प्राकृतिक गैस ब्रायोग, निर्माण बीर देखमाल प्रभाग, मकरपुरा रीड, वडीवरा-9 की इस ब्रियाचना की तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा।

भौर ऐसा झाओप करने वाला हर व्यक्ति विकिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगाकि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत ही या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कानाबाडा 2 से भागड़ा-1 तक पाइप लाइन विछाने की लिए

राज्य - गुजरात	जिलाः चेडा		तालुका	: संदान
गाव	सर्वे नं ०	१ न्देयर	एमारई	सेन्टीअर
कानावादा	91/1	0	15	20
		₹ 0 1201	6/50/8	2-मोड०]

S.O. 4006.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kanawada 2 to Changda-1 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may. within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE PILELINE FROM KANAWADA-2 TO CHANGADA-

State: Gujarat	District:	t: Kaira Taluka: Cam		: Cambay
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
KANAWADA	91/1	10	15	20

[No. 12016/50/82-Prod.]

का० आ० 4007. -- यतः केम्ब्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में कि यह भावस्थक है गुजरात राज्य में एस०एन०ए०जै० पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा से एस०एन ०ए०झी० अक्रिक गैस आयोग द्वारा विकाई आनी चाहिए।

भीर यतः यह प्रतीतः होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्यायक अनुसूची में उच्चीय की वर्णित भूमि में अधिकार की र्म्याजस उपयोग का करना मानग्यक है।

अतः अस पैट्रोलियम भीर खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग को भविकार का मर्जन) भविनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें अपयोग का भक्षिकार मजित करने का अपना बाबाय प्रतब्द्वारा घोषित किया है।

बत्तर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिकाने के भिए प्राक्षेप सवाम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस मायोग, निर्माण भीर देखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बदोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

ग्रीत ऐसा ग्राक्षेप करने वाला हर स्थक्ति विनिर्विष्टतः यह भी घ्यान करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

. अनुसूची

एस०एन०ए०जे० से एस० एन० ए० घो०तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुज रात	जिला और तालुका: मेहसाणा					
गांव	ब्लाक नं•	हैक्टेयर प	(मारई	सेन्डीघर		
कसलपुरा	674	0	06	50		
_	672	0	12	50∸		
	668	0	04	80		
	669	0.	13	80		
	619	0-	03	10		
						

[सं॰ 12016/51/82-मोह]

एल व्यापन गीयल, निवेशक

S.O. 4007. Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAJ to SNAJ in Gujarat state pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com-

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any persons interested in the said land, may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hearded in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From S. N. A. J. to S. N. A. O.

State: Gujarat District : & Taluka : Mchsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
KASALPURA		0	06	50
	672	0	12	50
	668	0	04	80
	669	0	13	80
	619	0	03	10

[No. 12016/51/82-Prod.]

L. M. GOYAL, Director

क्रिका तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

मई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1982

ना॰भा॰ 4008. ---सार्वजनिक परिसर (ग्रनधिकृत दखल कारों की निकालने) मधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतपुद्वारा अलीगढ़ मुस्सिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते निम्तलिखित सारणी के कालम (1) में उल्लिखित व्यक्ति को भारत सरकार के राजपन्नित प्रधिकारी के दर्जे के समकक्ष इस प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए एतदुवारा सम्पदा प्रधिकारी नियुक्त करती है भीर जो उक्त सारणी के कालम 2 की तदमुख्पी प्रविष्टि में निर्विष्ट सार्वजनिक स्थानों के सम्बन्ध में उसकी सम्बन्धित प्रशासनिक नियंक्षण की स्थानीय सीमाधों के भीतर इस धर्धिनियम के श्रंतर्गत सम्पदा श्रधिकारी के श्रधिकारों का उपयोग करेंगे श्रीर उनका वार्य निष्पादन करेंगे ।

सार्जी		
नाम	सार्वजनिक स्थानों भौर प्रशासनिक नियंत्रण की स्थानीय सीमाएं	
(1)	(2)	
प्रो० प्रब्दुल मजीद सिद्दीकी रसायन गास्त्र प्रोफेसर प्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रलीगट	म्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मौर उससे सम्बन्धित म्रलीगढ़ जिले की क्षेत्रीय सीमाम्री के भीतर स्थान	

[सं॰ फा॰ 382/82/डेस्क(यू)] धासा सिंह, डेस्क प्रधिकारी

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE (Department of Education)

New Delhi, the 16th November, 1982

S. O. 4008.—In excercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the person mentioned in clumn (1) of the Table below, being a professor of the Aligarh Muslim University, Aligarh, equivalent to the rank of a gazetted officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises si ecified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Name	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Professor Abdul Majid Siddiqi Professor in Chemistry, Ali- garh Muslim University, Aligarh.	

[No. F. 3-82/82/Desk (U)] ASSA SINGH, Desk Officer

अम ग्रोरप्नर्वास मंत्रालय

(अम विभाग)

आदेश

नई दिस्सी, 14 ग्रन्सुबर, 1982

का०आ० 4009.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध धनुसूची में विनिर्विष्ट विषय के बारे में विशाखापटनम पत्तन क्यास के प्रबन्धर्तंत्र से सम्बद्ध एक ग्रीधीगिक विवाद नियोजकों ग्रीर उनके कर्मकारी के बीच विधमान है:

भीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

भत. केन्द्रीय सरकार, ग्रौधीगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क ग्रौर धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक ग्रौधीगिक ग्रिधिकरण गठिस करती है जिसके पीठासीन प्रधिकारी श्री एस॰वी रामना रेडडी होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा ग्रीर उनत विवाद की उक्त प्रधिकरण को व्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

चया एम०बी० अनुभाग के श्रेणी 11 के ड्राइवरों को जूते वेने से इंकार करने की विभाषापटनम पत्तन न्यास के प्रबंधतंत्र की कार्रवाई न्यायोजित है? यदि नहीं तोसंबधित कर्मकार किस अनुसीण के हकदार है?

> [सं॰ एल॰-34011(10)/8?-डी॰ iv(ए)] टी॰सी॰ सीतारामन, डेस्क ग्रधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION >

(Department of Labour)

ORDER

New Delhi, the 14th October, 1982

S.O. 4009.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri S. V. Ramana Reddy shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Visakhapatnam Port Trust in refusing to supply shoes to Grade-II Drivers of M. V. Section is justified? If not, to what relief are the concerned workmen antitled?"

> [No. L-34011(10)/82-D. IV(A)] T. B. SITARAMAN, Desk Officer

आदेश

नई विल्ली 20 अक्तूबर, 1982

का०आ० 4010. ---केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबश्च धनुसूची में विनिर्विष्ट विषयों के बारे में दक्षिण रेल प्रणासन के प्रवंधतंत्र से सम्बद्ध एक घौद्योगिक विवाद नियोजकों धौर उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है:

मौर केम्ब्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निद्रक्षित करना वाछनीय समझती है;

भतः, केन्द्रीय सरकार, श्रौद्योगिक विवाद मिश्वितियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क श्रीर धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदेश गितियों का प्रयोग करते हुए, एक भौद्योगक अधिकरण गिंठत करती है, जिसके पीठामीन अधिकारी श्री ट्री०भरूल राज होगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उसत विवाद को उक्त अधिकरण को स्यायनिर्णयन ो लिए निर्देशित करती है।

अन् सृक्षी

'रेल बोर्ड के पत्न संख्या पी०जी०-72/मार०एल०टी०/69-3, ता० 12-6-74 में सर्ताविष्ट भादेशों को ध्यान में रहते हुए, क्या विक्षण रेल प्रशासन उन पुन नियुक्त किए भए ध्यमिको को, जिनकी पहले छुटनी की गई शी भीर जो भ्रपनी छंटनी के समय मजदूरी की स्केल वरें प्राप्त कर रहे थे, मजदूरी जी स्केल दरों का संवाय न करना न्यायोजित ठहराया जा सकता है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस भानुतोष के हकवार है?

[एल-41011(6)82-डी-II-सी] एस०एस० परागर, डेस्क मधिकारी

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1982

S.O. 4010.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Southern Railway Administration and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule

in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arul Raj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"The view of the Railway Board's orders contained in letter No. PG-72/RLT/69-3 dated 12-6-1974 whether the Southern Railway Administration is justified in not paying the scale rate of wages to re-engaged workers who were retrenched earlier and were in receipt of the scale rate of wages at the time of their retrenchment? If not, to what relief are the workmen entitled?"

[No. L-41011(6)/82-D. II (B)]

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4011.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Air force Halleswar, Post Office Tezpur, District Darrang, Assam, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA,

Reference No. 30 of 1982

PARTIES:

Employers in relation to the management of Airforce, Halleswar, P. O. Tezpur, Distt. Darrang, Assam.

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh.—Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers.—Absent On behalf of Workmen,—Absent.

STATE: ASSAM

AWARD

By Order No. L-14012/3/81-D. II(B) dated 23 August 1982 the Government of India, Ministry of Labour sent to this Tribunal the following dispute for adjudication:

"Whether the action of Garrison Engineer, Airforce, M.E.S. Tezpur in discharging Shri Kamal Chandra Keot, Valveman from service w.e.f. 24-8-72 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. On receipt of the Reference notices were issued to parties fixing 2-11-1982 as first hearing date with direction to file their respective documents and written statements, if any. But to-day when the case was called out nobody appeared. The Tribunal received a letter from the office of Garrison Engineer Airforce, Tezpur, P. O. Halleswar intimating that the concerned workman Sri Kamal Chandra Keot,

Valveman had been reinstated and he reported for duty on 14th July, 1982 (Forenoon). In view of above there seems to exist no dispute in the matter.

I, therefore, pass a 'No Dispute' Award in the case. Dated, Calcutta, The 2nd November, 1982.

Sd /-

M. P. SINGH, Presiding Office, [No. L-14012(3)/81-D. II (B)]

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4012.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Security Paper Mills, Hoshangabad, and their workmen, which was received by the Central Government on 9-11-82. 9-11-82.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (REGD.) PRESID-ING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R) (45) of 1981

PARTIES:

Employers in relation to the management of Security Paper Mills, Hoshangabad and their workmen represented through the S.P.M. Staff Union, C/o Security Paper Mills, Hoshangabad (M.P.).

APPEARANCES:

For Workmen.—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Management.-Shri K. K. Adhikari, Advocate.

INDUSTRY: Paper Mills DISTRICT: Hosbangabad (M.P.)

AWARD

Hoshangabad, the 29th October, 1982

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour vide Notification No. L-42011(12)/80-D. II (B) dated 20th November, 1981, for adjudication of the following dispute by this Tribunal:—

"Whether the action of the management of Security Paper Mills, Hosganbabad in denying overtime and night duty allowances to its staff members drawing basic pay of Rs. 751 and above is legal and justified when their counterparts in Indian Security Press, Nasik are entitled to such allowances? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

2. Facts which are not in dispute in this case are as under:-

Workmen in this case are the employees of the Security Paper Mills, Hoshangabad, hereinafter referred to as the Mills. The Mills employ different categories of workmen some of whom are getting Rs. 750 p.m. as wages. Neither any Overtime Allowance nor any Night Duty Allowance is paid by the Mills management to such workmen who are drawing their basic pay of more than Rs. 750 p.m. Workmen claim that since in the Indian Security Press at Nasik such allowances are paid to such members of the staff whose basic pay is more than Rs. 750 p.m. the Mills management is not justified in denying such allowances to them also. As the claim made by the workmen of the Mills was not conceded to by the Mills management an industrial dispute was raised which has resulted in the present reference to this Tribunal.

3. The case of the workmen is that in the Indian Security Press, Nasik, which is also an Undertaking of the Government of India as also in other Government Undertakings

like Ordnance Factory etc. Overtime Allowance and Night Duty Allowances are paid to those employees whose basic pay is more than Rs. 750; that those workmen who are receiving these two allowances in the Indian Security Press, Nasik and other Undertakings of the Government of India are employees of the came Government of which these workmen are the employees; that in the other establishment of Security Press Nasik there is no ceiling of basic pay for entitlement of these two allowances; that in the Ordnance Factory Khamaria, Jabalpur, Ordance Factory Itarsi, Government Mint_s at Calcutta, Hyderabad and Bombay, Central Government pays these two allowances to the workmen even though their basic pay is more than Rs. 750; that duty hours of the employees are fixed at 8 hours per duty hours of the employees are fixed at 8 hours per day and taking duties from the workmen beyond this duty period of 8 hours without payment of Overtime Allowance is not legal; that the Government cannot discriminate the case of one employee with the case of the other employees in the other establishment; that Overtime & Night duties involve extra physical and mental burden on the workmen and that denial of Overtime and Night Duty Allawances to the workmen by the Government and grant the same allowances to the similar workmen working in similar undertakings is a clear discrimination in law by the Government of India.

- 4. On behalf of the management, it is contended that members of the Security Papers Mills Staff Union (at whose instance the present reference ans been made) are not workers defined under the Factories Act, 1948; that overtime allowance of the workers who are covered under the Factories Act is regulated under Sec. 59 of the Factories Act; that these workmen are non-industrial workmen in the Mills; that the question of overtime allowance of workers of the Mills except those covered under Sec. 59 of the Factories Act is regulated by the Government of India Circulers referred to in Annexures A to E; that in accordance with these circulars overtime allowance is not payable to those employees who have been drawing basic pay Rs. 750 and above; that in accordance with the Ministry of Finance letters (Annexures H to Annexure I) the industrial and non-industrial and payable to Annexure I) the industrial and non-industrial and payable to Annexure I) the industrial and non-industrial and payable to the industrial and payable to those calculates the payable to those employees when the payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees who have been drawing basic payable to those employees the payable to those employees the payable to those employees and the payable to those employees the payable to those employees and the payable to those employees the payable to those employees the payable to the payable t trial employees drawing a basic salary exceeding Rs. 750 are not eligible for Night Shift Allowance; that these circulars are applicable to al departmental undertakings of the Government of India; that the terms and conditions with regard to Overtime and Night Shift Allowances which are applicable to the members of the Staff of the Security Press, Nasik, cannot be made applicable to the non-industrial employees of the Mills; that the Government of India have a number of industrial undertakings and unless the dispute referred to for adjudication is in respect of all the Industrial Undertaking; the employees of the Mills cannot choose one undertaking only for determination of the question of Overtime and Night Shift Allowances; that the Government have the absolute right to determine the terms and conditions of service of the employees of a particular undertaking; that Overtime Allowance and Night Shift Allowance is paid to the employees of the Indian Security Press Nasik by two different orders of the Government of India (These orders are referred to in Para 11 of the statement); that the Government are justified in regulating, fixing and prescribing different scales of pay and other allowances for different industrial undertakings; that in the Security Paper Mills the employees are getting production incentive allowance which is not paid to the employees of the Security Press at Nasik and that in the Security Press Nasik and Security Paper Mills at Hoshangabad the working hours are different.
 - 5. Rejoinder was filed only by the workmen and not by the Mills. In this rejoinder the workmen have reiterated the allegations of discrimination allegedly being made by the Government as also for their entitlement to the Overtime and Night Shift Allowances at par with the employees of the Security Press at Nasik.
 - 6. On these pleadings of the parties, the following issues were framed:

ISSUES

1(a) Whether the workmen of the Security Paner Mills Hoshangabed are entitled to claim Overtime Allow-

- ance and Night Shift Allowance as claimed in this case?
- (b) If so, from what date and at what rates?
- 2. Relief.
- 7. My finding on the aforesaid issues are as under :-

Issue No. 1(a).—That the workmen of the Seucrity Paper Mills Ltd. drawing pay of Rs. 751 or more are entitled to Overtime and Night Shift Allowance at the same rate at which the same is being to the similar employees of the Security Press at Nasik.

Issue No. 1(b) & (2).—As per order passed below, Reasons for the above findings:

- 8. Issue No. 1(a).—In this case no oral evidence has been given by either party. Only the management of the Mills has filed certain Government Circulars/Orders etc. in support of its contentions. Accordingly in the absence of any oral evidence the issues referred to above have to be decided on the basis of the pleadings of the parties and the documents filed by the management.
- 9. Ex. M/10 is the first document in order of time dated 10.8-1927 from the Finance Department, Government of India, addressed to the Master, Security Printing, India which gives him power to employ overtime labour to meet the work. It also specifies the manner in which the overtime is to be paid. Ex. M/11 is the next order of the Finance Department, Government of India, dated 6-1-1942 which allows 25 per cent more in addition to normal days pay as Night Shift Allowance. The next order of the Government in order of time is Ex. M/1 dated 8-3-1968 by which overtime allowance was allowed to non-industrial staff of the Mills for work done in excess of 48 hours on the terms and conditions stated therein. Ex. M/7 is the next document in order of time dated 10-2-1970. By this order the Finance Ministry allowed Night Duty Allowance to non-industrial employees of the Mills drawing pay upto Rs. 470 Ex. M/2 is the next document dated 18-5-1972 by which calculation of the rate of overtime allowance was fixed. By Ex. M/3 dated 13-10-1972 the period of work for entitlement of over-time and night shift allowances to workmen drawing basic pay of Rs. 500/- was regulated. Ex. M/4 dated 1-5-1974 is the next order of the Finance Ministry by which the ceiling of Rs. 500/- was raised to Rs. 750/-. To the same effect is order Ex. M/5 dated 6-1-75. The last order is dated 6-6-1980 Ex. M/6. By this order the General Manager of the Mills was informed by the Ministry of Labour that the limit of Rs. 750/- has been fixed on the recommendation of the Third Pay Commission and is applicable to all Industrial undertakings of the Government. It was further stated in this letter dated 6-6-1980 that under Sec. 64(1) of he Factories Act payment of overtime allowance to em drawing pay Rs. 750/- or more per month is barred. to employees
- 10. From the aforesaid documentary evidence it would therefore be clear that sometime in the beginning overtime/night duty allowance was payable but subsequently the ceiling was fixed at Rs. 470 Rs. 500 and lastly at Rs. 750.
- 11. Section 59 of the Factorics Act referred to in the statement of demand provides that where a worker works in a factory for more than nine hours in any day or more than forty-eight hours in any week, he shall be entitled to overtime wages at the date of twice his ordinary rate of wages. Sub-section (1) of Sec. 64 referred to in Ex. M/6 dated 6-6-1980, with is the last order of the Government, Provides for making rules to define persons who holds position of Supervision or management or who are employed in confidential position in a factory. No document has been produced before this Tribunal about the making of such rules or definition of persons holding the position of supervision or management employed as a confidential position in the factory. In the light of the aforesaid documentary evidence given by the management only, the only question that arises for consideration is as to whether the non-payment of overtime and night shift duty allowance of employees getting Rs. 750/or more can be said to be justified only on the basis of the Government Order?

- 12. The grievance of the workmen that their counter-parts in the Security Press at Nasik are being paid these two allowances and the same are being denied to them.
- 13. In para 11 it is stated by the management that restrictions imposed by the Government Order dated 1-5-1974 (Ex.M/4) for payment of overtime allowance to persons getting Rs. 750 is applicable to all the industrial undertakings of the Government including the Indian Security Press at Nasik. It is, however, admitted in this paragraph that despite the imposition of celling non-industrial employees of the Security Press at Nasik are paid overtime at the single rate in view of an old practice of paying this allowance without putting any limitation by virtue of the Government of India in the Finance Minstry's letter dated 16-8-1927 (Ex.M/10). It is also admitted that night shift allowance is also allowed to the employees of the Security Press in view of the order dated 6-1-1942 (Ex. M/11).
- 14. It would thus be clear that despite the order Ex. M-10 tlated 16-8-1927 and Ex. M/11 dated 6-1-1942 and the subsequent orders passed by the Government of India by which cellings have been fixed the employees of the Security Press are paid overtime and night shift allowances by the Government of India. Government of India is the owner of the Security Press at Nasik and the Security Paper Mills at Hoshangabad. An important question arises is as to whether there can be any discrimination between the two employees of the same employer in the matter of payment of overtime and night shift allowances?
- 15. Though the Government have absolute right to fix different scales of pay and allowances according to categories of employees in different industrial undertakings but there can be no departure from the basic principle of equal pay for equal work which is deducible from the constitutional provisions of the Constitution of India.
- 16. The question whether there can be any such discrimination as is apparent in this case was considered in the case of Randhir Singh Vs. Union of India and others (AIR 1982 SC 879). In that case their Lordships were considering the case of a Driver in the Delhi Police Force whose pay scale was different and lower as compared to the other drivers in the Railway Protection Force and other Departments of the Government. Considering the question as to whether the principle of equal pay for equal work is or is not a fundamental right or an abstract doctrine, it was held by their Lordships as under:—
 - "Construing Articles 14 and 16 in the light of the Preamble and Art. 30(d), we are of the view that the principle Eual pay for Equal work' is deducible from those Articles and may be properly applied to cases of unequal scales of pay based on no classification or irrational classification though those drawing the different scales of pay do identical work under the same employer."

On the facts of that case their Lordships directed the Delhi Administration to fix the scale of pay of the Petitioner at least at par with the scale of pay of the Drivers of the Railway Protection Force which was higher than the scale of pay admissible to the petitioner driver-constable in that case.

- 17. In this case in para 11 referred to above the management admits that the ceiling of Rs. 750 for non-entitlement of night shift and overtime allowances though applicable to the non-industrial employees of the Security Press also but that is being paid because of the two orders of 1927 and 1942 (Ex. M/10 and Ex. 1/11). It is not understood as to why when employees of the same employer i.e. Government of India in this case are being paid overtime and night duty allowances to employees of one industrial undertaking the same should be denied to the employees of the other industrial undertaking of the same employer.
- 18. It may also be observed that there are fixed working hours of the employees in all the industrial undertakings. At some stage employees getting less than Rs. 750 were allowed overtime and night shift allowance but the same is being

denied now. How can an employee in an industrial undertaking be asked to work overtime without payment of overtime allowance. Night shift allowance is paid because an employee is required to work during night hours which are not the normal hours of work. However, on principles of 'equity' and on the principle of 'Equal pay for Equal work' the claim by the workmen in this case appears to be justified. Though it was stated that the conditions of working in the Security Press at Nasik and Security Paper Mills at Hoshangabad are different but there is not an lota of evidence placed before this Tribunal by the management to show as to whether and to what extent the difference lies in the work and method of these two industrial undertakings. If some material has been placed before this Tribunal to justify the discrimination the matter could have been considered in the light of the material so placed, but since that has not been done the only inference is that the has not been done the only interence is that the general conditions of both the industrial undertakings under which the employees getting pay over Rs. 750 is the same. Consequently, there is no justification made out by the management for discrimination in the matter of payment of overtime and night shift allowances.

- 19. Issue No. 1(b) & (2).—As per orders passed below.
- 20. Accordingly for the reasons given above, the following award is given:—

The workmen of the Security Paper Mills Ltd., Hoshangabad who are drawing pay over Rs. 750 are entitled to overtime allowance and night shift allowance at par with such allowances being paid to the similar employees of the Security Press at Nasik. Such allowance shall be paid to these workmen from the date of this award.

In the circumstances of the case, both the parties shall bear their own costs as incurred.

S. R. VYAS, Presiding Officer
[No. L-42011(12)/80-D.Π(B)]
S. S. PRASHER, Desk Officer

आदेश

नई किल्ली, 4 नवस्मर, 1982

का०आ० 4013. किसीय सरकार, शीकौरिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस्त शिक्तयों का प्रयोग करने द्वुए स्यू संकलोर पन्तन और टूटीकोरन पत्न के अध्यक्ष से यह अपेका करनी द्वै कि वह औंचीयिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में विहित सामले के लिए अपने अधीन औंचौरिक स्थापन में एक कार्य समिति गठित करें।

[फा॰ सं॰ एस०-11018(6)/81-की 1(ए)]

ORDER

New Delhi, the 4th November, 1982

S.O. 4013.—In exericse of the powers conferred by subsection (1) of section 3 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby requires the Chairman of New Mangalore Port and Tuticorin Port to constitute a Works Committee in the industrial establishment under him in the manner prescribed in the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957.

[F. No. S-11018(6)/81-D.I(A)]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1982

का०आ० 4014, — केन्द्रीय सरकार, भीकोगिक विवाद अधिनिधम, 1947 (1947 का 14) की भ्रारा 33-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त गिक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भृतपूर्व श्रम, रोजगार भीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम प्रौर रोजगार विभाग) की प्रशिस्चना सै० का०नि० 4650 नारीक 19 दिसम्बर्ग, 1967 का निम्निज्ञत और मंगोधन करती है, प्रयोत

उक्त अधिसूचना से.उप बढ़ सारणी में कम स० 9 और उससे मनियत प्रविध्यों के स्थान पर निस्तिविधन रखा जाएगा श्रथीन ---

- '9(क) कर्ताटक राज्य सरकार गुलबर्गा जिना बदिर जिना रामच्र जिला द्वारा गठित श्रम न्य यालय वन्ल रो जिला बेलगम जिला हुबती उत्तर क्यारा जिला, बीजापुर
- 9 (ख) श्रमन्याय नय बगलार गलबर्गा ग्रीर बेनगाम प्रभागो को छोन्करकर्नाटकराज्य

जिता ग्रीर धारवा जिला।

निरमण मृत्र ग्रामिनन। कंश्यं० 1650 तार्रेख 19-12-67 भारत के राजपंत्र भाग 2 खंड 3 उपखंद (11) तारीख 30-12-67 को पक्तिशित में गई ग्रीम तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा उसका संशोधन किया गया

- (1) ग्राध्यूचना म०का०ग्रा॰ 1175 तारीख 20-3-68 30-3-68 वा
- (11) ग्रिमिसूचना म० का०ग्रा० 668 तारीख 11-2 69 22-2-69 की रजपत्र
- (111) অগ্নিষ্বা শ০ কাত্মাত 1894 বাৰীয়া 9-5-69 17-5-69 কা হাজ্যর
- (IV) ग्रिधिम्बना स० का॰ग्रा॰ 1768 नारीख 30-4-69, 10 5-69 का राजपत
- (v) भ्रधिम्चना म० का०भा० 2796 नारीख 3-771 24-7-71 का राजपत
- (VI) अधिमूचना स० का०मा० 3810 तारीख 23-9-72, 4 11 72 का राजपत्र
- (VII) अधिचना स० का०आ ० 4521 तारीख 26-9-75, 18-10-80 का राजपत्र
- (VIII) ग्रिसियूचन, स० का॰श्रा० 2914 तारीख 13-10-80 25-10-80 का राजपत
- (ix) ग्रिधसूचना स० का० ग्रा॰ 45 नारीख 19-12-81, 2-1-82 का राजपत्र
- (x) म्रिधिसूचनः स० का०म्रा० 1633 तारीख 16-482, 15-82 का राजपत

[संव एस-11020/9/81-3 व प्रई० ए]० एल०के० नारायणन श्रवर मचिव

New Delhi the 22nd November 1982

S. O. 4014 . In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33-C of the Industrial Disputes Act, 1947 (4 of 1947), the Central Government hereby makes the following furth a smendments in the notifier ion of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour, Employment and R habilita ion (Department of Labour and Employment) No. S. O. 4650. died the 19th Docember, 1967, namely

In the Table – nex d to the said Notific tion, for scrial No. 9 and the entries relating thereto the following shall be substitute 1, namely -

"3(1) Labor Cor Hubbi cons- Gulbarga District, Bidar trived by the Sixte Go- Dritt, vernment of Karia ka Raichur District, Bell ry District

Belinum District Ut'ra Karim Di i et Bij pur District und Dl i w d Di tre

9(b) L b itr Court Bingalore Tr Sate of Krit ka extidity Gilbary and Blgaum Divisions

Note Principal Notification ribbt had views O 4650 dited the 19 12-67, Palt II, Sulton 3 Subsection (ii) of Gazitte of India a ted the 30 12-1667 subsequently then by

- (i) Notifity tion, N , S O ± 175 dated 20-3-68. Gazette of 30 3-69.
- (ii) Notification No S.O. 668 dat d 11 2-6 G 7 tte of 22-2-69
- (iii) Not fication No. S.O. 1894 dated 9-5-69. Gazette of 17-5-69.
- (iv) Notification No. S.O. 1768 dated 20 4-62, Gazett of 10-5-69
- (v) Notification No. S.O. 2696 1 ted 3-7-71. G zett. of 24-7-71
- (vi) Notification No. S. O. 3510 dated 23 9-72. Gazette C. 41-1-72.
- (vii) Notification No. S.O. 4521 dated 26-9-75, Grante of 18-10-80
- (viii) No ification N ... O 2914 d ted 13-10-89 Gazette of 25-10-80
- (ix) Notificati n No S O 45 d ted 10-12-81, Gazette of 2-1-82
- (x) Notification No. S. O. 1633, Juted 16-4-82, Gazette of 1-5-82

[Nc S 11020 (9)/81 D I (A)] 1 K NARAYANAN Under Secy

नई दिल्ल 22 तत्रम्बर 1982

का अा 4015 - वंन्द्र यं मरव र की यह राज है वि राव पारफेट (भ्रपाट इट खानो) व नियाजन की बाबन मजदूर क द न्यूनतम मजदूरी भ्रष्टिनियम 1949 (1)48 का 1!) ये अन्य न नियम जा ज्यान चाहिए

भ्रत कन्द्रीय सरक र उक्त श्रिधिनियम क धारा ?7 द्वार। प्रदत्त णक्तियो का प्रयोग करत हुए उक्त नियाजन का उक्त श्रिधिनियम का अनस्वीं के भाग 1 से जा ने के अपने अग्रय क स्वना दन न

इस श्रधिपूचना क राजप त मं प्रकार का ताराख मं तित माम की अविधि का समाप्ति पर या उसस पा उक्त पारवान के बंबत किसी व्यक्ति संजो भं सुधाव या ग्राधेप प्रात्त हा केन्द्र संसरक र उनपर विचार करेगा।

[एस 3 2017 3 81 डन यू स (एस ाय)] एम० वर्ष भहत अवर सचिव

New Delh, the 22n i November 1982

S.O 4015.—Whereas the Certral Government s of opinion that the minimum rates of wages should be fixed under ne Minimum Wages Act 1948 (11 of 1948) in respect of the employment in Rock Phosphate (Apatite Mines),

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 27 of the said Act the Central Government hereby gives notice of its intention to add the said employment to Part-I of the Schedule to the said Act,

Any suggestions or objections which may be received from any person in respect of the said addition on or before the expiry of a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, will be considered by the Central Covernment.

[No S-32017/3/81-WC (M.W.)] M. L. MFHTA, Under Secy.

New Delhi the 22nd November, 1982

S.O. 4016—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyde abad, in the industrial dispute between the employers in relation to the mangement of Singarem Collieries Co. I imited Kothagudem, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th November, 1982.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CFNTRAL) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 20 of 1980

BF FWFEN

Workmen of Singareni Collieries C mpany I imited. Kothagudem, Kharimam District (A.P.).

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited Kothagudem, Khammam District (A P.).

APPEARANCES:

Sri D. S. R. Vaima, Advocate-for the Workmen.

Sti K. Srinivasa Murthy, Honorary Secretary Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry, Hyderabad—for the Management

$\Lambda W \Lambda R D$

By Order No. L-21012(1)/80-D IV.B, dated 15-12-1980, the Government of India referred the following industrial dispute existing between the Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and then Workmen to this Tribunal for adjudication:

- "Whether the management of Messrs Singatem Collieries Company Limited, Kothagudem is instified in dismissing Shri D. Subbatao, Watchman, Manugtar Collieries with effect from 7-4-1980? If not to what relief is he entitled?"
- 2. After the above industrial dispute was taken on file in I.D. No. 20 of 1980 on 22-12-1980, notices were issued to both the Management and the Workmen. The Workmen filed their claims statement on 12-2-1981. To the above claims statement, the Management filed their counter on 17-3-1981. Sri K. Srinivasa Murthy appeared for the Management as Management's representative whereas Sri D.S.R. Varma filed his vakalat for the Workmen with the consent of the other side. The case underwent some adjournments for enquiry.
- 3. While so, on 9-8-1982, a compromise retifion signed by the Management and the Workmen was filed into this Tribunal. Since the parties were absent on that day, the compromise petition numbered as M.P. No. 100/82 was posted to 27-8-1982 for appearance of the parties to record the compromise On 27-8-1982 Sri. V. Gopala Sastry, Deputy Chief Personnel Manager of the Company was present. He admitted the execution and the terms of the compromise read over to him. As the Workmen were not present on that day, the case was adjourned from time to time till today. Today also the Workmen were absent. The advocate of the Workmen namely, Sri.D. S. R. Vanna who is present for

om the Workmen admus the truth and the execution of the compromise and the terms thereof. Hence the compromise is bli-recorded today.

- 4. The following are the terms of the compromise recorded in M.P. No. 100/82:—
 - "(1) The Management agreed to consider the case of Sri D Subba Rio, Ex-Watchman, S&PC, Manuguru on compassionate grounds
 - (2) Sri D. Subba Rao will be reappointed as Watchman, S&PC., in the Company and posted in any Division. He will be allowed the basic pay he was drawing at the time of his dismissal.
 - (3) The intervening period i.e. from the date of dismissal to the date of his reporting for work on reappointment will be treated as leave on loss of pay. Mr. Subba Rao shall not have any claim for wages or other benefits during the intervening period.
 - (4) The parties are filing this compromise on the above terms and conditions before the Hon'ble Tribunal, in full and final settlement of the dispute, with a prayer to the Hon'ble Tribunal to pass an Award accordingly"
- 5 In view of the above compromise admitted by both the parties, this Award is passed in terms of the above compromise. A copy of the compromise petition is appended to this Award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 15th day of October, 1982.

'No. L-21012(12)/80-D.IV(B)]

Sd/-

S S. MFHTA, Desk Officer Industrial Tribunal

APPENDIX OF EVIDENCE

−ŅJ**I −**

Sd/-

Industrial Tribunal

BUFORE THE HON'BLI- INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL), HYDERABA D

In the matter of I.D. No 20 of 1980

BETWEEN

The Workmen of S.C. Co Itd, Manuguru Division.

-Claimant/Workman.

AND

The Management of S.C. Co. Itd., Managerry Division. Respondent/Management.

It is submitted that without prejudice to the merits of the case before the Hon'ble Industrial Tribunal (Central), the patties desired to settle the issue mutually. Accordingly, the issue is settled on the terms and conditions set out hereunder.—

- "(1) The Management agreed to consider the case of Sri-D. Subba Rao, Fx-Watchman, S&PC., Managuru on compassionate grounds.
- (2) Sri D. Subba R to will be reappointed as Watchman, S&P,C., in the Company and posted in any Division. He will be allowed the basic pay he was drawing at the time of his dismissal.
- (3) The intervening period i.e., from the date of dismissal to the date of his reporting for work on reappointment will be treated as leave on loss of pay. Mr. Subba Rao shall not have any claim for wages or other benefits during the intervening period.

(4) The parties are filling this compromise on the above terms and conditions before the Houble Tribunal, in full and final settlement of the dispute, with a player to the Hon'ble Tribunal to pass an Award accordingly".

In the circumstances, both the parties, pray the Honble Industrial Tribunal (Central), to pass an Award in terms of the above compromise.

For Workmen:

For Management:

Sd/-Sd/-

(R. D. Sharma). (M. Komaraiah), Executive Director, Creneral Secretary. Singateni Collieries Workers' Union. M/s. The Singareni

Sd/- D Subba Rao.

Collieries Company Limited.

Dated: 13-7-1982.

Kothagudem Collieries.

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 4017.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Contract Industrial Contract In ernment Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Deoli Colliery, Ranipur Sub-Atea of Messis Eastern Coalfields Limited, and their worknien, which was received by the Central Government on the 17th November 1982

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. CALCUTTA

Reference No. 51 of 1978

PARTIES:

Management of Deoli Colliery, Rampur Sub-Area, Eastern Coalfields Limited

AND

Their Workmen.

APPEARANCES.

On behalf of Management -- Mi, J. N. Mishia, Senior Personnel Manager.

On behalf of Workmen-Absent

STATE: West Bengal INDUSTRY : Coal Mine

AWARD

The following dispute was sent to this Tribunal by the Government of India, Ministry of Labour vide Order No. L-19012(63)/77-D.IV(B) dated 12th May, 1978, for adjudication:

"Whether the action of the management of Ranipur Sub-Area of Eastern Coalfields Limited in stopping

Shri Umapada Kumbhakar, Office Boy Colliery from work with effect from 30-4-73 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?

- 2. No one appeared on behalf of the workman. The management is present and the case has been heard ex-parte. The case of the Coal Mane Employees Union, Dishetgarh (Briefly the Union) is that the concerned workman Umapada Kumbhakat was an office boy of the colliery and he worked as such till 29th April, 1973 But the management illegally stopped him from work with effect from 30th April 1973 on the ground that he was a minor. The management of the Deoli Colliery, Rampur Sub-Area of Eastern Coalhelds I to contends that the reference is not maintainbale against the Government company the dispute having arisen prior to 1st May, 1973 the appointed date as per the coalmines Nationalisation Act, 1973 and also because no industrial dispute existed between the parties concerned. It is denied that the concerned workman was an office boy of the The management stated that the concerned workcolliery. man was a domestic servant of an officer of the collicry and was aged only 14 years.
- 3. In view of the order dated 1st October, 1980 passed in this case by Sri R. Bhattacharya, my predecessor-m-office, it is not necessary to go into the ments of the case of other contentions of the management. By that older it has been held that no appreciable number of workmen of Deoli colliery were members of this union, that no appreciable number of workmen authorised the union to espouse the cause of stands to espouse the cause of the concerned workman and had no representative character to tepresent the workman and of the Deoli collicity. It has also been held by that order that the present dispute is, therefore, not an industrial dispute After having held so the learned Tribunal applied Section 2A of the Act and directed the concerned workman to authorise the Joint Secretary of the Union of any other competent person to conduct his case. In my opinion this case cannot be treated as one under Section 2A of the Act. No individual workman raised any industrial dispute in this case. It was the Union who raised the present industrial dispute. It was a collective dispute which was referred to this Tribunal for adjudication. When the union has been held to have no locus stands to espouse the cause of Umapada Khumbhakar the reference is not maintainable, I see the Division Bench case of Calcutta High Court in Deepak Industries 1 td and another vs. State of West Bengal and Others, 1975 Lab. IC 1133. In Swapan Dasgupta v .1st Labour Court, West Bengal, 1976 Lab. IC 202 at 206, Para 9 it has been held by Sabyasachi Mukherji J. that when the reference is not under Section 10 read with Section 2A, that is to say, the reference has not been made on the ground that there is a dispute existing between the employer and the individual workman, the reference cannot be upheld on the ground of Section 2A of the Act. Further more, it has to be noticed that it is a case of non employment, that is, stopping the concerned workman from work and not a case of dismissal, discharge of termination of service and

hence Section 2A of the Act can have no application.
Accordingly I hold that the present reference is not maintainable and it is dismissed as such.

Dated, Calcutta.

The 2nd November 1982.

Sd/-

M P. SINGH, Presiding Officer [No. L-19012(63)/77-D.IV(B)1 S. S. MEIIIA, Desk Officer

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O 4018.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Hyderabad and their workman, which was received by the Central Government on the 13-11 82.

For Petitioner

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) :-AT HYDERABAD.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 9 OF 1982.

BETWEEN :

The Workmen of State Bank of Hyderabid.

AND

The Management of State of Bank of Hyderabad.

APPLARANCES .

Sri B. V. Raghavulu, President, State Bank of Hyderabad Staff Association for Workmen.

Sri K Srinivasa Murthy, Honourary Secretary, Andhra Pradesh Federation of Commerce and Industry, Hyderabud for Monagement.

AWARD

By Order No. L-12011/41/81-D II(A), dated 19-2-1982, The Government of India referred the following industrial dispute existing between State Bank of Hyderabad and their Workmen to this Industrial Tribunal for adjudication:—

"Whether the management of State Bank of Hyderabad is justified in discontinuing the subsidised transport tacility provided to the Workmen working at their Ramchandrapurum Branch, Medak District, Andhra Pradesh with effect from 1st June, 1981?'

- 2 After the above industrial dispute was taken on file in 1. D No. 9 of 1982 on 25-2-1982, notice were issued to both sides. The workmen engaged their representative, namely, Sii B. V Raghavalu, whereas the Management engaged Sii K. Simivasa Murthy. The Workmen took some adjournments for filling their claims statement. Then both parties represented that the matter was under talks of compromise.
- 3 Ultimately today both the parties, representing that they settled this dispute out of Court, filed a joint memo withdrawing the industrial dispute. Accordingly permission was granted to the parties for withdrawing the dispute and this Award is passed. A copy of the joint memo is appended to this Award

Dietated to the Storographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 29th day of October, 1982.

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

APPENDIX OF FVIDENCE:

--NIL---

S. V. RAMANA REDDY, Presiding Officer.

[No. L-12011/41/81-D.H(A)] N. K. VERMA, Desk Officer

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDFRABAD A. P.

Industrial Dispute No. 9 of 1982

BETWEEN

The Workmen of State Bank of Hyderabad.

The Management of State Bank of Hyderabad.

JOINT MEMO LILED BY BOTH THE PARTIES

It is submitted that

The petitioners pray that the petition be treated as withdrawing as the dispute no longer exists.

For Management

(P. V. Bapicaju)

Manager, Personnel Administration Dept. State Bank of Hyderabad

Hyderabad,

Hyderabad. 29-10-82.

(B. V. RAGHAVULU, President)

State Bank of Hyderabad Staff Association.

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4019.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government bereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Court No. 1, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Food Corporation of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th Novemher, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

PRESENT:

Justice M. D. Kambli Fsqr, Presiding Officer

Reference No. CGIT 24 of 1978

PARTIES:

Employers in relation to the Food Corporation of Inche.

AND

Their Werkman

APPEARANCES:

For the employer. -- Mr. S. G. Ghate, Advocate,

For the workman, -- Mr. A. R. Atrey, Advocate.

Food Corporation INDUSTRY

STATE:

MAHARASHTRA

Camp:

Nagpur

Nagpur, the 20th October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-42012(7)/78-D. II(B). dated 4th December, 1978, in exercise of the powers conferred by clause (d) of subsection (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of the Food Corporation of India and their workman in respect of the matters mentioned in the schedule given helow .

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Food Corporation of India (Maharashtra Region), Bombay in removing Shri D. C. Thakkar, Jeep Driver, from service with effect from the 23rd March, 1977 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The workman, D. C. Thakkar, Jeep Driver, vas in the employment of the Food Corporation of India (Maharashtra Region) He has been removed from service after holding a domestic inquiry with effect from 23 3-1977. The point to be decided in this reference is whether the action of the management in removing the workman from service is justified.

- 3. The workman was chargesheeted on the following charges:—
 - "(1) That in spite of repeated instructions given, Shri D. C. Thakkat, Driver Grade II refused to comply with and obey lawful orders and refused to wear uniform thus contravened conduct Regulation 31(d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971.
 - (2) That Shri D. C. Thakkar, wilfully absented from duty w.e.f. 16-9-75 to 26-12-75 and again w.e.f. 5-1-1976 till date to avoid wearing uniform thus contravened Regulation 24(iv) & (vi) of FCI (Staff) Regulations, 1971.
 - (3) That Shi D. C. Thakkar, misbehaved with the acting District Manager, Shri N. G. Tongachkar on 12-8-75 and also with the Assit. Manager (Audit) camp Nappur during August 1975 when he was instructed in writing to wear uniform, contravening the conduct Regulation 31 of the FCI (Staff) Regulations. 1971.
 - (4) That Shri Thakku, purchased 20 liters petrol on credit coupons, when there was sufficient petrol in tank of feep No. MPJ-8883 and 20 liters petrol could not be accommedated in the tank. Thus Shri Thakkar has misappropriated and used petrol for non-official use.
 - (5) That Shri D. C. Thakkar, Driver is doing private business of plying three wheeler as Taxi, contravening the conduct Pepulations 24(iii) and 45(i) of the PCI (Stail) Republic no. 1971".
- 4. One Miss. I. M. rahiha it was appointed as the Inquiry Officer. She issued a notice dated 20th October, 1976, calling upon the workman to attend the hearing on 29-11-1976. Accordingly, the inquir; Officer held the inquiry which she called the preliminary hearing on 29-11-1976 at the office of the Zonal Manager, Mistry Bhavan, Bombay. Accordingly, the delinquent workman remained present before the Inquiry Officer on hat date. It is not in dispute that on that day the workman appeared before he Inquiry Officer and admitted the charge No. 1 viz., that inspite of repeated instructions given to him he refused to comply with them and refused to we is uniform thus contravening conduct Regulation 31(d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971. At that time, he did not admit the other charges.
- 5. According to the employer-corporation, later on, on the same day, the workman gave a letter to the Inquiry Officer which stated:—
 - "With reference to to lay's proceedings of the inquiry, I agreed for the charges against me and I therefore request you, kindly to excuse me and further I request for appology,"

According to the employer, on the same day he submitted his resignation to the Pegion 1 Manager, Food Corporation of India, Bombay, with a copy addressed to the District Manager, Food Corporation of India, Nagpur. However, before this letter admitting the other charges was given to the Inquiry Officer, the inquiry proceedings of that day i.e. of 29-11-1976 were closed and the next date for the inquiry was fixed on 13-12-1976.

- 6. According to the employer, as the workman had filed a letter admitting all the charges he did not appear before the Inquiry Officer on 13-12-1976. The Inquiry Officer, therefore, submitted her report on 14-12-1976 to the Regional Manager (Maharashtra), Food Corporation of India, informing him:
 - "Since the official has admitted all the charges and therefore there is no necessity for any further en-

- quiries to be conducted into the charges framed against him. Moreover it is learnt that the official has also submitted his resignation to the office. Under the circumstances ro further action appears to be taken by the Inquiry Office. The enquiry is therefore treated as completed from my side."
- 7. After the said report was received from the Inquiry Officer, the Regional Manager (Maharashira) issued a show-cauce notice to the workman informing him that he had come to the council ion that the workman was not a fit person to be retained in service and he proposed to impose on him the penalty of removal from service. The workman was called upon to show-cause against the proposed penalty.
- 8. The workman gave a reply to the show-cause notice on 12-2-1977 stating therein that he had accepted only the charge No. 1 and that some writing was obtained from him in which it was saied that he had accepted the other charges also. In this reply the workman denied that he had accepted the other charges. Ho, therefore, requested that he may be given a chance to defend him before the Inquiry Committee. The Regional Manager (Maharasht a) did not accept this representation and he proceeded to remove the workman from service from the date the order was served on him.
- 9. In the statement of claim the workman stated that he had admitted charge No. I in the morning at about 11 or 11.30 a.m on 29-11-1976 before the Inquiry Officer Thereafter, he was called by the Inquiry Officer in the afternoon for collecting the relieving order to enable him to collect his train farc, etc. The nonkman alleged that when he went before the Inquiry Officer in the afternoon she started effering inducements. His version in the statement of claim is as follows:—
 - "It may be stated here that though the workman is Gugarathi, he knows Sindhi. The Inquiry Officer was also a Sindhi lady and she induced the workman to admit charges framed against him by observing that he would only be warned in the matter and nothing would be done to him. She also made it clear to the workman that in case he does not accept the course suggested by her of admitting the charges framed against him, he would find himself in a very tight position. She also had promised and assured the workman that she shall see that he gets all the leave, dues etc. In case he accepts the charges. It is during the talk the workman had also informed the Inquiry Officer that on account of the behaviour of Shri Rathod, he does not want to work under him. It is in this background, the Inquiry Officer collected two documents from the workman on or about 29-11-76. Those documents do not represent the frue state of affairs. Latter dated 29-11-76 wherein the alleged claim is made that all the charges are admitted by the workman, is not a voluntary admission on the part of the workman; nor it is an admission of the fact that he his committed any mission of the fact t

It will thus be seen that the workman wanted to say that the Inquiry Officer had induced him to give some writing and collected two documents from him viz., the document admitting all the charges and the other document of resignation. The version of the management is that the letter of resignation was sent by the workman direct to the Regional Manager, Bombay.

- 10. A preliminary inquiry was therefore held as to whether the inquiry conducted against the workman was fair and proper. In that preliminary inquiry the employer examined the Inquiry Officer. Mis, I. M. Tahilianl. She was cross-pamined at leasth by Mr. Atrev, the learned counsel for the workman. The workman also examined himself. There is on record an application given by the workman to the Inquiry Officer on 29-11-1976 (exhibit XE-33). The text of the application is as follows:
 - "With reference to today's proceedings of the inquiry, I agreed for the charge, against me, and I, therefore,

request you kindly to excuse me and further I request for appology. Further it is requested to do the necessary in my favour on humanitarian ground as I am having a family and I did not receive the salary since Sept., 1975."

The workman admits that this letter bears his signature. There is another application dated 29-11-1976 (exhibit E-4) by the workman to the Regional Manager, Food Corporation of India, Bombay, whereby he submitted his resigna-tion from the post of Driver grade II at Nagpur and requested the Regional Manager to accept the same at The workman admits that this application also early date. bears his signature. In the preliminary inquiry held by me as regards the fairness of the departmental inquiry the version of the workman was that the Inquiry Officer had got the two above documents written from some clerk and that she had induced him to sign them. The version of the Inquiry Officer was that the workman handed over to her the letter at exhibit E-3 in the afternoon of 29-11-1976 in the earlier part of the dry in which admittedly the work-man admitted the charge No. 1 The Inquiry Officer stated in the preliminary inquiry held by me mat when the work-man handed over to her the letter at exhibit F-3 she asked him why he was admitting all the charges. The workman then told her that he had already submitted his resignation to the competent authority i.e. the Regional Manager, Bombay and therefore he was not interested in the job and he was therefore admitting all the charges. The varsion of the workman as regards the document or resignation i.e. exhibit be-4 was that the Inquiry Officer had prepared the document and had obtained his signature telling him that it was in respect of the sanction of his leave. The version of the workman in respect of the document at exhibit E-3 wherein he is said to have admitted all the charges is that he was told that it was in respect of the admission of the charge In my order on the preliminary point dated No. 1 only. 27-8-1982 I have disbelieved the version of the workman as regards these two documents. I have given my reasons in that order. I have held there that the workman wanted to tesign on his on accord as he was not pulling on well with his immediate superior one Mr. Rothod, the District Manager, Nagpur. I have also held that the workman voluntarily admitted all the charges against him, probably to ensure that he was leniently dealt with in respect of the sanctioning the he was lenicity dealt with in respect or the sanchoning the leave to his credit and other benefits, if any. Rejecting all the contentions raised on behalf of the workman I held in my order on the preliminary point dated 27-8-1982 that did not find any substantial infirmity in the inquiry proceedings and that the workman had voluntarily admitted at the charges. One of the charges framed against the workman was that he was doing private business while remaining absent from duty and that he has been plying a three wheeler as taxi. It is therefore probable that he was not interested in his job under the present employer. I have therefore pointed out in my said order that this may be one of the reasons why he wanted to resign the job and to admit all the charges in the inquiry.

11. It is not in dispute that he admitted the charge No. 1. It is not in dispute that he signed the letter dated 29-11-1976 (exhibit F-3) in which he admitted all the other charges. I have rejected the contention of the workman that he had signed that letter not knowing the contents—there of on account of some inducement offered by the Industry Officer. The charge No. 1 is as follows:—

"That inspite of repeated instructions given. Shri D C. Thakkai, Driver Gride II refused to comply with and obey lawful orders and refused to wear uniform thus contravened conduct Regulation 31 (d) and 32 of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971."

The other charges which are set out in paragraph 3 above show that the workman wilfully absented form duty for a substantial period. He misbehaved with the acting District Manager, Mr. N. G. Tongaonkar on the dote mentioned in the charge and also with the Asstt Manager (Audit) camp Nagar when he was instructed in writing some time in the month of August. 1975, to wear uniform. He purchased 20 littles of petrol on credit compons when there was sufficient petrol in the tank of the jeep and thus misappropriated and

used petrol for non-official use. He was doing private business of plying a three wheeler as taxi thereby contravening the conduct Regulations 24(iii) and 45(i) of the F.C.I. (Staff) Regulations, 1971. The regulations of the employer-corporation which he contravened by committing the above acts have been set out in the charges.

- 12. The question for consideration is whether the punishment awarded to the workman is justified. Now, the punishment imposed upon the workman by the competent authority, Regional Manager, (Maharashtia) is one of removal from service. Mr. Ghate, the learned counsel for the employer, submitted that the charges admitted by the workman merited the punishment of dismissal. However, on compassionate ground the punishment awarded against him is only one of removal from service. I am inclined to hold that no interference is called for the in the punishment awarded to the workman.
- 13. Mr. Atray, the learned counsel for the workman, submitted that as the workman hall tendered his resignation, further departmental proceedings should have been dropped. He also submitted that the punishment at any rate is highly disproportionate to the charges held proved against the workman. His arguments frather was that the competent authority who awarded the punishment was not examined on behalf of the employer and did not offer himself for cross-examination. I do not find any substance in any of the submissions. Admittedly the workman admitted the charges No. 1. That charge, in my opinion, is sufficient to merit the punishment awarded to the workman.
- 14. I therefore find that the action of the management of the Food Corporation of India (Maharashtra Region), Bombay, in removing the workman, D. C. Thakkar, from service with effect from 23-3-1977 is justified, and, therefore, the workman is not entitled to any relief.
 - 15. My award accordingly. No order as to costs

M. D. KAMBLI, Presiding Officer, [No. L-42012(7)/78-D II(B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer.

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4020.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank, Bombay, and their workman, which was received by the Central Government.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/2 of 1982

PARTIES:

Employers in relation to the management of Punjab National Bank

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri Gurbachan Singh, Manager (Staff)

For the workmen—Shri K. N. Mehrotra, Vice-President, A.I.P.N.B. Employees Association, 2. Shri G. L. Kadam, General Secretary, P.N.B. Staff Union.

INDUSTRY: Banking, STATE: Maharashira.

Bombay, the 19th October, 1982

AWARD

By their older No. L-12012/8/81-D.II(A), dated 6-1-1982 for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947;—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Bombay in refusing to grant extra allowance to Shri G. L. Kadam, Clerk, is justified? If not, to what rehef is the workman concerned entitled?"

- 2. On the allegation that the clerk-cum-typist Shri G, L. Kadam besides his routine duties was performing other extra duties like Care-taker officer looking after the property of the Bank both moveable and immovable and also performing some additional duties, the Union who is espousing the cause of the workman namely Punjab National Bank Staff Union has made a demand for special allownce as payable to Special Assistant from 18-8-1965 till June 1973 and in the statement of claim, although the order of reference does not speak to this effect, a further demand that from July, 1973, the clerk-cum-typist should be promoted in the grade of an officer grade 'C' or in the alternative as a Special Assistant.
- 3. The claim is refuted by the Respondent Bank on whose behalf written statement is filed at Ex. 2/M and rejoinder at Ex. 16/M, denying the allegation that the clerk-cum-typist was performing any extra duties involving greater skill and responsibilities, and therefore according to the Bank the employee concerned is not entitled to any extra allowance as claimed neither under any award nor under the Bipartite Settlements and as such the claim is not entertainable.
- 4. On the strength of these pleadings the following issues arise for determination and my findings thereto are:—

ISSUES

FINDINGS

1. Whether the Union proves that Shri G.L.Kadam was performing special duties as contended?

Doing extra dutie,

2. If yes, was he entitled to special allowance as claimed?

Extra allowance of Rs.50/-per month.

3. Whether in the light of the order of reference the question regarding the weongful designation as tried to be plouded by the Union in the statement of claim can be gone into?

No

4. What award

As per award'

REASONS

5. In support of the contention that Shri Kadam was performing some extra duties besides his normal duties namely the routine duties there is the evidence of the clerk concerned Ex. WW whereby stating that he was performing some extra duties namely attending to the complaints of the tenants occupying the Bank's quarters, attending the Corporation office to obtain permission for carrying out additions and alterations of the property of the Bank, examining the work of repairs carried out in the building and also the repairs to furniture and fixtures and to see whether the repairs were carried out according to the specification and to report to the superior officer and to attend the property cases pending in the courts, attending the office of the Bombay Telephone for obtain n additional lines, attending various garages for obtaining quotations for carrying out repairs to vehicles of the Bank, attending the office of the R.T.O. for getting the vehicles passed and to pay taxes. He used to purchase cloth from the market for preparing the uniform for the s'aff in the region and verify the petrol bills of the cash-Vans, looking after the wo'k of contractors undertaking repairs to Typewriters, Water-coolers, Air conditioners etc. and to see the same is done according to the specification, to arrange disposal and auction of urserviceable goods, attending the office of the Controller of accommodation for obtaining N.O.C. and booking Railway and plane tickets for the everytime obtaining obtaining No. plane tickets for the executives, obtaining quotations for purchase of stationery and to visit the shops and make recom-mendations to the Manager and also to be incharge of the furniture and flytures lying in the residential houses of executives on transfer.

- 6. Though in the cross-examination the actual nature of duties was tried to be challenged, the fact that all duties were performed by the employee is also stated by another two witnesses serving in the same Bank S/shii B. L. Desai and S. V. Pikelay and further there is an important piece of evidence in the shape of report by the Manager under whom Shii Kadam was then serving recommending the grant of Rs. 50 P.M. as special allowance. Shii B. L. Desai who is serving as a Special Assistant says that from June, 1981 he is serving in Property Section of the Bank and that before him Shii Kadam was performing the duties in the said Section and there is further admission that his duties were wider than the duties performed by the Special Assistant. But Special Assistant performing certain duties would not make them duties of a Special Assistant for which purpose we shall have to refer to the Award and Settlements especially Chapter V and Appendix B of Bipartite Settlement of 1966. Another witness Shii S. V. Pikelay refers to the attendance of Shri Kadam in the Municipal Corporation office in connection with Bank work, but this evidence is not of much help to the Union.
- 7. It is evident that the claim of Shri Kadam or the Union on his behalf cannot be for special allowance as admissible and defined under Chapter V of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966, for such special allowance an employee must be appointed as a Special Assistant and performing such duties for which certain modalities have been prescribed in the tarlier awards. Consequently unless and until Shri Kadam was entitled to become a Special Assistant or performing duties as laid down he could not have claimed special allowance pyable to the Special Assistant.
- 8. This however does not mean that if there is proof of his performing extra duties, duties not routine of a clerk-cumtypist and further the duties for which he was required to work during odd hours and not restricted to the office hours, then the claim of the workman shall not stand justified, especially when the record speaks that for such type of duties outsiders were demanding Rs. 800 per month, and that too for attending the work for one or two hours a day.
- 9. Apart from the oral evidence, there are the various reports of the Manager under whom Shri Kadam was then serving. At Ex. 20/M there is a Memorandum dated 25-7-73 written by the Manager, P.N.B. House, to the Senior Rigional Manager recommending the sanction of an allowance to the tune of Rs. 50 per month since Shri Kadam according to him was well trained in attending to such type of work referred in the letter. The Asstt. Regional Manager however as can be seen from Ex. 21/M turned down the said recommendations, even then the Manager by another Memorandum dated 26-11-1973 Ex. 22/M made the same recommendation saying that it was not possible to requisition a sub-overseer and it would be economical to pay the same amount to Shri Kadam was posted as Clerk-cum-typist and in that capa-nother letter Ex. 25/M dated 19-8-1974 from the same Manager to the Regional Manager followed by another letter Fx. 26/M dated 30-9-1974 and Ex. 27/M dated 7-10-1974. When all these letters are reach together, the only conclusion nos ble is that besides his normal duties Shri Kadam was performing some extra duties to the knowledge of the Manaeer under whom he was placed and said authority was also satisfied nbout the legitimacy of the employee's claim. We know that Shii Kadam was posted as Clerk-cum-typist and in that canacity he could not have been expected to attend the Municipal Cornoration office to obtain permission for carrying on addi-Cornoration office to obtain permission for carrying on auditions and alteration of the property of the Bank, to examine the work of renairs carried out in the buildings and repairs to furniture and fixtures in order to verified whether work was carried out according to the specification and to attend various offices in connection with the Bank's week and he was not adhering to the office hours and even the management. in his letter says that he was required to work at odd hours. Considering therefore the proof rendered by the Manager's correspondence although the superior authorities were not cumunced of the legality of the claim, having regard to the totality of the evidence and having regard to the fact that a sub-overseer would have been required to be appointed for neiforming the same duties and that subsequently the Pank approinted as Special Assistant agreeing to pay him Rs. 283 as special allowance for doing the same type of duties done hy Shri Kadam. I am convinced that he was performing extra duties as contended and that his claim for extra allowance can be said to be just and legitimate.

- 10. From the representation of Shri Kadam which is referred in the Manager's letter dated 25-7-1973, Ex. 20/M it seems that for the first time the incumbent started claiming extra emoluments from July, 1973 though he was on that job since 1965 and if the incumbent himself realised about the extra duties in the year 1973 and then started moving in the matter, despite the proof that he was doing the same type of work earlier in point to the time he claim will have to be restricted to the period from July, 1973 and not before.
- 11. Once it is appreciated that what is claimed is not special allowance which cannot be claimed by Shri Kadam as he could never be appointed as special Assistant till 16-8-81, the quantum of Special allowance can never be Rs. 283 which is the special allowance prescribed under the Bipartite Setdement. The Union has got produced various correspondence and since the Manager who was the best person under whom Shri Kadam was working has recommended to grant Rs. 50 as allowance, it carries great weight. What was the representation of Shri Kadam is not on record but the fact that the correspondence was got produced shows that the Union also must be agreeing with his recommendations. Considering therefore that it is not special allowance but at the same time considering that Shri Kadam was performing extra duties other than the normal routine duties that too during odd hours which fact the Bank has admitted, I am convinced that he is entitled to extra allowance of Rs. 50 from July, 1973 to the end of July, 1981.
- 12. There is a prayer that either Shri Kadam should be granted the special allowance as Special Assistant or he should be promoted as Officer in grade 'C' but in the light of the order of reference, the prayer can never be considered as the prayer falls outside the scope of reference. I may add here that for promotion as officer there are certain formalities prescribed, similarly for the posting as Special Assistant there are certain modalities. So far as the promotion to the Officer's cadre, not only there is seniorily but also it depends upon how Shri Kadam is suitable to the post which can be judged by the superior officers of the Bank appointed for the same purpose. While deciding the present reference I can not consider the claim for promotion or for his posting as Special Assistant, as such request to this effect cannot be considered at all. The only conclusion is that Shri Kadam is granted extra allowance of Rs. 50 per month for the period as stated earlier. The Bank is to calculate the extra allowance and accordingly to pay the same to the concerned employee within one month from the date of this Award. No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-12012(8)/81-D.H(A)]
Central Govt. Industrial Tribunal
N. K. VERMA, Desk Officer.

New Delhi, the 24th November, 1982

S.O. 4021.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Acr. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New India Assurance Company Limited, Calcutta, and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNÁL, CALCUTTA

Reference No. 60 of 1980

PARTIES:

Employers in relation to the management of New India Assurance Company Limited, Calcutta

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES:

- On behalf of Employers—Mr. T. N. Mukherjee, Labour Adviser for the management.
- On behalf of Workmen-Mr. Anil Das Choudhury, Advocate.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Insurance.

AWARD

By its Order No. L-17011/5/79-D.IV(A) dated 15th July, 1980 the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

- "Whether the action of the management of New India Assurance Co. Ltd., Calcutta in denying officiating position and officiating allowance to Shri N. C. Tarafdar, Assistant at Area Office Accounts and Shri M. Dhara, Assistant et Division No. 3, with effect from 7th July, 1976 is justified? If not, to what relief are the conterned workmen entailed?"
- 2. The two questions to be determined in the present case are, (i) whether the two assistants aforesaid officiated in the post of Senior Assistant and (ii) whether they are entitled to officiating allowance from the management for the same with effect from 7th July, 1976. In my opinion the answer should be in the affirmative.
- 3. WW-1 Nemai Chandra Tarafdar, the Assistant (No. 4643) of the Area office Accounts is one of those two. His evidence is that he acted in officiating capacity on the post of Senior Assistant K. P. Nair from March, 1976 to March, 1979 when K. P. Nair Senior Assistant was promoted as acting Superintendent, under verbal order of the Assistant Manager R. Krishnan. His further evidence is that that was a higher post and that all the relevant documents concerning his officiating position were lying with the management; that he while acting in the post of Senior Assistant performed the duties mentioned in the letter Ext. W-1 dated 29th March, 1978. Those duties are also mentioned in para (8) of the written statement and run as follows:—
 - (i) G.I.C. Premium Statistics (Eastern Region).
 - (ii) Area performance Gross Direct premium Income.
 - (iii) Monthly premium in respect of number of claims paid and outstanding summary (Eastern Region).
 - (iv) Number of documents Summary.
 - (v) Codewise analysis of Misc. Disbursement book.
 - (vi) Various,"

He has further said that M. Dhara, another Assistant also officiating in the higher post of Senior Assistant and he too performed underwriting work in connection with the Inspector Code. The witness has also deposed that Barin Ghosh and Pradeep Kumar Dutta got officiating allowance for having done the work of Mr. Taimol in the Marine Claim Department, that they also had worked under the verbal order and similarly one Chakraborty (Samar Chakraborty as per written statement) and N. Chanda got officiating allowance. These two had worked with Mr. M. Dhar and they also had worked under the verbal order. In the cross-examination WW-1 says that there is clear division between the work of the Assistant and the work of Senior Assistant, that the work of underwriting is done both by Assistant and Senior Assistant. He explained it by saying that an Assistant does it without correspondence. He has further deposed that in the branch and Divisional office either Assistant or Senior Assistant does the work of statistics but in the Area office or

in Controlling office the it is done only by Senier Assistant. It is needless of say that WW-1 is in the Area office. I see no reason to disbelieve him.

- 4. The managements own letters to the various Assistants go to show that the fact of officiating was not challenged. Ext. M-1 is letter dated 27th June, 1978 written by the management to Samarendra Chakraborty, another letter Ext. M-2 dated 5th December, 1979 written to Subir Chakraborty (with whom N. Dhar and N. Chanda had worked) and Ext. W-2 the letter written to WW-1, namely, Mr. Tarafdar indicates that the fact of officiating was not in dispute. All these persons had claimed officiating allowance The claim was considered and rejected on the ground that officiating allowance was not admissible as per provisions from GIC. The ground is vague. The claim was rejected on a vague technical ground and not on the ground that they did not officiate.
- 5. The argument of the management before this Tribuhag not examined R. Krishnan, the Assistant Manager under not at all correct. It is to be noted that the management has not examined R. Krishnan, the Assistant Manager under whose verbal order WW-1 claim to have acted in officiating capacity. It is also to be noted that in the written statement the management raised only preliminary issue and did not deny the fact officiation. In the written statement which is on record only preliminary objection has been stated. No. statement about the fact of officiating has been made. The reference is of the year 1980, Even within this period of two years and more no other written statement on merit has been filed. There is thus no denial of the fact of officiation. So far as the preliminary objection is concerned it is frivolous and at the very commencement of the hearing of the case I nonted it out and then evidence was taken on merit. The witness of the union was cross-examined by the management and the case has been heard on merit only. From the various letters aforesaid indicating that the fact of officiation was not in dispute, from the absence of denial in the written statement of the management and from the evidence of WW-1 N. C. Tarafdar I come to the conclusion that the two Assistants officiated in the post of Senior Assistant. There can be no doubt that the two nosts are different with difference scales of nav. The post of Senior Assistant carries a scale of Rs. 230 735 and the post of Assistant has the scale of Rs. 175-585. The contention of the management that there is
- 6. The next question is whether the two Assistants are entitled to officiating allowance. There can be no doubt that they are entitled. Clause 15 of the General Insurance (N fignalisation) and Revision of Pay Scales and other conditions of service of Supervisory Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 runs as follows:
 - "15. Officiating Allowance—An employee may be required to hold officiating charge of a post in a higher category or additional charge of an equivalent post whenever considered necessary and where such officiating charge or additional charge is held for a continuous period of 15 days or more, the employee shall be paid a pro-rata allowance as follows, namely:—
 - (i) Officiating in a higher category of post: 20 per cent of his basic salary, subject to a maximum of Rs. 1000/- per month;
 - (ii) Additional charge of an equivalent post: 10 per cent of his basic salary, subject to a maximum amount of Rs. 50/- per month."

On a perusal of the above it is obvious that the two Assistants concerned in the present case are entitled to officinting allowance. The management argued that there was doubt and difficulty in the interpretation of this clause and so in 1001 GI/82—4

paragraph 21 of the 1974 Scheme it is the Central Government which can decide the dispute and not this Tribunal. The point has no froce. I do not see any doubt or difficulty in interpreting the provisions of Clause 15. The words of this clause are plain and unambiguous. It clearly confers light on an employee to get officiating allowance on pro-rata basis as mentioned therein. The contention is, therefore, rejected.

7. In the result my award is that the action of the management in denying officiating position and officiating allowance to Sri N. C. Tarafder Assistant at Area office Accounts and Sri M. Dhar, Assistant at Division No. III with effect from 7th July 1976 is unjustified. Both these Assistant are held to have officiated in the post of Senior Assistant as claimed by them and both are entitled to officering allowance admissible in Clause 15 of General Insurence (Nationalisation and Revision of Pav Scales and other conditions of service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974.

[No. L-17011(5)/79-D.IV(A)] M. P. SINGH, Presiding Officer

Dated, calcutta the 7th October, 1982

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 4022.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Nasik Division and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Life Insurance corporation of India Nasik Division.

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the Employers-Shri P. R. Pal, Advocate.

For the workmen—Shri V. D. Kathuria, Jt. Secretary, All India Life Insurance Corporation Employees' Federation.

STATE: Maharashtra INDUSTRY: Insurance

Bombay, dated the 18th October, 1982

AWARD

By their order No. L-17011/4/78-D.IV(A) dated 15-4-1980 the following disputes pertaining to Nagpur Division has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act and subsequently by order No. L-17025/4/30-D.IV(A) dated 31-3-1981 the Nasik Division of the Life Insurance Corporation of India was added:

- 'Whether the demand of the existing empanelled badli workmen In Nagpur and Nasik Divisions of the Life Insurance Corporation of India for their absorption as regular employees is justified ? If so, to what relief and from which date are the concerned workmen entitled?"
- 2. The Parties including Vima Karamchari Sanghatana Nasik have filed their pleadings and the written statement of Sanghatana assumes importance that being the only Union which is contesting the whole claim.
- 3. Now though as reference stands speaks of the existing empanelled badli workmen, the Union in paragraph 17 of Ex. 13/W states that there is no panel of Badli workmen at Nasik. Because of this assertion the contention raised on behalf of the Life Insurance Corporation of India is that when there was no panel, while the reference speaks of existing empanelled badli workmen, and if it is the order of reference which gives and confers jurisdiction to entertain the dispute, the present reference would not be sustainable in the absence of any panel. There is great force in this contention and when the order of reference is specific I cannot read in between the line or something different than what it speaks and the only course open to the Tribunal is to dispose of the reference on the ground that it is not sustainable This order is not being passed on merits nor the real dispute is being decided and therefore if the parties especially the workmen are in a position to raise a dispute, the disposal of the present reference on the issue in question should not create any bar in their path.
- 4. I was given to understand that with regard to similarly placed badli workmen at Nagpur, the Life Insurance Corporation of India entered into a settlement with the Union representing the case of those workmen whereby certain rights have been conferred and they have been absorbed in service. in terms of which settlement I am told there is an award passed by the Tribunal. When therefore the Life Insurance Corporation has entered into a settlement with regard to similarly placed employees at Nagpur, apart from the technical defect as noted, when the case of the employees at Nasik is on par with their counterpart at Nagpur, the Corporation should consider whether those very benefits which it has decided to extend to the Badli workmen at Nagpur should not be conferred on the workmen similarly placed at Nasik, since their contentions are of similar nature and they are alleged to have put in certain years of service in the Corporation. After all the Corporation has to give lead to other employers so that no cause for any just grievance remains.

No order are to costs.

Dt: 2-11-82.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-17025/4/80/DIV(A)]
T. B. SITARAMAN, Desk Officer.

New Delhi, the 25th November, 1982

S.O. 4023.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kenda Area of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post

Office Bahula, District Burdwan, and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No 52/82

PRESENT:

Shrri J. N. Singh. Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Kenda Area of M/s. Hastern Coalfields Ltd., P.O. Bahula, Dist. Burdwan.

AND

Their workmen

APPEARANCES:

For the Employers-Shri N Das, Advocate.

For the Workmen-None.

INDUSTRY : Coal.

STATE : West Bengal

Dated, the 9th November, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 19012 (23)/82-D. IV (B) dated the 28th May, 1982.

SCHEDULE

- Whether the action of the General Manager, Kenda Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Bahula, Dist. Burdwan in not properly designating and placing Shri Sushil Kumar Pathak and Paresh Chandra Mandal as Store Keepers in Clerical Grade-I, is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"
- 2. After receipt of the Reference notices were issued to both the parties for submission of their written statement. The management filed their written statement on 10-8-82 but the union was absent inspite of notice. The case was adjourned to 1-9-82 and on that date also the union absented themselves. A fresh notice was issued to the union directing them to file written statement by 24-9-82 failing which the case will proceed exparte. On 24-9-82 also the union did not appear inspite of service of notice and again a fresh notice was issued fixing 22-10-82 for hearing but again the union did not appear nor filed any written statement.
- 3. Thus it is clear that the union is not taking any interest in the case and they have no dispute with the management.
 - 4. In such circumstances a 'no dispute' award is passed.

J.N. SINGH, Presiding Officer [No. L-19012/(23)/82-D,IV(B)]

5.0. 4024.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Jaykaynagar, District Burdwan, and their workmen which was received by the Central Government on the 18th November 1982

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 3, DHANBAD

Reference No. 4/81

PRESENT:

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Nimcha Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan

AND

Their workman.

APPEARANCES:

For the Employers-Shri N. Das, Advocate

For the Workman-None.

INDUSTRY : Coal.

STATE: West Bengal.

Dated, the 10th November, 1982

AWARD

The Govt, of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(35)/80-D.IV(B) dated the 31st January, 1981.

SCHEDULE

"Whether the management of Nimcha Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Jaykaynagar (Burdwan) was justified in not regularising Shri Kamta Prasad Gupta as Canteen Manager/Canteen Supervisor in Clerical Grade II with effect from 1-12-1977? If not, to what relief the workman is entitled to?"

- 2. On 9-11-82 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in term, of the settlement.
- 3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

I N. SINGH, Presiding Officer [No. L-19012(35)/80-D.IV(B)]

Enc : Settlement.

BEFORE THE HONOURABLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 3, DHANBAD

Ref. No. 4 of 1981

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Nimcha Colliery, ECL, P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan

AND

Their workman

The Parties most humbly pray as under :-

That the above mentioned reference case has been fixed for hearing on 9-11-82.

That, the parties have discussed the matter and have come to an amicable settlement in favour of disposal of the case on the following terms and conditions,

- (a) the incumbent namely Sii Kamta Piasad and Gupta will be designated as Canteen Manager and will be placed in Clerical Grade-II in the pay scale of Rs. 508-23-692-29-808/- under the Wage Board for the Coal Mining Industry/NCWA-II with effect from 1-4-1982.
- (b) Sri Gupta will continue to be posted at Nimcha Colliery until further orders.
- (c) It has been also considered and agreed by the parties that Srî Gupta would be given 3 increments in the aforesaid Clerical Gr. II on fixation/fitment of his basic salary in Gt. II. The union or the workman shall have no claim for any other payments on any account relating to the dispute under disposal.
- (d) the instant settlement shall have no precedence. Under the aforesaid circumstances, the parties jointly pray for accepting the said terms of settlement by the Hon'ble. Tribunal and to pass on Award accordingly for disposal of the case under the Reference No. 4 of 1981.

J. N. SINGH, Presiding Officer

For the Union representing the workman,

Sd/-

For the Employers,

Sd/-(Shiv Kant Pandey).

Secretary,

Koyala Mazdoor Congress.

Satgram Area, Dt. 8-11-82. (D.R.K. Rao).

Personnel Manager,
Satgram Area, ECL.

Filed by

Sd/-

P. L. OJHA,

9-11-82 S. R.P.O. Salgram Area. S.O. 4025.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government Rereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ningha Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Kalipahari, District Burdwan, and their workmen which was received by the Central Government on the 18th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 57/80

PRESENT:

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Ningha Colliery, Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kalipahari (Burdwan)

AND

Their workman.

APPEARANCES:

For the Employers-Shri B. N. Lala, Advocate.

For the Workman-None.

INDUSTRY: Coal STATE: West Bengal

Dated, the 10th November, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(63)/79-D.IV(B) dated the 23rd September, 1980.

SCHEDULE

- "Whether the action of the managemen t of Ningha Colliery, Eastern Coalfield, Ltd., P.O. Kalipahari, (Burdwan) in not changing the designation of Shri Rameshwar Yadav as Labour Supervisor and in not placing him in proper grade with effect from 1st Septmebr 1974 was justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"
- 2. On 8-11-82 both the parties have filed joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in their terms of the settlement.
- 3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.
- 4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COUR'T NO. 3, DHANBAD

Ref. No. 57 of 1980

PARTIES:

Employers in relation to the Management of Ningah Colliery of Eastern Coalfields Limited

AND

Their workman.

Joint petition of compromise:—
Both the parties, herein concerned, most respectfully submit and state as follows:—

- That the above matter is pending adjudication before the Hon'ble Tribunal.
- (2) That, in the meantime, both the parties mutually negotiated the instant dispute and have settled the dispute on the following terms:
 - (a) That the employers agree to post Sri Rameshwar Yadav, the workman, herein concerned in the post of Clerk in Clerical Gr. II of the National Coal Wage Board Recommendation NCWA-I and II within a week from the date of Honble Tribunal accepts this settlement.
 - (b) That the workmen agree that they shall have no claim whatsoever for any back wages in any matter arising out of the present dispute.
 - (c) That the settlement fully resolves the insant dispute.
 - (d) That the parties shall bear their own costs of the proceedings.
- (3) Both the parties pray that the Honble Tribunal may be pleased to accept this settlement as fair and reasonable and may be pleased to pass an award in terms of the settlement.

And for this act of kindness the parties as in duty bound shall ever pray.

Dated this the 6th day of November, 1982

Sd/- Sd/-

For and on behalf of the workman. For and on behalf of the General Secretary.

Management.

[No. L-19012(63)/79-D.IV(B)] S. S. MEHTA, Desk Officer

आवेश

नई दिल्ली, 3 भगस्त, 1982

का॰आ॰ 4026---केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायब प्रनुस्था में विनिधिष्ट विषय के बारे में सेन्ट्रल बैंक प्राफ इंडिमा, अयपुर के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों भीर उनके कर्म-कारों के बीच विद्यमान है;

भीर केलीय सरकार उक्त विवाद की न्यामनिर्णयम के लिए निर्वेशित करना बांछनीय समझती है;

यत : केन्द्रीय सरकार, भौदोगिक विवाद प्रविनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भीर धारा 10की उप-धारा (i) के जंड (घ) द्वारा प्रवस पित्तयों का प्रयोग करते हुए, एक भौदोगिक भिक्षकरण गठित करती है जिसके पोठासीम भिक्षकरों श्री रामराज लाल गुप्त होंगे, जिनका मुख्यालय जयगुर में होगा भीर उकत विवाद को उकत प्रविकरण को स्यायनिर्णयन के लिए निवेशित करती है।

अनुसूची

क्या सेन्द्रल बैंक प्राफ इंडिया, जयपुर के प्रबंधतंत्र की भी एस० एस० गर्मा, उप-लेखापास तथा एक संरक्षित कर्मकार की तारीख 19-10-66 के द्विपकीय समझौत के उपवंधों के प्रमुखार ब्यूटी छुट्टी तथा याच्रा क्ला/वैनिक क्ला न देने की कार्यवाई व्यायोखित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस प्रमुलीय के हकदार हैं ?

[सं॰ एल-12012/269/81-की. II. ए.]

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 1982

S.O. 4026.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Bank of India Jaipur and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitute an Industrial Tribunal of which Shri Ramtaj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Bank of India, Jalpur in denying duty leave and payment of T.A./D.A. as per the provisions of Bipartite Settlement dated 19-10-66 to Shri S S. Sharma, Sub-Accountant, and a protected workman is justified? if not, to what relief is the workman concerned entitled?".

[No. L-12012/269/81-D. II(A)]

आवेशः

नई' दिस्सी,' 10 ग्रगस्त, 1982

का क्यां 4027 — के की य सरकार की राय है कि इससे उपावस अनु-सूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्नाटक बैंक लिए, हाबारी के प्रबंध-तंत्र से सम्बद्ध एक भौबोगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

भीर केलीय सरकार उपत विवाद को स्थायनिर्णयम के लिए निर्वेशित करना बांधनीय समझती है : शतः केन्द्रीय सरकार, भौधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (श) क्षारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक ग्रीधोगिक ग्रीधकरण गठित करती है जिसके पीठासीम ग्रीधकारी श्री बी॰ एच॰ उपाध्याय होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलोर में होगा, और उक्त विवाद की उक्त ग्रीधकरण की न्यायनिर्णयम के लिए निर्वेशित करती है।

प्रमुखी

नया कर्नाटक मैन लि॰, हुबली के प्रबंधतंत्र की हामारी शाखा के धन निसेष प्रचारक श्री एस. सी. बेल्लारी की वेय मासिक कर्नाणन की पीकते उसकी विए गए संबहण कार्जों की मोगने तथा प्रवंधतंत्र के धार्वेश सं॰ 5306/81 सारीष्ट्र 23-9-81 द्वारा 1-9-81 के भूतलकी प्रभाव से उसकी सेवामों की समान्त करने की कार्रवाई न्यायोखित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस ध्यावीय का हक्कार है ?

[सं० एल-12011/75/81-ही.2ए.]

ORDER'

New Delhi, dated the 10th August, 1982

S.O. 4027.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Karnataka Bank I.td., Havari and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947. (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri V. H. Upadhaya shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Karnataka Bank Ltd, Hubli in with holding the monthly commission payable to Shri S. C. Bellary. Money Deposit Canvasser, Havari Branch in demanding collection cards given to him and in terminating his services with retrospective effect from 1-9-81 by order No. 5306/81 dated 23-9-81 of the manager is justified? If not, to what relief is the workman entitled?",

[No. L-12011/75/81-D,II(A)]

आदेश

नहैं दिल्ली, 21 झगस्त, 1982

का० और० 4028.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद सनुसूची मैं विनिधिष्ट विषय के बारे में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक बीधोगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

भौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निवॅशित करना विक्रतीय समझती है ;

भत : केन्द्रीय सरकार, भौद्योगिक विवाद भवित्यम, 1947 (1947 का 14) भी धारा 7-क भीर धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (म) द्वारा प्रवत्त सिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एक भौद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठांसीन भविकारी श्री जी एस. बरीत होंगे, जिनका मुख्यालय घरमवानाद में होगा और उक्त विवाद की उक्त भविकरण भी त्यानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची ं

"क्या स्टेट वैक झाफ सौराष्ट्र के प्रबंधतंत्र की श्री विजु भाई रायाभाई चेकासिया, गोवाम चौकीवार, जवाहर चौक शास्त्रा सुरेन्द्र नगर, की सैव. 1-8-79 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो सेवंधित कर्मकार किस धनुसीय का हकदार है ?"

[सं॰ एल-12012/348/81-डी. 2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 21st August, 1982

S.O. 4028.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of Saurashtra, Surendranagar and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annxed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Bafot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of Saurashtra in terminating the service of Shri Vijubhai Rayabhai Chekhalia, Godown Chowkidar Jawahar Chowk Branch, Surendranagar with effect from 1-8-79 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?".

[No. L-12012/348/81-D. II(A)]

आवेश

नई विल्ली, 23 प्रगस्त 1982

का॰ आ॰ 4029 — केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के धारे में बैंक झाफ बड़ीदा, श्रष्टमदाबाद के प्रकन्धर्तल से सम्बद्ध एक भौधोगिक विवाद नियोजको और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं ;

भीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को व्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना बौछनीय समझती है ,

भत: केस्वीय सरकार, भौदोगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भीर धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रवस ग्रवितयों का प्रयोग करने हुए, एक श्रीद्योगिक श्रधिकरण गठित करती है जिसके पीठामीन श्रधिकारी श्री जीव एसव बरीत होने, जिनका मुख्यालय भहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त श्रधिकरणको न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसू ची

"क्या मैंक भाष बड़ीवा के क्षेत्रीय कार्यालय, प्रह्मवाबाद के प्रबंधकंत्र की श्री एन० बी० दिगे, सब-स्टाफ की 31-5-1981 से सेवाओं की विक्रीलन करने तथा समाप्त करने की वार्रवाई उचित और न्यायसंगत है? यदि नहीं, सो कर्मकार किस अनुतोप का हकदार है ?"

[स॰ 12012/397/81-की॰ 2(ए)]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1982

S.O. 4029.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of Baroda, Ahmedabad- and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot, shall be the Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bank of Baroda Region Office, Ahmedabad in terminating and or discontinuing the services of Shri N. V. Dige, sub-staff with effect from 31-5-80 is legal, proper and justified? If not, to what relief is the said workman entitled?".

[No. 12012/397/81-D. II(A)]

आहेर

नई विल्ली, 25 धगस्त, 1982

का० आ० 4030.--केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद अनुसूची में विनिधित्य विषय के बारे में जयपुर प्रौचलिक ग्रामीण वैक के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक भौद्योगिक विवाद नियोजकों भौर उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है:

भीर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना बांळनीय समझती है;

मतः, केन्द्रीय सरकार, भौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क भौर धारा 10 की उप-धारा (1) के खब (व) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, एक भौद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन प्रधिकारी श्री रामराज लाल गुप्ता होंगें, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा भौर उपन निवाद को उक्त प्रधिकरण को स्थायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करनी है।

अनुसूची

"क्या जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, अयपुर के प्रबन्धतंत्र की ग्रपने कर्मचारियों की भविष्य निधि ग्रंगदान की कटौती 1-11-1978 से 8.33 प्रतिगत के स्थान पर 6.25 प्रतिगत करना न्यायोचित हैं? यदि नहीं सो संबंधित कर्मकार किस ग्रमुतोष के हकदार हैं?"

> [सं॰ एल-12011/65/81-को॰ 2(ए)] एन० के॰ वर्मा, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 25th August, 1982

S.O. 4030.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jaipur Aanchlik Gramin Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Ram Raj Lal Gupta shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur in deducting Provident Fund Contribution of its employees @ 6.25 per cent of their basic Pay instead of @ 8.33 per cent with effect from 1-11,1978 is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?".

[No. L-12011/65/81-D. Π (A)] N. K. VERMA, Desk Officer

नई किंगे 8 नत्का, 1993

का० आ० 4031 — मेससं जुपटर रेडियों (रिज०) सी-46, श्रोकला, इण्डस्ट्रियल एरिया, फेम II. नई विल्ली-20 (जिले इसमें इसके पश्चास् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मकारी प्रविच्य निधि और प्रकीर्ण उगवन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चास् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छट विष् जाने के लिए मानेदन किया है;

भीर लेखीय संरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मचारी, किनी पृथक श्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय की जन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के झशीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायबों से झिंधन अनुकूल हैं जो कर्मचारी निकीप महबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें भनुकीय हैं;

भत , केर्ज्य सरकार, उस्त प्रधितियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदन मिन्तयों का प्रयोग करने हुए भीर इससे उपावद मनुसूत्वे में विनिर्दिष्ट गतों के भ्रष्टीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की सर्वाध के लिए उन्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में खुट देती है।

अमुसूची

- 1 उस्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक सम्बद्ध निधि धासुकत नई दिल्ली को ऐसी विवर्णियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा तिरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केस्ब्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाध्य के 15 बिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उनत प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके प्रत्यांत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संबाय, क्षेत्राओं का प्रत्यत्रण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमावित मामहिक बीमा स्की म के नियमो की एक प्रति, भीर जब कमी उनमें संगोधन किया आए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंक्या की भाषा में उसकी मुख्य वातों का प्रमुवाव, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी श्विष्य निधि का या उक्स प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किती स्यापन की श्विष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त धर्ज करेगा और उसकी बाबन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को गंदन करेगा।
- 6. यदि जनन स्कीम के प्रधीन वर्मचारियों को उपलब्ध फायदे वढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृष्टिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित क्य से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि यर्भचारियों के लिए मामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक अनुकृत हों जो उत्तत स्कीम के अधीन अनुक्षेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए मी, यदि किसी कर्मवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मवारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उनत स्कीम प्रधीन होता तो, तियोजक कर्मवारी के विधिक भारिम/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के कप में दोनों रकमों के धन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।

- 8. मामूहिक अीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संसोधन, प्रावेशिक प्रित्या निधि श्रामुक्त गई दिल्ली के पूर्व धनुसोधन के बिमा नहीं किया जायेगा और जहा किया सणीधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि श्रामुक्त, धपना श्रनुसोदन देने से पूर्व नर्मचारियों को श्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करमें का युक्तियुक्त श्रवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मजारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका हैं प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मजारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्व की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारी के भीतर, जो भारतीय जीवन बीभा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिमी को ज्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रहुव की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिष्यितियों या विधिक वारिसों की जो यबि यह, छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के घन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. जक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधील धालें वासे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/ विधिक बारिसों की बीमाइन रकम का संदाय तत्वरता से मौर प्रस्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से कीमाइन रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/230/82-र्पा॰एफ-2]

New Delhi, the 8th November, 1982

S.O. 4031.—Whereas Messrs Jupiter Radios (Regd.) C-46, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-20 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of

accounts, payment of inspection charges etc. chail be borne by the employers.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the 3r p Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the emptyees
- 5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Gran; Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange in enhance, he berents available to the enviloyees and the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee theamount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for navment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the spid Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entirled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (230)/82-PF, III

नदिविल्ली, 9 मध्यम्बर, 1982

का॰आ॰4032---केसीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कैमिकल डिस्ट्रीक्यूटर्स कारपोरेशन, 573, ब्लाक-एन॰, न्यू प्रलीपुर, कलकता-53 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहनत हो गई है कि कर्मचारी भिष्ण्य निधि भीर प्रकीर्ण उपक्षण्य प्रधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबश्य जनत स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त भविनियम की द्यारा 1 की उपद्यारा (4) हारा प्रदल सकितयों का प्रयोग करते हुए, उक्त भविनियम के उपवक्त उक्त स्थापन को लागू करती है।

सिक्या, एस०-35017/101/82-पीर् एफ०-III

New Delhi, the 9th November, 1982

S.O. 4032.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chemical Distributors Corporation, 573, Block-N, New Alipore, Calcutta-53, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1932), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017/101/82-PF, II]

का॰आ॰ 4033 — केश्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्च प्रार्ट ट्रेंड एक्सपोर्टेस (प्राइवेट) लिसिटेड, 12, च्रेगा रोड, कलकत्ता-17 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचा भिष्य निधि और प्रकीण अपबन्ध प्राधिनियम, 1982(1952 का 19) के उपबन्ध उकत स्थापन को लाग् किये जाने काहिये;

भात केम्ब्रीय सरकार, उकत प्रशिवियम की धारा 1 की उपधान्य (4) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करत हुए, उक्त प्रशिवियम के स्थानक उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एस॰-35017/96/82-पी॰ एफ॰-I]]

S.O. 4033.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Art-Trend Exports (Private) Limited, 12, Darge Road, Calcutta-17, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No.S-35017]96[82-PF.II]

का ब्यान 4034---केन्द्रिय संरकार की यह प्रतीत होता है कि मैससें जालान प्रोडक्शन्स, 183/1, धर्मटोला स्ट्रींट, (बूसरी मंजिल) कलकत्ता-13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस धाल पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि ग्रीर प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रीविष्यम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन की नागू किये जाने का हिंचे;

मतः केसीय सरकार, उपन भिधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपत श्रिधिनियम के उपबन्ध उपत स्थापन की लागु करती है।

[सं॰ एस॰-35017/89/82-पी॰एफ॰-II]

S.O. 4034.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messra Jalan Producctions, 183|1, Dharamtolla Street, (2nd Floor), Calcutta 13, have agreed that the provisions of the Employees' provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (1° of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No.S-35017]89]82-PF.II]

का॰ आ॰ 4035.—केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बरतनाशय, 56/1, कैनिंग स्ट्रीट, कलकला-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मकारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मकारी भिवस्य निधि और प्रकीण उपवन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा ३ की उपवारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धर्षिनियम के उपवक्ष उक्त क्यार्यन की लागु करती है।

[सं॰ एस॰-35017/94-/82-पः॰एफ॰-II]

S.O. 4035.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Baratanalaya 56[1, Canning Street, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017/94/82-PF.II]

का ब्ला 4036.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुमार एजेर्स्सस, 1/4, डी० खामेन्द्र बटर्जी रीड, कोसीपुर, कलकला-2 जिमके प्रत्नार्गत 16 इंडिया एक्सचेज प्लेस कलकला-1 स्थित इसका मुख्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य मिश्रि भीर प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के जपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहुग्ये;

धतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की अपधारा (4) द्वारा प्रवत्त गमितयों का प्रयोग करने हुए, उक्त धिधिनियम के उपजन्ध उक्त स्थापन को सागू करती है।

[सं॰ एस॰-35017/110/82-पी॰एफ॰-II]

S.O. 4036.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messra Kumar Agencies, 1/4-D, Khagendra Chatterjee Road, Cossipore Calcutta-2 including its Head Office at 16, India Exchange Place, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35017/110/82-PF.II]

कांश्या 4037.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससे सिस्वर क्लोस्टोबम (प्राइबेट) लिमिटेड, सी०-101, हिन्द मीराष्ट्र इंडस्ट्रियल एस्टेट) ग्रंधेरी कुर्ला रीड, मुम्बई-59 जिसके भ्रन्तगैत 95 साबेरी बाजार कालबादेवी रीड मुम्बई-2 स्थित इसका रिकर्ट्र इस कार्यालय भी है नामक स्थापन से सावझ नियोजक गौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बान पर महमन हो गई है कि कर्मचारी प्रविध्य निधि भीर प्रकीण उपबन्ध मधिनियम, 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उकत स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः केन्द्रीय नरकार, उकन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपगच्य उकत स्थापन को लागु करता है।

[स॰ एस॰-35018/57/82-पी॰एक॰-II]

S.O. 4037.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mesus Silver Plastochem (Private) Limited, C-101, Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Bombay-59 including its Registered Office at 95, Zaveri Bazar, Kalbadevi Road, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/57/82-PF.II]

काल्या व 4038.—केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुनावला धाईस फैन्ट्री, 188, लेभिगटन रोड, सिनर्वा सिनेमा के पीछे. मुम्बई-4 ब्रोर उनके 35-सी जेराईभोय स्ट्रीट, म्मूनिसिपल बकंशाप के पास, फीरस रोड, मुम्बई-8 स्थित कार्यालय सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भौर कर्मजारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मजारी भविष्य निधि भौर प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने जाहियें;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त भिवित्यम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मित्रयों का प्रयोग करते हुए, उक्त ग्रिधितियम के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[सं॰ एस॰-35018/58/82-पी॰एफ॰-II]

S.O. 4038.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sunawalla Ice Factory, 188, Lamington Road, Behind Minerva Cinema, Bombay-4, including its office at 35/C, Jeraijbhoy Street, Near Municipal Workshop, Foras Road, Bombay-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the sald establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conerred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/58/82-PF.II]

का॰ 4039.---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि गैसर्स धार्बनेंस फैक्टरी एम्प्लाइन करुपूमर्स को-प्रापरेटिव सोमाइडी लिमिटेड, धार्डमेंस फैक्टरी एस्टेट, वरणगांव, जिला जलगांव, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक धीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस धान पर सहमत ही गई है कि कर्मचारी शंबच्य निधि धीर प्रकीण उपबन्ध धीयनियम, 1952 (1952 का 19) ने उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त मधिनियम के उपबक्त उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰एस॰-35018/65/82-पी॰एफ॰-]]]

S.O. 4039.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ordnance Factory Employees Consumers Co-operative Society Limited, Ordnance Factory Estate, Varangaon, District Jalgaon, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/65/82-PF.II]

ं नगा अरा ० 4040. --- केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीस होता है कि मैसर्स हुवं प्रिटरा, 122, डा-मगाहरा रोड, सर्वोदय केन्द्र बिल्डिंग, मुम्बई-9, मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुमंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी कविष्य निधि और प्रकार्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उपस स्थापन को जागू किये जाने चाहियें;

भत. केन्द्र य सरकार , उवत श्रिधिनियम की धारा 1 की उपघारा (4) द्वारा प्रदक्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए, उवत भौधीनयम के उपयन्ध उवत स्थायन को लागु करती है।

सिं॰ एस॰-35018/66/82-पी॰ एफ॰-Iा]

S.O. 4040.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Harsha Printery, 122, Dr. Meisheri Road, Sarvodava Kendra Building, Bombay-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

INo. S-35018/66/82-PF.III

का आ 4041. के वि सर्मार की यह प्रतंत होता है कि मैससं पटेल मिन्येंटिक यानं (पाइबेट) लिमिटेड, मिसल एस्टेंट सं० 2, गाला सं० 6 और 10, प्रीपेरी-कुर्ला रोड, मुम्बई-59, जिसके प्रत्तांत चोकसे चैम्बर्स, 117, मान्येरी बाजार, मुम्बई-2 स्थित इसका मुख्यालय में है। नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों का बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी अधिरंग निर्धि और प्रकंणे उपबन्ध प्रधिनयम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन का लागू किये जाने चाहियें,

ष्ट्रत केन्द्र य सरकार, उक्त प्रधिनियम क धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त प्रक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागु करती है।

[स॰ एस॰-35018/68/82-र्पः ०एफ०-_1]

S.O. 4041.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messis Patel Synthetic Yarn (Private) Limited, Mittal Etate No. 2, Gala No. 6 and 10, Andheri-Kurla Road, Bombay-59 including its Head Office at Choksey Chambers, 117, Zaveri Bazar. Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act. the Central Government her-by applies the provisions of the said act to the said establishment.

INo. S-35018/68/82-PF.III

का० आ० 4042 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीस होसा है कि मैरासे मनीकान मलक नत्व, 11वी मंजिल, राहेजा चेम्बर्ग, निरमन पाइंट, मस्बर्ध-21 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक ग्रीर कर्मेणारियो की बहु-संख्या इस बात पर गहमत हो गई है कि कर्मेणारी प्रविद्य निधि ग्रीर-प्रकीर्ण उपबन्ध ग्रीधिन्यम, 1952 (1052 का 19) के उपबन्ध एक्ट स्यापण की लागू किए जाने चाहिएं: कतः केन्द्रीय सरकार, एक किंधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त पक्तियों का प्रयाग करते हुए, उक्त प्रिधिनियम के उपवन्ध एक स्थापन की लागु करती है।

[सं॰ एस-35018/56/82-पो॰एफ॰-II]

S.O. 4042.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Manilal Talakchand, 11th Floor, Reheja Chambers, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment,

[No. S-35018/56/82-PF.II]

का० आ० 4043.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससे लक्ष्मी फाइनेंस, 3-6-140/5-सी, हिमायस नगर, हैक्राबाद-29. नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि वर्मचारी 'विष्ण निधि भीर प्रकीण उपबच्ध ध्रक्षि-निथम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू किए जाने बाहिए,

भत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की बारा 1 की उपधारा(4) द्वारा प्रदत्त माक्तियों की प्रयाप करते हुए, उक्त प्रधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[सं० एस-35019/197/82-पी०एफ-[I]

S.O. 4043.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lakshmi Finance, 3-6-140/5C, Himayat Nagar, Hyderabad-29, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35018/197/82-PF.III

भाव आव 4044. --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससे वेंस्केटश्वर एवं के मकल्य एण्ड भिनग्रस (प्राह्मवेट) लिमिटेड, इंजीनियरिय डिविजन, प्लाट सव 3-बी, इंडिस्ट्रियल एस्टेट, ग्रम्बाट्र, महास-98, नामक स्थाय से सम्बद्ध नियाजक और कर्मचितियों की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अवध्य नियाज प्रतिय और प्रकीर्ण उपवन्य अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्य उक्त स्थापन की लागू किए जाने चाहिर्;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रक्षिणियमं की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त एक्तियों की प्रयाग करने हुए, उक्त श्रीधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन की साम् करती है।

[सं॰ एम-35019/185/82-पी॰एफ-I]]

S.O. 4044.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mcssrs Venkateswara Agro Chemicals and Minerals (Private) Limited, Ingineering Division, Plot No. 3-B, Industrial Estate, Ambattur, Madras-98, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019/185/82-PF.II]

का० आ 4045 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० श्रीनिवास भट्ट एण्ड वास्पनी, कोट्टकुलम राड, कोचीन-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भीर कमंत्रारियों की बहुसंख्या हस बात पर सहमत हो गई है कि कमंत्रारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपवन्ध श्रक्षिन्म, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त स्थापन की लागू किए जाने वाहिए;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त मिन्नियम के उपवन्ध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[स॰ एस-35019/186/82-पी॰एफ-2]

S.O. 4045.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. Srintvasa Bhat and Company, Kettukulam Road, Cochin-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

INo. S-35019/186/82-PF.III

का॰ आ॰ 4046 ---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैससें श्री विजय इंडस्ट्रीअ, धनाट सं॰ 19, आई॰डी॰ए॰ पत्तनेनेक मेडक जिला, आन्ध्र प्रदेश, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियंजिक और कर्मनात्यों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मनारी विवय निश्च और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त भविनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मक्तियों को प्रयोग करते मुण्, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[सं० एस-3 5 र्र 1 9 | 1 8 7 | 8 2-पी ० एफ- 2]

S.O. 4046.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sri Vijaya Industries, Plot No. 19, I.D.A., Pathancheru, Medak District, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35010/187/82-PF.II]

का० आ० 4047.-- केन्द्रीय सरकार की यह प्रसीत होसा है कि भैसर्स मुनल महल रेस्तरां, सेठी भवन, राजेन्द्र ज्येस, नई विल्ली-8 नामक स्थापन से सभ्बद्ध नियोजक भीर कर्नवारियों की बहुमंख्या इस बात पर सहसत हा गई है कि वर्मवारी भिवष्य निधि भीर प्रकीण उपबंध भिवित्यम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उनते स्थापन को लागू किए आते वाहिए ;

मतः केन्द्रीय सरकार, उपत प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदस्त प्रक्तियों का प्रयोग करते द्वुए, उक्त प्रधिनियम कें उपयोग जन्म स्थापन को लागू करती हैं।

[सं॰ एन-38019/195/82-यी॰ एफ॰-2]

S.O. 4047.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mughal Mahal Restaurant, Sethi Bhavan, Rajendra Place, New Delhi-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]195[82-PE. II]

का० आ० 4048.-- केन्द्रीय संग्कार की यह प्रतीस है कि भैगर्स श्रीवाकुलम गर्वनेमेंट एम्प्याइज, बी-प्रापरेटिव स्टेमें लिसिटेड, श्रीकाकुलम (ग्रान्ध्र पदेण), सम्भ स्थापः से सम्बद्ध विषाण, ग्रीर कर्मबारियों की बहुनेवा इस बात पर सहमन हो गई है कि कर्नेबार न्थिय निधि ग्रीर प्रकीण उपबंध प्रजितियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन का लागू किए जाने चाहिएं;

भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधितियम की धारा । की उपधारी (4) द्वारा प्रदक्त प्रकितयों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रधितियम के उपधार उक्त स्थापन की लागू करती है।

[मं॰ [म-35019/196/82पा॰ [फ॰ t]

S.O. 4048.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Srikakulam Government Employees Co-operative Stores Limited Srikakulam (Andhra Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]196[82-PF. II]

का० आ० 4049.--केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि
गैसर्न भेल्स एफ सिंतरा, ग्रार० एन० वर्नाड बिल्डिश, उदीर्थ 576101
जिना यान।रा'कनीत्म, नामक स्थापन से सम्बद्ध, नियाजक ग्रीर कंमेपारियों की बहुसंख्या इस आत पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अधिध्य
निधि ग्रीर प्रकीर्ण उन्बंध ग्रीधिनयम, 1952 (1952 पा 19) के उप
यंत्र उक्त थापन की लागू किए जाने चिहिए;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, जन्न श्रीधनिय की-घारा 1- की उपधारा, (4) हारा प्रदक्त प्रतितयों का प्रयोग करते हु,ए, उक्त श्रीधनियम के उपबंध उक्त स्थापन को सागू करती है।

[सं॰ एस-35019/199/82-पी॰ एफ॰2]

S.O. 4049.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sales and Service, R. M. Karnad Building, Udupi-576101, District Kannada, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]199[82-PF. II]

का० आ० 4050.---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भैसर्स धौकर इडिया धार्क एंड भैसर्स बैस्टिंग वर्क्स, 18, कोन्नूर हाई रोड, भद्रास-23, नामक स्थापन से सभ्यद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अविष्य निधि धौर प्रकीर्ण उपवंध धौधनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवंध उस्त स्थापन को लगा किए आने चाहिए;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवस्त शक्तियो या प्रयोग करते हुए, उक्त मर्धिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एस-35019/204/82-पी॰ एफ॰-2]

8.0. 4050.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Our India Are and Gas Welding Works, 18, Konnur High Road, Madras-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]204]82-PF. II]

का० आ० 4051.-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हीता है कि भैसर्स विशास बदर्स, कोबला फी ट्रेंड जीन, गोसी घाम (कच्छ.) जिसके इंतर्गत 509, वर्कगेट चैम्बर्स-5, न्यू मेरीन लाइका, मुस्वई-20 स्थित इसकी गाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध, नियोजक प्रौर-कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भिवया निधि प्रौर प्रकीर्ण उपबंध श्रिधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध, उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

श्रतः भेत्य्रीय -सरकार, उन्त श्रीधितयम -की धारा 1 की उपधारा (4)-श्रारा प्रवस्त गन्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त श्रीधितियम के उपबंज उन्त स्थालन को खागू करती है।

[ग० एस-35019/205/82-गी० एफ०-2]

8.0. 4051.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Milak Brothers, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham (Kutch) including its branch at 509, Churchgate Chambers, 5, New Marine Lines, Bombay-20, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]205]82-PF, II]

का बार 4052, — के जीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैससे एक्सप्रेस प्राप्तेस एक्सप्रेस, 4/1, कीर्तिकार, जीबोपिक सेंब, नई दिल्ली-15, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मकारियों की बहुसंक्या इस बान पर सहमत हो गई है कि कर्मकारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपर्धं भिष्यिम्यम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागृ किए जाने चाहिए;

मतः केन्द्रीय सरकार उन्त मधिनियम की घारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवंत मिनतयों का प्रयोग करते हुए, उन्त अधिनियम के उपवन्त उन्त स्थापन की लाम करती है।

सि॰ एस॰-35019/210/82-पी॰एफ॰-2]

S.O. 4052.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Express Process Engravers, 4|1, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi-15, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]210/82-PF. II]

काल्ला॰ 4053.—केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि मैससे यूनिसन इंजीनियसे 7/27 कीर्तिनगर भौधोगिक क्षेत्र नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्नचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्नचारी स्विध्य निश्चि और प्रकीण उपवंध ब्रिश्चियम 1952 (1952 को 19) के उनवन्ध उक्त स्थान को लागू किए जाने वाहिए;

अतः केन्द्रीय संस्कार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एम-35019/211/82-पी एफ-2]

S.O. 4053.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Unison Engineers, 7|27, Kirti Nagar, Industrial Area, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]211]82-PF. III

का० आ० 4054.—केन्द्रीय भरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रभात किरण पसैट मोतसं एसोसिएणन प्रमात किरण 17 ्रजेन्द्र प्लेस नई विल्ली-8 जितके मंतर्गंत इसके दो मूक्टि अवांत् बीप शिका पसैट भोनसं एसोसिएणन मोर कॉर्लि महल एसैट मोनसं 17 राजेन्द्र प्लेस नई विल्ली भी है नामक स्थान से सम्बंध कियोजक मौर कर्मवािभी की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मवारी गविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबच्च मिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उन्ह स्थापन को भागू किए जाने चाहिए;

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 1 की उपचारा (4) द्वारा प्रवस स्वितयों का प्रयोग करते हुए उक्त पिधिनियम के उपवस्य एक्त स्थापण को नागू नारती है।

[मं॰ एम॰ 35019/212/82-पो॰एफ॰-2]

S.D. 4054.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mossrs Prabhat Kiran Flatowners Association, Prabhat Kiran, 17, Rajindra Place, New Delhi-8 including its two units namely Deep Shikha Flatowners Association and Kirti Mahal Flatowners, 17, Rajindra Place, New Delhi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

[No. S-35019]212[82-PF, II]

का० आर० 4055---केम्ब्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कावेरी कन्टेनर्स (प्राइवेट) निमिटेड वी /12-13/जय भारत इंडिस्ट्रियल एस्टेट जलहामी कैम्परोड यंग्रावंतपुर बंगलीर-22 नामक रबायन से सम्बद्ध नियोजक गौर कर्मबारियों की बहुमंत्रत इस बात पर मह्नन हो गई है कि कर्मबारी मिश्रिय निधि भीर प्रकीण उपवन्ध प्रधिनियस 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध जनन स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त मिश्रिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त मिश्रितयों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधिनियम के उपकल्ध उक्त स्थापन की लागू करती है।

[स॰ एस॰-35019/213/82-पी एफ-II]

S.O. 4055.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cauvery Containers (Private) Limited, B, 12-13, Jai Bharat Industrial Estate, Jalahalli Camp Road, Yeswanthur, Bangalore-22, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]213]82-PF. II]

का०आ। 4056.— किशीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री बालामी माइन राइम मिल, 27, रेलवे स्टेशन रोड, मिरफाली,तिमल माबु, लामक स्थापन से सम्बद्ध निधीजक भीर कर्मचारयों की वह संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि सर्मचारी भिष्ठिय निवि भीर प्रकीण उपवन्ध मधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उका प्रक्षितियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त गवितयों का प्रयोग करते द्वुए, उक्त प्रक्षितियम के उपबक्ष्य उक्त स्थापन की लागु करती है।

[रॉ॰ एग॰-35019/221/82-पी॰एफ॰-II]

S.O. 4056.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Balaji Modern Rice Mill, 27, Railway Station Road, Sirkali, Tamil Nadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]221'82-PF. II]

कां बां 4057.--केक्ट्रीय सरकार को यह प्रतात होता है कि मैसर्स गांधीगंज प्राइमरी को प्रापरेटिक बैंग लिमिटेड, गांधी गंग, बोदार, कर्नाटज, मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोज र ग्रीर कर्म निर्देश की बहुनंद्र्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मबारी भिक्तिय निश्चि ग्रीर प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 जा 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने बाहिए;

मत नेन्द्रीय सरकार, उन्न प्रधिनियम की प्रारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त प्रकियों का प्रयोग करने हुए, उना प्रधिनियम के उपबन्ध उन्त स्थापन की लागू करती है।

[म ॰ एम ॰ - 35019/232/82-पी॰ एफ ॰ -II]

8.0. 4057.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messre The Gandhi Gunj Primary Co-operative Bank Limited, Gandhi Gunj, Bidar, Karnataka, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]232[82-PF. II]

का बा 4058. — केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होगा है कि मैसर्स इंटेगरेटिड प्रासेस प्राटोमेणन (प्राइवेट) लिमिटेड, ए-173 फर्स्ट फेंब, फोर्च काम, पीनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट, बंगलीर-58 जिसके अन्तर्गत वार्ड सं 16, कासरीडीह, धानी भवन के सामने, दुर्ग-1, मध्य प्रदेश स्थित इसकी बाल्बा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक थीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी अविषय निधि और प्रकीण उपवन्त अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपवन्त उमत स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

भतः केन्द्रीय भरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 1 की उपघारा (4) द्वारा प्रदत्त णिनयों का प्रयोग करने हुए, उक्त श्रीधनियम के उप-बंध उक्त स्थापन को सागु करती है।

[सं॰ एग॰-35019/231/82-पी॰एक॰-II]

S.O. 4058.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs integrated Process Automation (Private) Limited, A-173, 1st Phase, 4th Cross, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58 including its branch at Ward No. 16, Kasaridih, Opposite Dhani Bhavan, Durg-1, Madhya Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees' Povident Funds and Miscel-Integrated Process Automation (Private) Limited, A-173, applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]233]82-PF. II]

कां आं 4059. -- वेस्क्रीय सरकार को यह प्रती १ होता है कि मैसर्स रोमर फैशन्स, 2, इराबालू चेट्ट स्ट्रीट, पहली मंजिल, महाम-1, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक भीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि यमंचारी भविष्य निधि भीर प्रकीण उपवन्ध मिध-नियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्राधिनियम की द्यारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त गर्कितयों का प्रयोग करने हुए, उक्त ग्राधिनियम के उपयन्त्र उक्त स्थापन की लागू करती है।

[सं० एस-35019/334/83-पी:०एफ ०-II]

S.O. 4059.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Romar Fashions, 2, Errabalu Chetty Street, 1st Floor, Madias-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-ection (4) of Section 1 of the said Act, the Contral Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]234[82-PF. II]

का॰ जा॰ 4060. - किस्त्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसमें जनरल काममें लिमिटेड, 102, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली-1 जिसके अन्तर्गत 50/2-3 हनुमान रोड, नई दिल्ली-1 स्थित ध्राकी खाखा भी है, मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कमैं वारियो की बहुसँख्या इस बास पर सहमत हो गई है कि कमैं वारी मिविष्य निधि और प्रकीण उप-बंध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिएं,

म्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रक्षितियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त प्रधितियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं॰ एस-35019/236/82-पी॰एफ॰-II]

ए०के० भट्टाराई, प्रवर सचिव

S.O. 4060.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs General Commerce Limited, 102, Bangla Sahib Road, New Delhi-1 including its brench at 50|2-3, Human Road, New Delhi-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019]236[82-PF. II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई विल्ली, 11 मवम्बर, 1982

का॰ का॰ 4061. - केलीय सरकार, त्यूनतम मजदूरी ग्राधितयम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रवत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतवहारा उन्न अक्षितियम की अनुसूची के भाग-1 में मैगनेटाइट खानों का नियोजन जोड़नी है जिसे जोड़ने के संबंध में वह भारत के राजपल धमाधारण, दिनीक 14 मई, 1982 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाणित भारत गरकार के मूनपूर्व अम मंद्रालय की अधिसूचना सं० का॰ धाद 320(प) दिनांक 14 मई, 1982 द्वारा प्रपने धामय की सूचना पहले दी जा चुकी है।

[स॰ एम॰-32017/2/81-डब्स्यू सी (एम॰ डब्स्यू॰)] एम॰एल॰ मेहना, धवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 1982

S.O. 4061.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby adds to Part I of the Schedule to that Act, the employment in Magnetite mines, notice of its intention to do so having already been given, by the notification of Government of India in the late Ministry of Labour number S. O. 320 (E) dated the 14th May, 1982 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 14th May, 1982 as required by the said section.

[No. S-32017|2|81-WC(MW)] M. L. MEHTA, Under Secy. मई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1982

भाराजार 4082.--मैसर्स धन्नः द्रासपोर्ट कारपोरोगन विभिन्देड, मंत्र 12, नामक्रव्य रोड, सलीम-7 टी० भनं/7480, (जिमे इसमें इसके पश्चात उक्स स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीर्ण उपवश्च अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चास उक्त क्रिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिन जाने के लिए आवेदन किया है;

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निशम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मवारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निजेर महब्ब बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इमनें इनके परवात उनन म्कीम कहा गरा है) के अधीन उन्हें अनुजीय हैं;

श्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उरधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावक अनुसूची में विनिर्देष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की प्रविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवक्षों के प्रवर्तन से छूट देवी है।

अनुसुकी

- ा. उक्न स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक मिल्य निश्चित्रामुक्त, तिमलनाडु की ऐसी विवरणियां भेडेगा और ऐसे तेवा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेंगा जो केन्द्रीय संरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2 नियोज क, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाध्ति कि 15 दिन के भीतर सदाय करेशा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खड़ (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके धन्तर्गत लेखाओं का रखा आना, विकरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, नेव्याओं का धंसरण, निरीक्षण प्रधारों का संदाय ग्रादि भी है, होने वाले सभी व्यायों का कहन नियोजक द्वारा किया आएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमीदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, प्रौर जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, सब उस संगोधन की प्रति स्था कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुषाय, स्थापन के सुखना पट्ट पर प्रयोगत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी मिवय निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की मिवय निधि का पहिल ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है ती, नियोजिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुरन्त वर्ष करेगा ग्रीर उसकी बाबत प्राययक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निश्य को संवत्त करेगा।
- 6. यदि उन्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाएं जाते हैं ती, नियोजक सामृष्टिक बीमा स्कीम के ध्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की छाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामृष्टिक बीमा स्कीम के ध्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक ध्रनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के ध्रधीन ग्रनुकृत हैं।

- 7. सामू हक बीमा स्थीम में किसी बात के हांते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी भी मृत्यु पर इस स्थीम के ब्रधीन संदेव रकम उस एकम से कम है जो कर्मचारी को उस बणा में संदेव हाती जब वह उकत स्थीम के ब्रधीन होता सी, निर्योजक कर्मचारी के विधिक वारिस/राम निर्वेणिती को प्रतिकर के क्य में दोनों रकमों के ब्रस्तर के बरावर रकम का सबाव करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्काम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादेणिक मिल्य निश्चि प्रायुक्त, त्रिमलनाडु के पूर्व प्रमुगोदन के बिना नहीं किया आयेगा और जहा कियी संगोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रित्रकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निश्चि यायुक्त, प्रपना प्रमुगोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना वृष्टिकीण स्रष्ट करने का प्रमुगोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना वृष्टिकीण स्रष्ट करने का प्रमुगोदन प्रयसर देगा।
- 9. बिंद किसी कारणवर्ग, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय खंखन बीमा निश्म की उस सामृष्टिक बीमा एकीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपत्त चुका है प्रधीन नहीं रह आते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने बाले फायदे निसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवत्र, नियानक उस नियस तारीख के भीतर, की भारतीय जीवन बीमा नियम नियस करें, प्रीमिश्म का संदाय करने में, शसकल रहता है, और पालिसी को व्यवसन हो जाने दिया जाता है, तो छूट रदद की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमिथम के संत्राय में जिए गए किसी व्यक्ति-कम की दशा में, उन मूक सबस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसा को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त क्लीम के अन्तर्गत होंने, बीमा कार्यदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियाजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन प्राने बाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक बारिमों को बीमाकृत रकम का संबंध तत्सरता से श्रीर प्रायीन दना में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मान दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं॰ एस॰ 35014/440/82-भ०नि॰-II]

New Delhi, the 11th November, 1982

S.O. 4062.—Whereas Messrs Anna Transport Corporation Limited, No. 12, Rama Krishna Road Salem-7 (TN/7460) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu, maintain such accounts and Provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group rance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where, for any reason, the employer falls to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (440)/82-PF, II]

कांव्याव 4063.— मैंसमें शत्याई पेरियार ट्रांगपेट कारपोरेशन लिमि-टेड, 3/137, मालमेट, वालघरेड़ी पोग्ट प्राफिन, पोस्ट वाक्य नंव 56, विल्लपुरम-605602 (तिमिलनाड/8091), (िसे इनमें इसके परवण्य उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमेंचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप-बन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परकात उक्त मधिनियम कहा गया है) की आरा 17 की उपवास (2क) के अधील छूट विए जाने के लिए ग्रावेदन किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रीकदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिमा ही, भारतीय जीवन बीमा निश्म की सामृहिक बीमा स्कीम से प्रधीन जीवन बीमा के रूप में पायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के निये ये फायदे उन फायदों से श्रीधक अनुकूल हैं जो वर्मचारी निक्षी सहस्रद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाल उक्त स्कीम कहा प्रधा है) के अधीन उन्हें श्रनुश्रेष हैं;

ग्रसः केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपधाना (2क) द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रीर इससे उपायग्र श्रमुसूत्री में विभिद्धित गतौ के प्रधीन रहते हुए, उस्त स्थान की तीन वर्ष की प्रज्ञीय लिए उना स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से कृट किया है।

अनुसूची

- कि इक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोज के प्रावेशिक भविष्य निर्धि भ्रायुक्त, तिसलाकु की ऐसी विवर्शणयां भेजना भीर ऐसे लेखा रखेना स्था निरीक्षण के लिए ऐनी मुखिसाएं प्रदान करेना जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविद्ध घरे।
- 2. नियां जक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रश्येक मात की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त यिवित्यमं की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के धर्धान समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्टीम के प्रशासन में, जिसके धन्तर्गत निखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, निखाओं का धन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय द्यादि भी है, होने वात सभी अवयों का बहन नियंजक हारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, श्रीर जन कभी उनमें मंगोधन किया बार, तथ उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा के उसकी मुख्य बातों का मनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि काई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी मविष्य निधि पर या उक्त मिर्मित्यम के प्रधीन छुट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है तो, नियाजिक साम्हित बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरस्त दर्श करेगा और उसकी बाबल प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम की संदर्श करेगा।
- 6 यदि उस्त महीन में मधीत कर्मनारियों की उपलब्ध फायदे बढाये आते हैं तो, नियंत्रक सामृहिक बीमा महीम के मधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फाउदों में समृज्ञित रूप से बृद्धि की जाने की बायस्था करेगा जिसमें कि वर्मनारियों के गिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उस फाउदों से अभिक अनुष्ल हों. की उपल स्कीम के प्रधीन अनुजेय हैं।
- 7. सामृश्चिम बीमा करीम में किसी बाद के होते हुए भी, यदि किसी कामैवारी की मृत्यु पर इस स्काम के अधीन सन्देय रकम उस रकम में बाम है, जो कर्मवारी की एम दशा में सदेय होती जाय बहु उसत लीम के अधीन होता तो, नियाबक कर्मनार्थ को विधिक वाण्यि[नामिव्यिमिती को प्रतिया के क्या में द्यारी के प्रतिया के क्या में द्यारी के क्या में क्या में द्यारी के क्या में क्या में द्यारा करेंगा।
- 8. सार्वित श्रीमा रतीन के उपतन्त्रों में गाँद भी मंगीतन, प्राद्दिणक मिष्टिक निधि प्रायुक्त समितनाडु के पूर्व शनुमोक्त के विना मही किया जातुका और अहा किसी संशोधा से कर्मवर्गियों के हित पर प्रसिक्त

- प्रभाव पड़ने की संभावन। हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त, भपने। अनुभोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को धपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मुक्तियुक्त अपसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवा, स्थापन के कर्मजारी, भारतीय जीवन कीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पड़ी प्रथम जुना है भश्रीन मही यह जाते हैं, या इस महीम के श्रीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से क्षम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जासानी है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रिमियम का मंदाय करने में असकल रहता है, और पालियी को अपयान ही जाने दिया जाता है तो, छुट रह की जासकती है।
- 1. नियांत्रक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिका की दशा में छन मृत सबस्यों के नाम निर्देशिक्षियों या विधिक वाश्मिं को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदी के संदाय का उत्तरवायित्व नियांजक पर होगा।
- 12 उकत स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के बधीन धानै बाके किसी साइस्व भी मृत्यु हुंनि पर उसके हुकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाव तत्परता से भीर प्रत्येक दणा में भारतिय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिधिकन करेगा।

[संख्या एस-35014/383/82-पी ०एफ०-II]

S.O. 4063.—Whereas Messrs Thanthai Periyar Transport Corporation Limited, 3/137, Salamedu, Valudhareddy Post Office, Post Box No. 56, Villupuram-605602, (TN/8094) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourarble to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenace of accounts, submission of returns, payment of insurace premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Croup Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, it the bentfits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme
- 7. Nowithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an empolyee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a teasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any réason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc, within the due date, as fixed by the 1 ife Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (383)/82-PF, 11]

सा० आ० 4064—.मैसर्य पांडियान रोडवेज कारपोरेशन लिमिटेड, वार्ड पास रोड, सबुरी-625016 (टी एम/6882) (जिसे इसमें इसके पण्यान् उक्त स्थापन कहा गया है) ने वर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपवन्ध प्रधिनियम 1952 (1952 का 19), जिससे इसमें इसके पण्यात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपवारा (2क) के प्रधीन छट दिए जाने के लिए श्रावेदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मकारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन कीमा निशम की मामृहिक कीमा स्कीम के अधीन कीवन कीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे वर्मकारियों के लिए में फायदे उत्त फायदों में प्रधिकानुकूलन है जो कर्मकारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इससे इनके पण्कान् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभेय है;

ग्रन', केरद्रीय सरकार, उक्त भ्रधिनियम की धारा 17 की उपकारा (2क) इत्या प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग कारते हुए ग्रोर इससे उपावक प्रनुम्बी में विनिर्दिष्ट णतों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापनी को तीन वर्ष की प्रविधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन में खूट देती है।

धनुसूर्या

- । उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोज्ञक प्रदेशिक शिवय्य निकिक्षेत्र अपवन समिलनाडु को ऐसी विवयणिंग भेजेगा घीर ऐसे लेखा रखेगा । तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुजिधाए प्रदान करेगा जा केन्द्रीय संस्थार, समय-समय पर निरिष्ट करें।
- ए नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय-पर निदिष्ट करें।
- 3 सामृहित बीना स्काम के प्रभामन में, जिसके ग्रन्तर्गन लेखाओं का प्रमान का नामा, जाना विवरणायों ना प्रमान किया जाना, बीमा प्रीमियम का नाबाय, लेखान्ना का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों के मंदाय श्रादि भी हैं, होने वाले सभी क्यां का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 3 नियोजक, केन्द्रीय गरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामहिक बीमा स्कीम के नियमी की एक प्रति, और जब कभी उनमें संगीधन किया जाए, तम उस संगीधन की प्रति तथा कर्मवारियों की बहुसख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का ग्रानुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदेशित करेगा।
- उन्दिकोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य सिधि का या उन्त प्रधितिश्य के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य तिथि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है तो, तियाजक सामृहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप मे उसका नाम तुरल्य वर्ज करेगा ग्रीर उसकी बाबत ग्रावण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सबस परेता।
- 6 यदि जनत स्कीम के प्रधीन कमंचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाएं जाते हैं ती, नियोज्ञक सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कमंचारियों को उपलब्ध फायदों में ममुचित रूप से बुद्धि की जाने की ब्यवस्था करेगा अससे कि कमंचारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उस फायदों से श्रीक्षक अनुकृत हो, जो जनत स्कीम के श्रधीन मनुक्रेय है।
- 7 साम्हिक बीमा स्कीम में किसी बाल के होते हुए भी पदि किसी व मंजारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मन्देग रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दणा में सदेश होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देणिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमी के अस्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा।
- श मामृतिक कीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भावच्य निधि प्रायुक्त तिमलनाडु के पूर्व प्रमुभोवन के बिना नहीं किया आएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की सभावना हो बहां प्रादेशिक भविच्य निधि घासुका, अपना प्रमुखेद देने से पूर्व कर्मचारियों को घपना पुष्टिकोण स्पष्ट करमें का युक्तियुक्त अवसर हेगा।
- 9 यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय बीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं पत्र जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवण, नियोजक उस निधन तारीख के भीनर, को भारमीय जीवन भीमा निधम निधन करे प्रीमिधम का संदाय करने में भस्कल रहना है, भीर पालिसी को रूपगत हो जाने दिया जाना है तो छट पह की जा मकती?

1001 G of 1/82---6

- 11. नियोजक द्वारा प्रीमिम्स के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्षा जिला में उस मृत सबस्यों के नामनिद्धितियों या विधिक वारियों की जी शिव सह छूट ल दी गई होती ती उक्त स्कीम के झंदरीत होते, बीमा फायधों के संवाय का उत्तरवाधित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्वापन के संबंध में निर्याजक, इस स्कीम के अधीन प्राने वाले किसी सदस्य की मृत्युं हुँनि पर उसके हक बार नाम निर्देणितियों विश्विक वारिसों की बीसाकुत रक्षम का संवाय तरपरना से भीर प्रत्येक दशा में भागतीय जीवन बीमा विश्वम से भीमाकुत रक्षम प्रान्त होने के साल दिन के भीनर सुनिध्यिश करेगा।

[संख्या एस 35014/278/82-पी•एफ II]

S.O. 4064.—Whereas Messis Pandiyan Roadways Corporation Limited, Bye Pass, Road, Madurai-625016 (TN/6882) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that

- would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment scheme do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(278)/82 PF. II]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 1982

का अा 4065. मैसर्सम पैकी इलैक्ट्रोसिक्स एण्ड इलैक्ट्रिक्ट्रस लिमिटेइ, 7154, प्रकासलाई, मदास (टी०एन० 3072) (जिसे इसमें इसके पश्चान उत्तर स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भित्रप्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम 1052 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चान उत्तर अधिनियम कहा गया है) को धारा 17की उपधारा (2क) के स्रधीन छूट दिए जोने के लिए भावेदन किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का संसाधान हो गया है कि उतन स्थापन के कर्मवारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, धारतीय जीवन बीमा निगम की सामृद्धिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहें है भीर ऐसे कर्मवारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधि अनुकूल है जो वर्मवारी निभेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चास उकत स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें अनकीय हैं

धन, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रक्षित्यम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध धनुसूची में विनिविष्ट शर्तों के श्रक्षंत रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के राभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि
ग्रायुक्त तमिलनाह को ऐसी विवर्गणया भीजेगा श्रीर ऐसे लेखा रखेगा तथा
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार,
समय-समय पर सिदिन्ट करें।

- 2 नियोजक, ऐसे निरंक्षण प्रभारों का प्रत्येष मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उनत श्रीवित्यम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के श्रधीन समय-समय पर निदिष्ट करें।
- 3. मामूहिक वीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा प्रीमयम क. संदाय, लेखाओं का प्रश्नरण निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रादि भी है, होने वाले सभी ब्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार धारा यथा धनुमोदित मामूहिक वैमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, श्रीर जब कभी उनमें समोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति स्थाकर्मचारियों की बहुसच्य, की भाषा में उसकी मुक्ष्य बातों का धनुबाद स्थापन के सूचना पष्ट्र पर प्रविधित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त मधिनियम के मधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की शविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप से उसका नाम तुशस्य वर्ज करेगा और उसकी बाबन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन कीमा निमा को संदत्त करेगा।
- 6 यदि उसन स्कीम के प्रजीत कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाने हैं तो, नियंजिक साभृष्ठिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मेजारियां की उपलब्ध फायदों में ममुजित रूप से युद्धि की जाने की व्यवस्था करेंग जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामुष्ठिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदों उन कायदों से प्रधिक अनुबूल हो, जो उसत स्वीम के प्रधीन अनुकेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए थी, यदि किसी कर्मजारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय रक्तम उस रक्तम से अम है, जो कर्मजारी को उस घणा में सदेय होती, जब वह उपत स्कीम के अधीन होता, नियंजिक कर्मजारी के विधिक वारिस/नामनिवेशिनि को प्रतिकर के उप में बोनो रक्तमों के धन्तर के बराबर रक्तम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भिष्य निधि प्रायुक्त तमिलनाकु के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा भीर जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत्व प्रभाव पड़ने की सभावना हो वहां, प्रावेशिक भिवष्य निधि धायुक्त, भपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर येगा।
- 9. यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले मपना चुका है मधीन नहीं रह जाने है, या इस स्कीम के मधीन कर्मचारियों को ब्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं. तो यह छूठ रह की जा सकती है।
- 10- यदि किसी कारणवस, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रसक्त रहता है, ग्रीर पालिमी की व्यपगत हो जाने दिया जाता हैती, छूट रह की जा मकती पर हैं।
- 11. नियोजिक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सबस्यों के नामनिवेशियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट नदी गई होती तो उक्त स्कीम के संतर्गत होते, बीमा फायशों के सवाय का उत्तरवायित्व निवोजिक पर होगा।
- 12 उनन स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के झधीन झाने बाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिनियों/

विधिक पारिसो की सी.माक्कन २७म का संदाय तरपरता **से क्षीए प्रत्येक** दशा में भारतिय जीवन कीमा निगम से वी.माक्कस रकम जाप्त हीने के सास दिम के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्यः एस० 35014/87/82-पी०एफ-2]

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 4065.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals 1td., Philips, 154, Anna Salai, Madras-600002 (TN/3072) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nautre of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, I amil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be hable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insulance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer,
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

INo. S-35014(87)/82-PF, III

का अभा ० 4066.— सैसमं की सेन्ट बाइज एण्ड की सकत्म लिसिटेब, को सेन्ट हाउस, बेलार्ड एम्टेट, बम्बर्ड (महा/1108) (जिसे इसमें इसके पण्नात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें क्रमके पश्चान अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भिन्न सुट विष् जाने के लिए आयेदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायरे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायरे उन फायदों में प्रधिकानुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उकत स्कीम कहा गया है) के बधीन उन्हें भनुजेय है,

धतः केन्द्रीय गरकार, उक्त श्रिधिनियम की धारा 17 की उपघारा (2क) हारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करने हुए भीर इससे उपाबद्ध भनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के ग्रधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भनिध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से भूट देशी है।

अनुसूची

- ३. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोगक प्रावेशिक भविष्य निधि भागुमन महाराष्ट्र का ऐसी विवर्णियां भेजेगा प्रौरऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के सिएऐसी मुलिझाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीमर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रश्चिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निविध्ट करें।
- 3. स(मृह्फि बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके घन्तर्गत लेखाओं का प्रखा जीना विवरणिया का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का सबाम, लेखाओं का घन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मंदाय आदि भी है, होने काले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

- 4. नियोजक, केल्डीय सरकार झारा यथा झनुमोदित साभृतिक कीमा रकीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें सशोधन किया जाए, तब उस सभोधन की प्रति सथा कर्मचारिया की बहुसंख्या की भाषा में , उसकी मुद्रय बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पद्र पर प्रविणित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मजारी, जो कर्मजारी भविषय निधि का या उक्त मधिनियम के मधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके रथापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक विभा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा। और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की सदस्य करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बहाग् जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृजित रूप से दृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए मासूहिक श्रीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रक्षिक प्रनृक्ल हो, जो उक्त स्कीम के ग्रधीन प्रमृक्षेय है।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हाते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रकम के कम है, जो क चारी को उस दणा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्दणिनी का प्रतिकर के रूप में दोनो रकमा के अन्तर के स्थानर रकम का सदाय करेगा।
- 8. सामृहिक डीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त सहाराष्ट्र के पूर्व प्रनुमीवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की संभावना हो, बहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, भवना भनुमोवन देन से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवसर वैंगा।
- 4 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन शीमा निगम की उस सामृष्टिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रयना चुका है भ्रधीन नहीं रह जाने हैं या इस स्कीम के भ्रधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम ही जाने हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियाजक उस नियत तारी के के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियम करे, प्रीमियम का मंदाय करने में अभक्त रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदोय में किए गए किसी व्यक्तिक की दमा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट नदी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रतर्गत होने, बीमा फायदों के संदाय का उन्तरदायिस्व नियोजक पर होगा।
- 1.2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन प्राने काले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितयो/विधिक बारिसी की बीमाकृत रकम का सवाय तत्परता से और प्रत्येक देणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मृतिश्वित करेगा।

[संख्या एस-35014/315/82 पी०एफ०-4]

S.O. 4066.—Whereas Messis Clesent Dyes and Chemicals Limited, Cresent House, Ballard Estate, Bombay-400038 (MH/1108), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance scheme of the

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinalize referred to as the caid Scheme);

Now, therefore, in excress of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHFDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges of the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Institute Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately ented him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced. So that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Institute Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtia and white any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Groop Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as aheads adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled
- 10. Where, for any reason, the employer tails to now the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Cornoration of Iodia and the noticy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11 In ass of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal heirs of deceased members who would have been covered under the sail S hemolour for grain of this exemption, shall be that of the end loyer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Cornoration of India.

[No. \$-35014(315)/82-PF, 11]

कार आर 4067— मैससं इतेक्य इजिन वास्त्रज्ञ लिसिटेड 17-बी, हदसार इडिस्ट्रियल एस्टेट, पुणे-411013. (महा/11765) (जिसे इसमें इसके पक्षान् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कार्मकोरी भित्रप्य गिंध और प्रकीण उपवध श्रीधनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पक्षान् उक्त अग्रिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अर्धन छूट दिए जाने के लिए धानेदन किया है,

श्रीर केन्द्रिय सरकार का समाधान हो गरा है कि उन्न स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या श्रीमियन का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन कीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन वीमा के स्थाप की सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन वीमा के स्थाप फायदे उठा रहे है श्रीर ऐसे वार्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदा में अधिक अनुकृत है जो कर्मचारी निजीप सहबद्ध वीमा स्कीम 1976 (शिमें इसमें इसके प्राचान उक्त स्कीम वाहा गरा है) के अश्रीत उन्हें अनुक्रेय है,

श्रंत केन्द्रीय सरकार, उसन श्रंतिनियन की धारा 17 की उत्थारत, (2%) द्वारा प्रवत्त गॉक्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उत्तबद्ध श्रनुसूची में विनिधित्द शर्ती के श्रंतीन रहते हुए उसनस्यापन को नीन वर्ष की श्रंतिक के लिए उका स्कीम के सभी उत्विधों के प्रवर्तन में छड़ देनी है।

अनुमूचरे

- ा उक्त स्थापन के सबध में नियंजिक प्रदेशिक भविषय निश्चि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवर्णणया भेजेंगा घौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जा केन्द्रीय गरकार समय-गमय पर निष्टिष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभा के प्रत्येक भास की सन्तादन के 15 दिन के भीनर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उस्त ग्राधिन्यन की धारा 17 की उपवारा (अक) के खंड (क) के श्रधीन समय-समय पर निरिद्ध करे।
- 3 सामृहिक कीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके अन्तर्गत लेखान्ना ना रखा जाना विवर्णणयो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमेपन का संदाय, लेखान्ना का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सदाय फ्रादि भी है, होत वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय- सरकार द्वारा यता अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति, धीर जब कभी उनमें मशोधन किया जीए, तय उस संशाधन की प्रति तथा कर्मचारिया की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य यातों का प्रसुदाद, स्थापना कभूचन। यह पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 सिंद काई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी भित्रिय निश्चिका या उक्त श्रीधिनयम के श्रिजीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भित्रिय निर्धिक। पहले ही सक्षम्य है, उसके स्थापन से नियोजित किसी गाना है तो, नियोजक सासू-हिक बीसा स्कीन के सदस्य के रूप से उसार नीम तुरस्य दर्ज करेगा छीर उसकी बाबन श्रीवरूष प्रतिस्थम भारतीय जीवन बीसा निया की सदस्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्काम के अधीन कर्मचारियों को उत्लब्ध फायदे बढ़ाए जात है तो, नियोंजय सामृहित बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारयोंका उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि का जाने की व्यवस्था करेगा जितन कि कर्मचारियों के लिए सामृहित बीमा स्कीम के अधीन उत्तरित फाइदे उन फायदों में आवक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्रेय हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि विभी कार्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के धवीन मंदेय रकता उस रकता से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीन के धवीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिमानाम निर्देशिती की प्रान्तक के रूप में दोनों रकमा के अन्तर के कराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उनबंधों में कोई भी संगोधन, प्रादेशिक भावित्य निधि धायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोधन के बिना नहीं किया जीएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मकारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक भशिष्य निधि धायुक्त, धाना धनुमोदन देने से पूर्व कर्मकारिया को ध्रयना दृष्टिकोण स्वाट करने का युक्तियुक्त ध्रवस्त स्वस्त स्यस स्वस्त स्
- 9 यदि किसी कारणपण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन कीना निगम की उस सामूहिक कीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहुँच अपनी चुका है अर्धन नहीं रह जीते हैं, या इस क्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाल फायदे किसी जीति से या हो जाते हैं, तो यह छूट रद की जा सबती है।
- 10. यदि विःमी कारणवण, नियंत्रियः उस नियंत्र तरीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीभा नियन नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, घौर पालिमी को व्यवस्थत हो जाने दिया जाता है तो, छुट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियन के मंदाय में किए गए किसी व्यक्तिक की दशा में उन मृत सदस्यों के नाभनिर्देशितियों या विधिक कारिसों की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रकारी होते, बीमा कायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रवीत प्राते वाले किसी/भदस्य की मृत्यु होने पर उसके हृद्धार नाम निर्देणिनियों विधिक वारिसों की की साकृत रक्षम का संदाय तत्यरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के साव दिन के भीकर मिनिएवन करेगा।

[सं० एस-35014(313) / 82---पी ०एफ० II]

S.O. 4067.—Whereas Messrs Inex Engine Valves Limited, 17-B, Hadapsar Industrial Estate, Pune (MH/11765), theremafter referred to as the said establishment, have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enloyment of benfits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more tayourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinalter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtta, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall Jisplay on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately emol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a teasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(313)/82-PF.III

का० आ० 4068.— मैसर्स एन० जी० ई० एफ० लिमिटेड, तिईर-कीन हाऊस, डा० ई० मोसेस रोड, महालक्ष्मी, बम्बई-11 (सहा/17.509) (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मकारी मिंबड्य निधि और प्रकीण उपसंघ मधिनियस, 1952 (1952 का 19) जिपे इसमें इसके पश्चान उक्त मधिनियस कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के मधीन छूट विए जाने के लिए मांबेयन किया है;

ग्रीर केन्द्रीय संद्रकार का समाधात हो गया है कि उक्त स्थापत के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमिथम का संवाय किए जिला ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीत के अधीन जीवक बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों ने श्रीवक अनुकृत है जो कर्मछ। निक्षेप महब्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्वान् उत्तय स्कीम कहा ग्या है) के श्रवीत उन्हें अनुक्रेय है,

भतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रीविनियम की बारा 17 की उश्वार। (2क) द्वारा प्रवक्त शिक्षायों का प्रयोग करते हुए और इसने उश्वद्ध अनुसूची में किनिविष्ट शहीं के श्रीविन रहते हुए, उक्त स्थापन को नीन वर्ष की भविष्ठ के लिए उक्त स्कीभ के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूखी

- 1 जन्म स्थापन के संबंध में नियोज अविधिय भिविष्य निधि ध्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी अवरणिया भीजेगा धीर ऐसे लेखा रखेगा नया निरीक्षण के लिए ऐसी गुविधाएं प्रवान करेगा जो केरद्वीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निर्देक्षण प्रधारो का प्रस्येक माम की ममाध्यि के 15 विक के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की जाता 17 की उपधारा (3क) के अंड (क) के प्रधीन समय-नम्भ पर निविध्य करे।
- 3. मामुहिन बीम। स्कीम के प्रशासन में, जिसके घरार्गत लेखाओं का रखा जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है, होने वाने सभी कामों का रहन निर्माण हारा निया जाएता।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमोदित सामृहिक बीमा रक्षीय के नियमों की एक प्रति, धीर जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कमंचारियों की बहुतंख्या की भाषा में उसकी मुख्य ब'तो का धनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रवर्णित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी मिष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अधिष्य निधि का पहने ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक मामू-हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उमका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आध्यस्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबल करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीभ के ध्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक मामूद्रिक बीमा स्कीम के धर्मान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में ममूद्रिक रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मचारियों के लिए मामूद्रिक बीमा स्कीम के ध्रधीन उपलब्ध फायदे उस फायदों से ख्रधिक ध्रमकुल हों, जो उक्त स्कीम के घ्रधीन ध्रमुक्तिय हैं।
- 7. भामृहिक बीमा स्कीम मे किसी बार्त के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्युपर इस स्कीम के हाधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दक्षा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के हाधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसानामनिर्देणिती को प्रतिवार के रूप में दीनों रकमों के झंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. साम्हिक बीमा स्कीम के उपवेदों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व धनुमीवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां कियी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की 'भावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रवता प्रनृभोदन देने से पूर्व कर्मचारि) की प्रपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त धनमर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवम, स्वापन के नर्मचारी, भारतीय जीवन कीमा ित्रगम की उस सामृहिक कीमा स्कीम के, जिसे स्वापन पहले प्रपना चुका है

- मधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मवास्थि को आपन होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवाम, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमिथम का सदाय करने में भनकल रहता है, भीर पालिसी को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक हारा प्रींमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा मैं उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक विरमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रत्यांत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायिस्व नियोजक पर होगा।
- 12. उनन स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के शंक्षीन श्राने वाले किसी सदस्य की भृत्युकोने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/विधिक वारिसों की बीसाइन रकम का संदाय तत्यरता से श्रीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीसा निगम से वीसाइन रकम प्राप्त होने के मान दिन के भीतर मनिश्चित करेगा।

[मंक्या एस-35014] 197| 82-में ० एक-III]

S.O. 4068.—Whereas Messrs N.G.F.F. Limited, Ticericon House, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Bombay-11 (MH/17509) (heremafter reterred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in emoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident I und Commissioner, Maharashtia (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the clost of every month,
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a membel of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme

appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance. Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs 'nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtia (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shell before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefit, to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the stid Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the I ife Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(297)/82-PF. II]

का आ 0 4 06 9 - मैसर्ग इर्ज नियरिंग इण्डस्ट्रियल फीण्टी कम्पनी, मेलपालाय म रोट कोयम्बर्गर- 9 (तिसलनाड्/2.356) (जिसे इसके इसके पण्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने वसीवारी भविष्य निश्चि और पर्कण उपाबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसके पण्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा 17 को उपयोग (2क) के प्रयोग छूट दिए जाने के लिए आयेवन निया है,

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हा गया है कि उक्त स्थापन के कर्मजारी, किसी पृथक भिन्दाय या श्रीभियम का सवाय किए जिना ही, भारत्य जीवन बामा निगम की सामृहिक बीमा स्वीम के अर्थान जीवन वोमा के रूप में पायद उठा रहे हैं श्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिये के पायदे उन फायदों में श्रीधक श्रतुकृत है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्कात उक्त स्कीम कहा स्था है) के श्रधान उन्हें श्रतुक्षेय है.

श्रत, केन्द्रोय संस्थार, उत्तत अधिनियम की धारा 17 की उत्तधार। (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीर इससे उपाधक धनुसूबों में विनिद्धिक सती के श्रवान रहते हुए, उत्तत स्थापन को नाम वर्ष की प्रविधि के लिए उद्दार रहीम के सभा उपस्था के अवर्तन से छुट वेता है।

प्र**नम** भी।

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियाजक प्राद्याणक भविष्य निधि भ्रायक्त तमिलनार का ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा निया निरोधण के निए ऐसः गृविधाए प्रदान भग्रेगा जा केन्द्रीय सरकार समय समय पर निदिष्ट करे।

- े नियाजक, ऐसे निर्दाक्षण प्रभारों का प्रत्येक भास की समाप्ति के 15 दिन के सीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्द श्रिधिनियम की धारा 17 की उपधारों (3क) के खण्ड (क) के श्रधीन समय समय पर निद्दिन्द करें।
- े सामृहिक बीमा र्काम के प्रणासन में, जिसके घरत्यीत लेखाधी का रखा जाना, विवरणियी का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियस का सदत्य, लेखाधी का ग्रन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का सदाय प्रादि भी है, हाने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियाजक, केन्द्रिय सरकार द्वारा यथा धनुमादित सामूहिक बीमां स्कीम केशनियमों की एक प्रति, श्रीर जब कभी उनमें सणाक्षन किया जाए, तक उस सणोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बासों का धनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि काई ऐसा कसचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का यो उक्त अधिनयम के अर्धान छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले हैं। सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाना है तो, नियोजिक सामृहिण बीमा स्वाम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबन आवायक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन्त करेगा।
- 6. यदि उम्म रक्ष म के प्रश्रंन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बकाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अर्धान कर्मचारिया को उपलब्ध फायदों में समृचित स्प से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकृष हो, जो उनत स्कीम के अर्धान अनुकेश हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी आत के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के प्रिधिक बारिस/नामनिर्देशिती की प्रक्रिक के रूप में दोनो रकमों के प्रन्तर के अराबर रकम का सदाय करेगा।
- 8 सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में काई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त तिमलनाषु के पूर्व अनुमौदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कमंच,रियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने नी सभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, भपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-यक्त अवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मजारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले बागना जुका है ब्राधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के श्राधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणविश, नियोजक उस नियन नारीआ के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में ग्रमकल रहना है, ग्रीर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाना है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिनियों या विश्विक वारियों की जो यदि यह छूट म दी गई होती तो उक्त स्वीम के अन्तर्गत हाते. बीमा फायदी के मदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के श्रावीन श्रांत वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देणिनियों। विधिक कारिसो की यीमाञ्चन रकम का संदाय गतारता से भीर प्रत्येक द्या में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाञ्चन रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मृतिश्चित करेगा।

[संख्या एस-3501 1/277/82-पी॰एफ॰-[I]

S.O. 4069.—Whereas Messrs Engineering Industrial Foundary Company, Mettupalayam Road, Coimbatore-9 (TN/2356) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, inenjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(277)/82-PF, II]

का॰आ॰ 4070 - मैसर्स श्री राम रेयन्स, श्रीराम नगर, कोटा-32404 (राजस्थान) (राज॰/1128) (जिसे इसमें इसके पश्चात उनत स्थापन कहा गया है) ने कर्मकारों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवत्थ प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उनत प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) ने प्रधीन छूट दिए जाने के लिए भानेदन किया है :

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भ्रमिदाय या प्रीमिश्रम का संदाय किए जिला ही, भारत य जंदन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अभ्रीत जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से भ्रधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात उन्त स्कीम कहा गया है) के अर्धन उन्हें अनुजोय हैं.

भतः, केन्द्रिय सरकार, उकतं स्रिधितियमं की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त णिकत्यां का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबस्न अनुसूर्वा में विनिर्विष्ट णतौँ के स्रक्षीत रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती हैं।

अनुसृची

- 1 उक्त स्थापन के सबंध मे नियोजक प्रादिशिक भविष्य निधि श्रायुक्त राजस्थान को ऐसी विवर्णध्यां भेजेना और ऐसे लेखा रखेना नया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निरिष्ट करें।
- 2. नियाजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावा का प्रत्येक माम की ममारित के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त ग्रीधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के ग्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके भ्रत्नमेंत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, रेखाओं का भ्रत्तरण, निरीक्षण प्रभावीं का संदाय-भ्रादि भी है, होने वाले सभी व्यथीं का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रिय सरकार द्वारा यथा धनुमीदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, धीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कमेंचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृख्य बातों का धनुवाद, स्थापन के मूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

1001 GI/82-7

- 5. यदि कोई ऐसा कमंचारी, जो कमंचारी भविष्य निधि का या उपन मिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजित सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरून दर्ज करेगा और उसकी बाबन भाषायक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि जनन स्कीम के भ्रष्टीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रष्टीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचिन रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के भ्रष्टीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से भ्रष्टिक धन्कुल ही, जो उन्त स्कीम के भ्रष्टीन भ्रमुक्तेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किमी बान के होते हुए भी, यदि किमी कर्मवारी भी मृत्यु पर ध्म स्कीम के भ्रधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जी कर्मवारी को उस दशा में मंदिय होती, जब वह उकत स्कीम के भ्रधीन होता तो, नियोजक कर्मवारी के विधिक वारिम/नामनिर्देणिति को प्रतिकर के स्प में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेग, ।
- 8. सामूहिक वीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन, प्रावेशिक मिल्य निधि मामुक्त राजस्थान के पूर्व मनुमीदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संबोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि म्रामुक्त, म्रपना भनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-पुक्त भवसर देगा ।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मनारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपता चुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मनारियों को प्राप्त होने वाले फायबे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणक्या, नियोजक उस नियत तारीख़ के भीतर, जो भारतीय त्रीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में भ्रसफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने विया जाता है ता, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के गंदाय में किए गए किसी व्यानिक्स की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के ग्रंक्स्पन होते, यीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उपन स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रश्नीन धाने बांसे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियों/ विधिक धारिसी की बीमाक्कन रकम का संदाय तत्परता से भीर प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाक्कन रकम प्राप्त होने के मान दिन के भीतर सुनिधिवन करेगा।

[सक्या एम-35014/276/82-पी०एफ०-H]

S.O. 4070.—Whereas Messra Shriram Rayons Shriram Nagar, Kota-324004 (Rajasthan) (RJ/1128) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident 1-und Commissiner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may driect from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sallent features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the sold Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approved, give a reasonablt opportunity to the employees to explain their point of view,
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case with 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(276)/82-PF. II]

का० आ० 4071.....मैसर्ग रीनक इन्टरनेशनल लिमिन्ड, इलाहाबाद सैंक बिल्डिंग, 17-पालियामेंट स्ट्रीट, नई विल्ली-1 (डी एल/2229) (जिसे इसमें इसके पश्चत्। उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निश्चि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधितियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्चाल उक्त ध्रधितियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए घावेदन किया है;

श्रीर केन्द्रीय भरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियन का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अश्रीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रिधक भनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहब्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उक्त स्वीम महा गया है) के अश्रीन उन्हें अनुक्षेय है;

भतः, केन्द्रीय सरकार, उस्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त सिनयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपध्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्त स्कीम के सभी अपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

भनुसूची

- गः उन्त स्थापन के सम्बन्ध में नियाजक प्रावेणिक भविष्य निश्चि प्रायुक्त, दिस्ली को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा सथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निविष्ट करें!
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों ना प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संबाय करेगा जो केन्छीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निरिष्ट करे।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके ध्रग्तर्गत लेखाओं का रखा जामा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का ध्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय ध्रादि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक क्षारा किया जायेगा।
- 4. तियां जभ, केर्नीय सरकार दारा यथा धनुमोदित सामृह्कि बीमा स्कीम के नियन की एक प्रति, ग्रीर जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब उन संशोधन की प्रति तथा कर्मनारियों को बंदुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का ग्रामुबाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मधारा, जो कर्मधारी शविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन ९८ प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बामग प्रावश्यक प्रीमियम भारतिय जीवन बीमा निगम की संदत्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कांम के श्रश्नीत कमैनारियां को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तां, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के धर्धिन धर्मणारियां को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मणारियों के लिए सामृहिष बीमा स्कीम के धर्धिन उपलब्ध फायदे उन फायदों में स्थिक धनुकून हों, जो उपन स्कीम के धर्धीन धनुकीय है।

- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सब्देय रकम उस रकत से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामिनदेशिसी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संकोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त विल्ली के पूर्व प्रनुमोवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृष प्रभाव पहने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना धनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवमर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवाग, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बोमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, सो यह छूट रछ की जा सक्ती है।
- 10. यदि किसी कारणवण, नियाजक उस नियत नारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में प्रमफल रहता है, और पालिसी को व्यवगत हा जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा गकती है।
- 1.1. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की वर्णा में उन मृत सवस्यों के नामनिवैशितियों या विधिक वारिसों को जो यवि यह एुट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के झन्तर्गत होते, बीमा फायवों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन थाने वाले किसी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिर्देशितियों विधिक वारिसो की बीम। इत रकम का संव। य तत्परता से भीर प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा इत रकम प्राप्त होने के सान विन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(275)/82-पी०एफ०-11]

S.O. 4071.—Whereas Messrs Raunaq International Limited, Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street, New Delhi-110001 (DL/2229) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premlum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is tiable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs entitled for it and in any case within / days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(275)/82-PF. II]

कां०आ० 4072 — मैसर्ग फटिलाइजर कारपोरेशन प्राफ इडिया लिमिटेड, मधुबन, 55 नेहरू प्लेम, नई विस्ली-110019 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी प्रविध्य निधि प्रोर प्रकोण उपबन्ध प्रधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके परवास उकत प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के प्रधीन छुट दिए जाने के लिए आविदन किया है।

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रीभवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही भारतीय अधिन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं श्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रिधक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्काम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें अनुकृष हैं:

धतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधार। (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध धनुसूची में विनिद्धित्य शतौं के ध्रधान रहते हुए, उक्त स्थापन को तीम वर्ष की स्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभा उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूर्च?

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि अ। युक्त विल्ली को ऐसी जिवरणिया भेजेंगा श्रीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा को केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 2. निर्योजक, ऐसे निर्राक्षण प्रभारों का प्रत्येक मान की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उनत प्राधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के ध्रधान समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3. स.मृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके भ्रन्तगंत लेखामों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमिथम का सदाय, लेखामों का भन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय भ्रादि भी है, होने वाले सभी ष्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जामेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रिय सरकार द्वारा यथा अनुमादित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किय। जाए, तब उस मशोधन की प्रति धथा कर्मचारियों की बहुसक्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रवर्णित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त भिधितियम के भ्रधीन छूट प्राप्त कियी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है हो, नियोजिक सामृहिक वेभा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त वर्ष करेगा भीर उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीयन बीमा निगम की संदल्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के प्रश्नीत कर्मणीरियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में भिधिक अनुकृत हों, जो उनत स्कीम के प्रधीन अनुक्षेत्र है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मजारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सम्वेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मजारी को उस दण। में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मजारी के विधिल वारिस/नामिपीकिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रत्तर के वरांबर रकम का संदाय करेगा।

- 8. सामूहिक कीमा स्कीम के उपवन्धों में कोर्ट भी संशोधन, प्रादेशिक भिलप्य निधि प्रायुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, जहां प्रादेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिस्थलन अवसर देशा ।
- 9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मुकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपना खुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीक्षि से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत नारी स के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम करे संदाय करने में भ्रासकल रहत है, भीर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जात है तो. कुट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए कियी व्यक्तिसम की दशा में उन मृत सबस्यों के नामनिर्देशितिया या विश्विक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रस्तर्गत होते, बींम। फायबों के संदाय का उत्तरदायत्व नियोजक पर होगा।
- 12. उकत स्थापन के सबध मं नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन प्राने बाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेणितियों/ विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता में और प्रस्थेक दशा में भारतिय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम पापन होने के साति विन के भीतर मुनिष्चित करेगा।

[संख्या एस- 35014/274/82-पी एफ- II]

S.O. 4072.—Whereas Messrs Fertilizer Corporation of India Limited, Madhuban, 55, Nehru Place, New Delhi-110019 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charge? as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient leadures thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance reporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Gorporation of India.

lNo. S-35014(274)/82-PF. I]

का अरा 4073. -- मैसर्स घाई ०पी ० सी ० ए० - लेबी टरीज प्राइवेट लिमिटेड, 48- कांडिवर्ला एण्डस्ट्रियल एस्टैट, काण्डीवर्ला (बेस्ट) - बस्बई - 400067 (महा/1419) (जिसे इसमें इसके पण्डात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मच रा भविष्य निधि घौर प्रकीर्ण उपबन्ध घांधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त घांधिनयम कहा गया है) की घारा 17 की उपधारा (2क) के बांधीन छूट दिए जाने के लिए घांबेदन किया है,

धीर केन्द्रीय सरकार का समधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन भीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मनारिमों के लिए ये फायदे उन फायदो से मिसन अनुकूल हैं जो कर्मनारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चात् उकत स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय हैं;

मत:, केन्द्रीय सरकार, जनत भ्रिधिनियम की धारा 17 की जपधारा (2क) द्वारा प्रदक्त ग्राक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके जपाबद्ध भ्रमुसूची में विनिधिष्ट गतों के प्रधीम रहते हुए, जक्त स्थापन को तीन वर्ष की ग्रावधि के लिए जनत स्कीम के सभी जपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- जनत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य मिधि
 आ,युक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा
 निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समयसमय पर निर्धिष्ट करें।
- 2. तियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समारित के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केग्सीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के भंधीन समय-समय पर निविध्द करें।
- 3. सामूहिक में:मा स्कीम के प्रशासन में, जिसके मन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवर्णियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का प्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय भावि भी है, होने वाले सभी अवयों का बहुन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. तियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुषाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अधिष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजिस किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उनका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी याबन आवश्यक शीमियम भारनीय जीवन बीमा निगम को संबत्त करेगा।
- 6. यदि उन्त स्कीम के मधीन कर्मणारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के मधीन कर्मणारियों को उपलब्ध फायदों में समुणित रूप से युद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मणारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक मनुकूल हों, जो उन्त स्कीम के अधेन मनुक्षेत्र हैं।
- 7. सामृहिक बीम. स्कीम में किसी बात के हीते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उसत स्कीम के प्रधीन होता ती, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती को प्रसिक्त के रूप में दोनों रकमो के घन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक धोमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि म्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व मनुमोधन के बिना नहीं किया जाएना भौर जहां किसी संशोधन से कमंत्र,रियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पढ़ने की संभावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि म्रायुक्त, भ्रपना म्रानुमोदन देने से पूर्व कमंत्रारियों को म्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक भविष्य स्वस्त स्वस्त देशा।
- यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा क्कीम के, जिसे स्थापन पहले सपना

चुका है मधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के भवीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

- 10- यदि किसी कारणवर्गा, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीम। निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में श्रसफल रहता है, भीर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जात. है तो, इट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दश, में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह कूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के मन्तर्गत होते, बीमा कायदों के संदाय क. उत्तरद यिख नियोजक पर होगा:
- 12. उनत स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन धाने धाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्वेशितियाँ/ विधिक बारिसी की बीम.कृत रकम का संदाय तत्परसा से धौर प्रस्थेक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के बीतर सुनिध्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/270/82-पी॰एफ-II]

S.O. 4073.—Whereas Messrs I.P.C.A. Laboratories Pvt. Limited 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West)-Bombay-400067 (MH/1419) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more tavourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insume Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Oroup Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled
- 10. Where, for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defualt, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(270)/82-PF, II]

का० आ० 4074:---मैसर्स चेमफाब, भ्रम्बत्तूर इण्डस्टियल एस्टेट, मद्राम (टी एन/6767) (जिसे इसमें इसके पण्णात् उकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निश्चि भीर प्रकार्ण उपबन्ध भविनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्णात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवैदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन कायदों से अधिन अनुबूल है जो नर्मचारी निजेप सहबद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त स्कीम कहा गया है) के मधीन जन्हें अनुकीय है;

मतः, केस्टीय सरकार, उकत प्रधितियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध मनुसूची में विनिर्दिष्ट शतौं के प्रधान रहते हुए, उकत स्थापन को तीन वर्ष की स्ववंध के लिए उकत स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अन्सूषी

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त तिमलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा घीर ऐसे लेखा रखेगा नथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की सभाष्ति के 15 दिन के भीतर संदाय भरेगा जो केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. साम् हिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके भन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाम, लेखाओं का ग्रन्तरण, निरीक्षण प्रभागों का संदाय ग्रादि भी है, होने बाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरफार द्वारा यथा अनुमोदिन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति नया कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का ग्रनुवाद, स्थापन के सुचना पट्ट पर प्रश्नान करेगा।
- 5. यवि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी भविष्य निधि का या उनत प्रधितियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त वर्ज करेगा श्रीर उसकी बाबन प्रायण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निराम को संबक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायबे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मकारियों को उपलब्ध फायबों में समुचित रूप से बुद्धि की जाने की श्ववस्था करेगी जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायबे उन फायबों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनजेय हैं।
- 7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, येदि किसी कर्मजारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अवीत सन्देय रक्तम उस रक्तम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अवीत होता तो. तियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/तामितिंगिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रक्तमों के ग्रन्तर के बर्व र क्रम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्राविधिक भिष्य निधि भ्रायुक्त निमलनाडु के पूर्व अनुमोवन के बिना नहीं विधा आएगा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रावेणिक भविष्य निधि भ्रायुक्त, अपना भनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त भवमर वैगा।
- 9. यदि किसी कारणवा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीभा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना खुका है अधीन महीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधान कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करें, प्रीमियम का संदाय करने में ग्रासकान रहता है, भीर पालिसी को व्ययपान हो जाने दिया जाता है तो, छुट रह की जा सकती है।
- 11 नियोजक हारा प्रीमियम के संदाय के किए गए किसी व्यक्तिकम की क्या में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसों को

जो यवि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के भ्रन्तर्गत होते, यीमा फायदों के सवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजफ, इस स्कीम के प्रधीन प्रान्त बाले किसी गदस्य की मृत्यु होन पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ विधिक वारिसी की बीमाकुन रकम का संदाय तत्परता से प्रीर प्रध्येक वक्षा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकुन रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चिम करेगा।

[मंख्या एस- 35014/249/82-पी०एफ-H]

S.O. 4074.—Whereas Messrs Chemfab, Ambattur Industrial Estate, Madras (TN|6767) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favoudable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Λ ct, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Schemes and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees then the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.

- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilty for payment of assurance benefits to the nominees or the logal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(249)/82-PF.II]

का आ ० 4075.....मैंसमें भ्रम्बर कारपोरेशन, लक्ष्मीनिवास, जयेन्द्रगंज, ग्वालियर, 474009 (एस पी/2261) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि भौर प्रकीण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त भिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भ्रभीन छूट विए जाने के लिए भ्रायेवन किया है,

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उकत स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन योगा निगम की मामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा निगम की मामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है श्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाक उकत स्कीम कहा गया है) के श्रिष्ठीन उन्हों अनुजेय है;

श्रम, केन्द्रीय सरकार, उक्ष्म धिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए धौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिद्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्ष्म स्थापन को तीन वर्ष की खबधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देशी है।

अनुमूखी

- 1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निर्देशिण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रश्येक सत्म वी समाध्ति के 15 विन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रिय सरकार, उक्त श्रिक्षित्यम की धारा 17 की उपधारा (उक्त) के खड़ (क) के द्रार्थन समय-समय पर निदिष्ट करें।
- 3. समूहिक विमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके ग्रन्थर्गन लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, विभा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सवाय भादि भी है, होने वाने सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय मरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कत्री उनमें मंगोधन किया आए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की बहुमंत्रया की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पहंड पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यति कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भावण्य निधि का या उक्त मिन्नियम के भवीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सथस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त को करेगा भीर उसकी बाबत भावण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संवत्त करेगा।
- 6. यदि उन्त स्काम के महीन कर्मनारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्काम के मधीन कर्मनारियों की उपलब्ध फायदी में समृजित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिमसे कि कर्मनारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के महीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से मधिक प्रनुकृत हो, जो उक्त स्कीम के मधीन श्रनु-नेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मेचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अर्थान सन्देग रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के भंधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्वेणिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमो के अस्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक मिषण निश्चित्र प्राप्तुकत मध्य प्रदेश के पूर्व भनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिबूल प्रभाष पढ़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्राप्तुकन, प्रपना प्रमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रापना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तिस्मुकन भवकर देगा।
- 9. यदि फिनी कारणवर्ग, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की जस सामृष्टिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रापना चुका है भ्रष्टीम नहीं रह जाते हैं, या इन स्कीम के ग्राप्तीन कर्नचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह् की जा सकती है।
- 10. यदि किसी भारणवण, नियोजक उन निया सारीख के मीक्षर, को माण्सीय जीवन बीमा निगम निया करे, प्रीमियम का संदाय करने मे मसफल ग्रहना है, भीर पालिसी को व्यागन हो जाने दिया जाना है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11- सियोजक द्वारा प्रीमियन के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की बंगा में उन मृत संदर्श्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उका रहीम के अन्तर्गत होते, बीमा कायवों के संदाय का उत्तरदायिस्व नियोजक पर होता।
- 12. उन्हार स्थापन के संबंध में नियोजफ, इन स्कान्त के प्रधीन प्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नाम निर्दीणनिर्यी/विधिक वारिसो की बीमाकृत रक्षम का संदाय तरपरना में प्रोर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निरास से वीमाकृत रक्षम प्राप्त होने के सात दिस के भीतर मुनिष्टिन करेगा।

[संख्या एस - 35014/248/82 पीरिंगफ-H]

S.O. 4075.—Whereas Messrs Ambar Corporation, Laxminiwas, Jayendragani, Gwalior-474009 (MP[2261) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act); 1001 GI/82—8

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 thereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group lusurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund of the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is camployed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees then the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employer been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominte of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as lixed by the Life Insurance Corporation of India etc. and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomincellegal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

INo. S-35014 (248)|82-PF.III

का॰ आ॰ 4076 → नैसर्स दूरवाणी केवल्स प्राइवेट विमिटेड, "मारुधी मैनवान" दीसरी मंजिल, 19/7, किल्पम रोड, बंगलीर-560052 (किएन/4661) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी मिन्य निधि और प्रकीर्ण उपस्था अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात एकत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2%) के अधीन छूट (देए जाने के जिए अधिनन किया है;

भीर केन्द्रीय संस्कार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक ग्रामियाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के ग्राधीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायवे उन फायवों से भ्राधिक भनुकूष हैं जो कर्मचारी निकाप सहब्द्रश्च बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चास उक्स स्कीम कहा गया है) के ग्राधीन पन्हें भनुकेय हैं;

मतः , केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रीव्यात्म की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रगीग करते हुए और इससे उपाबक्ष भनुसूची में विनिधिंद्य क्षतों के श्रीवा रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की श्रविध के लिए स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां बेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर भिविष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाधित के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्धिट करे।
- 3. सामूहिक बीम। स्कीम के प्रशासन में, जिसके घन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संवाय लेखाओं का धन्तरण , निरोक्षण प्रभारों का सदाय धादि की है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेथा ।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकारु द्वार. यथा धनुमीदित सःमृहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, घोर जब कथी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का प्रमुखाव, स्थापन के सुखना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।
- 5. यवि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्वापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त वर्ण करेगा घौर उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम आरतीय जीवन बीम, नियाम की संबत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के अधील कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों

- को उपलब्ध कायदों में समुचित रंप से वृद्धि की जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मजारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीत उपलब्ध फायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल थीं, जो उक्त स्कीम के अधीत अनुक्रेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्म-चारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सबैय रक्तम उस रक्तम से क्तम है, जो कर्मबादी की उस वणा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन हीता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिय/नामनिर्वेषिती की प्रतिकर के इप में दोनों रक्तमों के प्रशार के बर बर रक्तम के संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपवन्त्रों में कीई भी संशोधन, प्रादेशिक मिविष्य निधि भायुक्त कर्नाटक के पूर्व प्रतुमीदन के विना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव महने की संभावना हो, बहां प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुभोबन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भवता चुका है भ्रधीन महीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के भ्रधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायरे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह पूर रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी काश्यवण, नियोजक उस नियन गारीख के भीनर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में ग्रसफल रहता है, ग्रीर पालिसी की व्यपगत हो जाने विया जाना है तो छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के संदाय में फिए गए किसी क्यसिकम की दशा में उन मूत सदस्यों के नाम निर्देशितीयों या विधिक वारिसों की जो यदि यह छूट न दो एई होनी तो उनक स्कीम के सम्पर्तित होते, बीमा पायवों के संशय के उनस्दाधित विशेषक होता ।
- 12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीत के ध्रधीर धाने वाले किसी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हंकवार नाम निर्देशिनीयों विधिक वारिसो की बीमाइत रकम का संदाय तत्परना से भौर प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बानाइत रकन प्राप्त हाने के सास विक के भीतर मुनिश्चिन करेगा।

[सं॰ एस-35014/244/82-गे॰ एक-II]

S.O. 4076.—Whereas Messrs Doorvanl Cables Private Ltd., Maruthi Mansion, 3rd Floor, 19/7 Canningham Road, Bangalore-560052 (KN-4661) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Prov dent Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Emplioyees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc. the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

कांश्मां 4077—मैसमें मेटल बाक्स इंडिया सिमिटेड, 19, इलाइक मुवाली स्ट्रीट, तोविरपेट, मद्रास (टी एन/196) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत स्थापन कहा गया है) ने कर्षचारी भविष्य निधि भौर प्रकोण उपबन्ध भिवित्यम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मिशित्यम कहा गया है) की झारा 17 की उपञारा (2क) के भर्षान छूट विए जाने के लिए भावेदन किया गया है;

धीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक घर्षियाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना हैं, भारतीय जीवन वीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के घर्षीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं घीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से घर्षिण अनुकूल हैं जो कर्मचारी निभेष सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उन्त स्कीम कहा गया है) के घर्षीन उन्हें अनुनेथ है;

भ्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) क्षारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिद्धिट शर्तों के भ्रद्धीन रहते हुए, उक्त स्थापन की सीन वर्ष की भ्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबग्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

अनुसूची

- 1. उन्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक मिक्य निधि ग्रायुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा ग्रीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रस्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाध करेगा जो केन्द्रीय संरकार, उक्त मिनियम की घारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के भवीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रकासन में, जिसके धंकर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीम। प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का मन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रावि भी है, होने वाले सभी क्यों का बहुन नियोजक द्वारा किया आयेगा।
- 4. नियोजक, केन्दीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, धौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसँख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातो का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदक्षित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के भ्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरक्त दर्ज करेगा और उसकी बाबन भ्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सवत्त करेगा।
- 6. यदि छम्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक सामृद्धिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृदिन रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृद्धिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अधीन अनुकृष हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकृष हों।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए बी, यदि किसी कर्मेवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से क्षम है, वो कर्मवारी को उस दवा में संदेय होती, जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मवारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती को

- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी रांगोझन, प्रावेणिक भविष्य निधि अप्वम्न भिन्तताहु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेणिक भविष्य निधि आयुक्त, प्रपा प्रनुमोदन देने से पूर्व वर्मचारियों को प्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुवन अवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवर्श, स्थापन के कमंबारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिमें स्थापन पहले अपना चुका है ब्राईत नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के ब्राईत कमंबारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीनि से कम हा जाने हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवया, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीयन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में भसफल रहता है, ग्रीर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है ती, खूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यां के नामितर्वेणितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो उकते स्क्रीम के अनुगत होते, योमा फायवों के संवाय का उक्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सबंध मे नियोजना, इस स्कीम के ध्रवीन माने बाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हजदार नाम निर्देशनियी/विधिक वारिसो की दीमाइन रकम का सवाम तरपरता से मीर प्रत्मेक दला में भारतीय जीवन बाग। निगम से बीमाइन रकम प्राप्त होने के साल दिन के भीतर सुनिध्वत करेगा।

[संख्या एस० 35014/241/82-पी०एफ० II]

8.0. 4077.—Whereas Messrs Metal Box India, Ltd., 19, Elaiya Mudali Street, Tondiarpet, Madras (TN/196) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of furce years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Control Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Enaployees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where apy amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(241)/82-PF.II]

कां कार 4078 -- मैससं इथिको इन्स एण्ड कैंसिकत्स मैस्पूर्यक्विश्व कें 37, ए-इण्डस्ट्रियल एस्टेट पोलो पाउण्ड, इस्पैर--- 452002 (कोड स०प्र० 2470) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन गर्भ ना है) ने कर्मचारी स्विच्य विधिश्रीर प्रकीणं उपबन्ध समिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त समिनियम कहा गया है) की या र 17 की उपधारा (2क) के समिन सूट दिए जाने के लिए सानेवन किया है; भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, तिसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए विना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक बीमा स्कीम के भ्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहें हैं भीर ऐसे कर्मचारियों वो लिए ये फायदे उन फायदों से ग्रधिक अनुकूलन हैं ओ कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध भीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाल उक्त स्कीम कहा गया है) के भ्रधीन उन्हें भ्रमुक्तेय है,

मतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त मिनियम की घारा 17 की जपभारा (2क) द्वारा प्रवत्त मिनियों का प्रयोग करते हुए मीर इससे उपावद मनु-सूची में बिनिदिष्ट शर्ती के मधान रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की मर्वाध के लिए उना स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अमृसूर्च?

- 1 उपत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक श्रांबब्ध निधि भाषुमत सध्य प्रदेश को ऐसी विवरणिया भेजेगा भीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केर्ब्राय सरकार, समय-समय पर निविद्ध करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभार का प्रस्येक मास की समाध्ति के 15 विन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रिय गरकार, उदन प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के प्रण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निविष्ट करें।
- 3. सामृहिक भीना स्वीम के प्रशासन में, जिसके प्रशासित लेखायों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखायों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि की है, होने वाले सभी व्ययों वा पहन नियोजक शास किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुसोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब ककी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस समोधन की प्रति क्षया कर्मचारियों की सहुसक्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी मिवय्य निधि का या उक्त प्रक्षितियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामृद्धिक कीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा भीर उसकी बाबत था वश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन कीमा निगम को संबत्त करेगा।
- 6. यदि उनते स्कीम के प्रधीन कर्मधारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाएं जाते हैं, तो, नियोजक सामूजिबीमा स्कीम के प्रधीन क्षमंचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहित बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से मुश्कि प्रतृष्ट्रम ही भी उनते स्कीम के प्रधीन प्रवृत्वेय हैं।
- 7. सामूहिक बोला स्कीम में किसी बात के हों। हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के श्रवीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उन दणा में संदेय हाती, जब बहु उक्त स्कीम के श्रवीन होता तो, नियोजिक कर्मचारी के बिधिक वरिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के स्प भें दोना रकमों के सन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8- सामूहिक योग। स्कीम के उपबन्धों से कोई भी संबोधन प्रावेशिक भिवज निधि आयुक्त मध्य प्रवेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएका भीर बहां कियों संशोधन के कर्मकारियों के हिन पर प्रसिक्त प्रभाव पड़ने की संझावना हा, वहां पारेशिक भविष्य निधि श्रायुक्त, समना मणुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रंपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा ।

- 9. यदि किसी कारणवम, स्थापन के कर्मणारो, भारतीय कीवन बीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन गहले अपना मुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाल प्रायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियन आरीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें। प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहना है, भीर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रें। मिथम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृथ मदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीय के प्रेंगर्गत होने, सीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होते पर उसके हकदार नाम निदेशितिया/ विश्विक वारिसों की बीम। इत रक्तम का संदाय तत्परता से मीर प्रत्येक स्था में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा इत रक्तम प्राप्त होने के साल दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/239/82-मी०एफ० 11]

S.O. 4078.—Whereas Mesers Ethico Drugs & Chemicals Mfg. Co., 37-A, Industrial Estate, Pologround, Indore-452003, (MP/2470) (heremafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (heremafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, is the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the condition, specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts, the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses invoved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees,
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employer in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance surance Scheme, if on the death of an employee the amount ployees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approach of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the suid establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits—to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of defaut, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

INo. S-35014(239)/82-PF.III

काश्या • 4079. — मैससं लीबसं इंजीनियरिंग वक्सं, इण्डस्ट्रियल टाउन जालकार-144004 (पी/एन)160) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी सविष्य निधि सौर प्रशी उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चान उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के सधीन छूट विए जाने के लिए प्राविवन किया है ;

श्रीर केण्द्रीय सरवा' का समाधान हो गया है कि उक्त स्वापन के कमचारी, किसी पृषक श्रमिवाय या श्रीमियम का संवाय िए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के अर्थन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहें हैं श्रीर ऐसे कर्मवारियों के लिए ये जायदे उन कायवों से श्रिक श्रमुकूल जो कर्मवारी निक्षेप सहवढ़ बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें श्रमुक्षय है;

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्न प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थ्रीर इससे उपायक मनुसूची में विनिर्दिष्ट सर्ते के भ्रधीन रहते हुए, उक्त स्वापन को तीन वर्ष की सर्विध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

मनुत्र्वी

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक निर्माणियां नियोजक प्रावेशिक निर्माणियां निर्माणियां भेजेंगा धीए ऐसे लेखा तथा निरीक्षण के निए ऐसी सुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय संस्कार, समय-समय पर निर्दिष्ट वरें।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विन के भीतर संवाय करेगा को केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निरिष्ट करे।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रस्तांत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का प्रस्तरण, निरीकण प्रभारों का संवाय पावि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुविधित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. मदि कोई ऐसा कर्मबारी, जो कर्मबारी भविष्य निधि का मा उक्त भिवित्यम के प्रधीन कूट प्राप्त किसी स्वापन की मविष्य निधि का पहले हो सबस्य है, उसके स्वापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम सुरूल वर्ज करेगा और उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम चारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के मधीन काँमकारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के मधीन कमैंनारियों को उपलब्ध फायदों में समृश्वित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कमैंचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के मधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से मधिक मनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन मकुन्नेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्तीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्तीम के मधीन सम्बेग रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त रकीम के मधीन होता तो, नियोजक कमजारी के अधिक वारिस/नामनिवेंकित को प्रतिकर के रूप में बोनों रकमों के भन्तर के बराबर रक्तम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपनन्तों में काई भी संशोधन, प्रावेषिक भविष्य निधि प्र.युक्त पंजाब के पूर्व प्रनुमीवन के बिना नहीं किया जाएगा भीर जहां किसी संशोधन से कमचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संवावना हो, वहां प्रावेशिक भविष्य निधि भायुक्त, भपना भनुनोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को भ्रयमा वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर वेगा।
- 9. यदि किसी कारणवर्षा, स्थापन के कर्नेवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भ्रपना चुका है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीक के प्रधीन कर्मवारियों को प्राप्त होंने वाले फायदे किसी रीति से कम ही जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियत तारील के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में मसक्तम रहता है, मीर पाणिसी की न्ययगत हो जाने दिया जात है तो छट रह की जा सकती है।

- 11. नियोजक द्वारा त्रीनियम के तंदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन भूत सदस्यों के नाम नियेशिर्द्रतयों या विद्यिक वारिसों को जो सर्वि यह छूट न की नई होती तो उक्त स्कीम के संगाँत होते, बीमा फायवों के संवाय का अत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 1.2. उक्त स्वापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के धंधीन धाने वाले किसी संदेश्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नाम निवेशितियाँ/विधिक बारिसों की बीमाइत रकम का संवाय सत्परतः से धीर प्रत्वेक वक्ता में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइत रकम प्राप्त होने के सात विभ के भीतर सुनिश्वित करेगा।

[संख्या एस-35014/338/82-पी०एफ०-II]

8.0. 4079.—Whereas Messrs Leader Engineering Works, Industrial Town, Juliundur-144004 (PN/160) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the empoyee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the poicy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(238)/82-PF.II]

का०आ० 4080--- मैसैस हिस्बुस्तान बाउन बोवरी लिमिटेड, पो०बाक्स तं० 16 प्राई०ए० फरीवाबाव (पी०एन०375) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कमैंबारी भविष्य निधि धौर प्रकींण उपबन्ध भिक्षियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चान एक्त प्रक्रितियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के भ्रष्टीन छूट दिएर जाने के लिए भ्रावेदन किया है;

मीर केन्द्रीय सरकर का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मवारी, किसी पृषक मिना या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, मारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीन के मधीन जीवन बीमा के किए में कायदों उठा रहे हैं भीर ऐसे वर्मवारियों के लिए में कायदे उन कायदों से मधिक अनुकूल हैं जो कर्मवारी निवाप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (बिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के मधीन उन्हें मनुकेय है;

मत., केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रविनियम की धारा 17 की उपाधारा (2क) द्वारा प्रवत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाध्य धनुसूची मे विनिधिष्ट मतौं के प्रवीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की प्रविध के लिए उक्त स्कीम के सभी उपाध्यों के प्रवतन से छूट देती है।

अनुसूची

उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक मिष्य निधि
प्रायुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा सथा
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवात करेगा जो केम्ब्रीय सरकार,
समय-समय पर निविष्ट करे।

- 2. नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाध्य के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा त्रा केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्विष्ट करें।
- 3 मामूहिक भीना स्थीम के प्रशासन में, जिसके घर्मनिस सेखाओं का रखा जाना, विश्वरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, सेखाओं का प्रस्तरण, निरोक्षण प्रभारों का संवाय प्राप्ति भी हैं, होने वासे सभी ज्यायों का बहुन नियोजक हारा किया जायेगा।
- 4. निर्मानन, केस्ब्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमीदिन मामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति ग्रीर जब कभी उनमें संगोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनृवाद, स्थापन के सूबनान्यह पर प्रदेशित करेगा।
- 5. यदि कांई ऐसा कर्मवारी, जो कर्मवारी भविष्य निधि का या उक्त मिनियम के मधीन छूट प्राप्त किसी स्वापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्वापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्तीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरम्त को करेगा भीर उसकी बावन भविष्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सेवल करेगा।
- 6. यदि जन्म स्कीम के भवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के भवीन कर्मचारियों को जप्तब्ध फायदों में ममुधिन रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा विससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के भवीन उपलब्ध फायदे उम कायदों से मधिक श्रानुकृष हो, जो जन्म स्कीम के भवीन सन्तुवेप हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मकारी की मृद्ध पर इस स्कीम के अधीन सबैय रक्षम उम रक्षम से कम है, जो कर्मकारी का उस बया में संदेय होती, जब यह उक्ष्म स्कीम के अधीन होता तो, निर्मामक कर्मकारी के विक्षिक बारिम/नाम निर्वेणिक्ति को प्रतिकर के रूप में दानो रक्ष्मों के अन्तर के बराबर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उबन्धी में काई मी संशोधन, प्रावेशिक धिविष्य निधि भायुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिस पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भिन्द्य निधि भायुक्त धपना धनुमोदन देने से पूर्व वार्मेनारियों की भपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्त मुक्त भवतर देगा।
- 9. यदि किपी कारणवार, स्थापन के कर्मजारी, भारतीय जीवन कीमा नियम की उम मामृहिक विधा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अवीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अवीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाने कायदे किसी रीति से कम हो जाने हैं तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किमी कारणवण, नियोजक उम निया कारीख के भीकर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियम करें, प्रीमियम के संदाय करने मे मसकल रहता है, भीर पालिसी की व्ययगत ही जाने दिया जाता है ना, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोगफ द्वारा प्रीभिथम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिक मि वशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशियिया या विधिक बारिमों की को यदि यह, खूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के मन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरशायित्य नियालक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सरमन्त्र में निरोजक, इस स्कीम के प्रवीत प्राक्ते वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्षवार नाम निर्देशिनियो/

निधि शारिसों की बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से घौर प्रस्येक दक्षा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम पाष्त्र होने के सात बिन के भीसर मुनिश्चित करेगा।

[संक्या एन 35014/237/82-पी॰एफ॰-I1]

S.O. 4080.—Whereas Messis Hindustan Brown Boverl Ltd., Post Box No.16, I.A. Faridabad (PN|375) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Misscalaucous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the pature of Life Insurance which hare more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government herbey exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDUI F

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses invoved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on-the death of an employe the amount nayable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the empoyee as compensation
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and

where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of tht Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of of default, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No.S-35014(237)|82-PF.II]

का॰ आ॰ 4081 .-- मैसर्स श्री गणेश रोलिंग मिस्स, विस्ती रोड, सातरोड खुर्व (हिसार)-125044 (कोश नं॰ पी॰ एन॰/4563) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भिष्टिय निधि और प्रकीर्ण उपबंध मिशिनयम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मिशिनयम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के मिश्रीन छूट दिए जाने के लिए श्रायेवन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक धिषयाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के छधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन फायदों से धिक प्रमुक्त हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्कीम कहा गया है) के घधीन उन्हें धनुक्षेय हैं;

भ्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त भ्रधितियम की धारा 17की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर इससे उपाबद्ध भ्रमुपूषी में विनिर्देष्ट शर्तों के भ्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भ्रषधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंदों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेश भीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीकण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 विन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रीधनियम की स्रारा 17 के उपधारा (3क) के खंड (क) के श्रीत समय-समय पर निविष्ट करे।
- 3. सम्हिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके मन्तर्गत सेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का प्रन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय ग्रावि भी है, होने वाले सभी क्यमों का बहुन नियोजक द्वारा किया आयेगा।

- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा घनुमोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रांत, और जब कभी उनमें संबोधन किया जाए, तब उस संबोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का घनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रविधित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्स भिधिनियम के भधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा भीर उसकी बाबत श्रावश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबत करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के श्रधीन कर्मशारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उत्त फायदों से श्रधिक श्रनुकुल हों, जो उक्त स्कीम के श्रधीन श्रनुकेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कमंजारी की मृत्यु पर इस स्कीम के मधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कमंजारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के मधीन होता तौ, नियोजक कमंजारी के विधिक वारिस/नामिवेंशिती को प्रतिकर के रूप में वोनों रकमों के मन्दर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कीई भी संगोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त पंजाब के पूर्व मनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा मौर जहां किसी संगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि श्रीयुक्त, श्रपना प्रमुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को श्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त श्रवसर देना।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय खीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले श्रपना चुका है श्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्वीम के श्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीका के भीतर, वो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपशत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियांजिक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिम की दशा में उन मृत सवस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी वई होती तो उक्त स्तीम के मंतर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरवाधित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन धाने बाले किसी सबस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्दोणितयों/ विधिक वारिसों की बीमाक्कत रकम का संबाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में मारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सास दिन के भीतर सुनिध्यत करेगा।

[संख्या एस-38014/236/82-पी० एफ-II]

5.0. 4081.—Whereas Messrs Shree Gantsh Rolling Mills, Delhi Road, Satrod Khurd (Hissar)-125044 (Code No. PN|4563) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

4228

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more tavourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHFDUI F

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the trules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in tespect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be hable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(236)/82-PF, II]

का० आ० 4082 — मैंनर्स नेमनल को-प्रापरेटिव कंज्यूमर्स फैडरेमल प्रॉफ डीड्या लिमिटेड, मुख्यालय दीपाली, (5वां फ्लॉर) 92-तेन्नर प्लेस, नई विल्ली-110019) कीड-नं० डीएल 2333, (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अविषय निधि घीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 को 19) जिसे इसमें इसके परचात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है कि धारा 17 की उपधारा २क के अधीन छूट दिए जाने के लिए धायेदन किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रीभवाय या श्रीमियम का संदाय निए जिना ही, भारतीय जीवन बीमा निशम की मामृष्टिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए से फायदे उन फायदों ने श्रधिक श्रनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रधीन उन्हें श्रन्शेय है;

श्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रिधिनियमं की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्न गक्तियों का प्रयोग करने हुए श्रीर श्रूसमे उपाबद्ध श्रन्-सूत्री से विनिर्दिष्ट गर्नों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवधी के प्रवर्तन से छूट देती है।

अन्स् चर

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक प्रविष्य निधि प्रायुक्त विल्ली को ऐसी वियरणिया भेजेगा घीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रवात करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समास्ति के 15 दिन के भीतर गृंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रक्षिनियम की धारा 17 नी उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- स्मामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गम लेखाओं का पन्ना जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदिभी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक कारा किया आयेगा।
- 4. ियंजिक, केल्क्षीय सरकार द्वारा यथा अनुसोदित सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें सणोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बानों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उभन अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, तियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबल आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा मिगम की संदन करेगा।

- 6 यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाते हैं ता, नियाजक सामृष्टिक वं मास्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उप-लब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाते की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृद्धिक बीमा स्कीम के ग्राधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से प्रधिक प्रमुक्त हो, जा उन्त स्वीम के ग्राधीन ग्राम्जैव है।
- 7 सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मन्यू पर इस स्कीम के अधीन सदेय रक्तम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दणा में सबेय हाती, जब वह उकत स्कीम के अधीन हाता मी, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/नाम निर्देशिक्षी की प्रतिकार के स्वाप करेगा।
- 8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबधों में काई भी सणोधन, प्रार्थणक भविष्य किथा आयुक्त विल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना सही किया जायेजा और जहां किने सणांधन से कर्मचारियों के दिन पर प्रतिकृत प्रभाव पहने की संभावना हो बहा, प्रार्थणिक अधिष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देना।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन यीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिसस्थापन पहले अपना चुका है अर्धान नहीं यह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त होने बाने फायदें किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रह की जा सकती है।
- 10 यदि शिक्षी कामणवान, नियानक उसं नियम तारीख के भी मुर्ज ने भारतीय जीवन बीमा निर्मा नियन करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगन हो जान दिया जाना है तो. छूट इ की जा सकती है।
- 11. नियोजन हारा प्रीमियम के सदाय में किए, गए किसी व्यतिक्रम की दशों में उन मृत सदस्यों के नामनिर्दाणितियों या विधिक वारियों को जो यदि यह, छूट न दीं गई हानी नो उक्त स्कीम के अनुगंत हाते. बीमा फायदा के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12 उनन स्थानन के सबंध में नियाजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मन्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देणिनियां/ विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय नश्वरता में और प्रत्येक बंशा में भारतीय जीवन कीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सान दिन के भीनर मुनिण्यित करेगा।

[मुख्या एस-३५०१४/२३ १/४२-पी० एफ-2]

S.O. 4082.—Whereas Messrs National Cooperative Consumer's Federation of India Ltd., H. O.: Deepali (5th Floor), 92, Nehru Place, New Delhi-110019 (Code No. DL 2333) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the renefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not temain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

(No. S-35014(234)/82-P.F. II]

मर्क दिल्ली, 13नवम्बर, 1982

का० आ० 4083 .—मैंससं बी० सी० एम० इंजीमियरिंग प्रॉबक्ट्स, असरोन, रोपड़ (पी एन। 5959) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपक्षेत्र अधिनियम, (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेदन किया है:

भौर केन्द्रीय सरकार का समाद्यान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक मिनदाय या प्रीक्षियम का संदाय किए बिना हीं। भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए में फायदे उन फायदों से मिश्रक मनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप मनुबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें भनुबोय है;

मतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त भिक्षितियम की धारा 17 की उपबारा (2क) द्वारा प्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर इससे उपायद मतृसूची में विनिर्विष्ट शर्तों के भधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की सबक्षि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्नों के प्रवर्तन से सूठ वेली है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि भायुक्त पंजाब को ऐसी विवर्णियां मेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक सास की सन। प्रित्त के 15 विन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के प्रधीन समय-समय पर मिविष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके घंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीभिवम का संदाय, नेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मेचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद; स्थापन के श्रुचन प्रदृष्ट पर प्रविश्त करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी पविषय निधि का या उक्त प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की प्रविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ग करेगा और उनकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के म्रद्यील कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते, है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के म्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था फरेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के म्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से म्रिक्ड मनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के म्रधीन मनुक्षेय हैं।

- 7. सामूहिक बीमा स्कृिम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी समंवारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवेय रक्तम उम रक्तम से कम है, जो कमें जारी को उस वसा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता, तो नियोजक जमंबारी के विधिक वारिमानामिर्विशितों को प्रतिकर के रूप में वोनों रक्तों के अंतर के बरावर रक्तम सा संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भिविष्य निधि भायुक्त पंजाब के पूर्व प्रजुमीवन के बिना नहीं किया जायेगा भीर जहां किसी संशोधन से कर्मनारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रजाब पड़ने की संभावना हो वहां प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रथना प्रमुभीवन देने से पूर्व कर्मणारियों को भ्रयना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भ्रवसर वेगा।
- 9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मजारी, भारतीय जीवन कीमा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले भनता चूका है मधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के मधीन कर्मजारियों को प्राप्त होने वाल फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रह की जा ककती है।
- 10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारी के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में घसफल रहता है, भीर पालिसी को व्ययनत हो जाने विया जाता है, तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीभियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिकम की वंशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की जो यदि यह ,छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रतर्गत होते, बीमा फायवों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन माने पाले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निर्धेशितियों विधिक वारिसों की बीमाइन रकम का संदाय तत्यरता से भौर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाइन रकम प्राप्त होने के सान दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014/245/81-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 13th November, 1982

S.O. 4083.—Whereas Messes DCM Engineering Products Works, Asron, Ropar (PN/5959) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance permia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund, of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of decessed members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(245)/82-PF.II]

का० आ० 4084.—मैंसर्स तिमलनांडु शूगर केन फार्म कारपोरेशन जिमिटेड वाधापाधियानगलम थंजाबर (टीन एन/7930) (जिसे इसमें इसके पश्चात् जकत स्थापन कहा गया है) ने कर्मवारी भिषय निधि भीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके

परकात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपवारा (2क) के अधीन छट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है:

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाञ्चान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक श्रीकाय या श्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायवे उठा रहे हैं श्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायवे उन फायदों से श्रिष्ठक श्रमुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महुबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम यहा गया है) के श्रधीन उक्हें श्रमुकेय है;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उन्त श्रक्षिनियम की घारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवस पाकित्यों का प्रयोग करने तुए और इससे उपायद प्रमु सूची में विभिद्धिय गतौं के श्रक्षीन रहते हुए, उन्त स्थापम को तीन वर्ष की श्रवीय के लिए उन्त स्कीम के सभी उपवंदों के प्रवर्तन से छट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्राविशिक भनिष्य निश्च प्रायुक्त समिलनाइ को ऐसी निवरणियां भेजेगा श्रीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरोक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार ममय-समय पर निविष्ट करे।
- 2. नियोजन, ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार, उक्न अधिनियम की आरा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-मनय पर निर्दिष्ट करे।
- 3 सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, िक्सके प्रशीन लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का प्रंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रादि भी है, होने वाले सभी क्यों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रनुमोदिन सामृहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति भौर जब कभी उनमें संबोधन किया जाए तब उस संबोधन की प्रति तया कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी, मध्य बातों का अनुवाद, स्थान के सूचना-पट्ट पर प्रधणित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उन्त श्रीधनियम के श्रिश्चेन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामू-हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरस्त दर्ज करेगा श्रोर उसकी बाबत श्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबत्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मनारियों को उरलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मनारियों को उपलब्ध फायदों में सनुष्टित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मनारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिन प्रनुकृष हो, जो उक्त स्कीम के प्रधीन प्रनुक्षेय हैं।
- 7. सामृहिक बीभा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीत सदेय रुक्त उन रक्तम में क्षत्र है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवैय होती, जब वह उनत स्कीम के अधीत होता सो, नियोजक कर्मचारी के विधिक व।रिस/नामनिर्वेशिती को प्रतिकृत के रूप में दोनों रक्तमों के असर के बराबर रक्षम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीभा स्कीम के उपनंत्रों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त नीमलनाहु के पूर्व प्रनुमोदन के बिना नहीं किया प्राएम। घोर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना मनुमोदन

देने से पूर्व कर्मणारियों को प्रपना दुष्टिकोण रूपष्ट करने का शुक्तिमुक्त अवसर देण।

- 9. यदि (कसी कारणवाग, स्थापन के कर्नवारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उन मामृहिक बीमा स्कीम के जिने स्थापन पहने श्रपना निहा है अबीन नहीं रह जाने है, या इस स्कीम के अधीन कर्मवारियों को प्राप्त होने बाले भायदे किसी रीनि से कम हा जाने हैं, तो यह छूट रह की जी सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवन, नियोजन उस नियत सारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर प्रीतेमान का महाय करने में प्रतक्ष रहता है और पालिसाको अपनात हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह कि जा सकती है।
- 11. नियोजक हारा प्रेशंमध्य के सदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामानदीं प्रतिया या निष्धिक नारिमा की जो यदि यह छूट न दी गई हाती का उक्त मतान के प्रश्ति ही।, बान फायदी के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उदय स्थापन के सबस में नियागन इस स्कीत के अधीन प्राने बाल किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जाते हरदार नाम निर्देशातया। विधिक वारिना की वीमाकुन रजा का मदाय नत्स्ता से और प्रायेक दण। में भारतीय जावन बाला नियाग में बीपाकुन रजा प्राप्त होने के नाम दिन /के मीन स्मिन करेगा।

[संख्या एस-35014/252/82-पी०एफ०-II]

S.O. 4084.—Whereas Messis Tamil Nadu Sugar Cane Farm Corporation Limited, Vadapathimangalam, Thanjavur. (TN/7930) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the sailent features threof, in the language of the majority of the employees.

- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employes, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Coporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince flegal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

INo. S-35014(252)/82-PF.II]

का० आ०४।085 --- मैंसर्स डेल्टन केवल्स लिसिटेड, 24, दिन्य।गंज सई दिल्ली (डीएल/179) (जिसे इसमें इसके पण्जात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी श्रीवच्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध प्रधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्जात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रकीन छ्ट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है,

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मधारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किए जिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा कि रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकृत है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय है;

श्रात. केन्द्रोय नरकार , उक्त प्रश्नित्यम की धारा 17 की उपधार (2क) द्वारा प्रदेश श्रावतयों का प्रयोग करने हुए धीर इसमें उपायखं सम्मुची में विनिदिष्ट शर्मों के ग्रहीन रहते हुए, उक्त स्वापन को तीन वर्ष की स्वविद के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवन्धों के प्रवर्तन में दृट देती है।

अनुसूची

- । उक्त स्थापन के सबन्ध में नियोजक प्रादेणिक भिनाप निधि ग्रायुक्त विल्ली को ऐसी बिवरणियां भेजेगा ग्रीर ऐसे लेखा रखेगा नधा निरिक्षण के लिए ऐसी मुखिधाए प्रदान करेगा जो केटीय सरकार, समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधार। (3क) के खण्ड (क) के प्रधिन प्रसय-समय पर निर्दिष्ट करे।
- 3 सामृहित कीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके घरतर्गन लेखाओं का रखा जाना, विवरणिया का प्रस्तुन किया जाना, वीमा प्रीसियम का संदाय, लेखाओं का श्रस्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय श्राधि भी है, होने वासे सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामृहिक बीमा स्कीम के नियमों ना एक प्रति, और जब कभी उनमें संगोधन किया आए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मकारियों की बहुरांख्या की भाषा में उसकी भुक्य बातों का अनुवाब, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदिशित करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उनन मिधिनयम के प्राचीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का यह ले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक सामूहिक बीमा स्त्रीम के सबस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा भीर उसकी बाबन भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदहन करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के भ्रधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, तियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के श्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में भ्रधिक श्रनुक्ल हो, जो उक्त स्कीम के श्रधीन अनुनेय है।
- 7. समूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मकारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मकारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उसन स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मकारी के विधिक बारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के मण में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्त्रीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भिविष्य निधि प्रायुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के जिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मकारियों के हित पर प्रतिकृष्य प्रभाव पक्ष्ते को स्तावना हो, वहां प्रादेशिक भिविष्य निधि अध्युक्त, प्रपना अनुमोदन तेने से पूर्व कर्मवारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देना।
- 9. यदि किमी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा विगम की उस मासूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले घ्रपना चुका है प्रधीन मही रह जाते है, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायदे किसी रीति से कम हा जाते हैं, तो यह छूट उद्द की जा सकती है।
- 10 यदि किसी कारणवण, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असफल

- रहाता है, श्रीर पालिसी को व्यवसात हो जाने दिया जाता है तो, छूटू रहद की जा सकती है।
- 1! नियाजक द्वारा प्रंभियम थे सदाय में किए मए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जायदि यह छूट नर्दा गई होती तो उक्त स्कीम के ग्रत्कात होते, बीमा फायदों के संदाय ना उत्परदायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उनन स्थापन के संबंध में नियोजक, इस सिक्तम के अधीन आने वालि किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसो की बोमाक्कत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बामा निगम से बीमाक्कत रकम प्राप्त होने के सान दिस के भीनर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एम०-35014/254/82-पी० एफ-II]

-= _ - _ _ . . _ _ .

S.O. 4085.—Whereas Messrs Delton Cables Limited, 24, Daryaganj, New Delhi (DL/179) (heremafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the emyloyers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the fegal heir/nomines of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employers.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(254)/82-PF.1]]

का॰ था॰ 4086:.....मैसर्स जैनेलेक लिमिटेब, जोगेवनरी इंस्ट, सम्बर्ध (एस॰ एक॰/609) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मेचारी भविष्य विधि और प्रकीण उपबन्ध मिधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चत् छक्त मिधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए मानैबन किया है;

भौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उकत त्यापन के कर्मभारी, किसी पृथक प्रभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के वप में जायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मभारियों के लिए ये फायदे उन काययों से प्रधिक प्रनुकूल हैं जो कर्मजारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्वात उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें अमृत्येय हैं;

श्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रविनियम की धारा 17 की उपधान (2क) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपा-बख प्रमुक्ती में विनिधिष्ट शर्तों के के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की ध्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट वेती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के मम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विधरणियां भेजेगा धौर ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय संग्कार, समय-समय पर निविष्ट करे।
- 2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 किन के भीतर संबाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनयम की घारा 17 की उपधारा (3क) के आपक (क) के अधीन समय-समय पर निर्विष्ट करे।

- 3 सामृहिक बोमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके ध्रन्तगंत लेखाओं का रखा जाना- विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा, कीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अतरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का घटन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार शारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तया कर्मजारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भिषण्य निधि का या उक्त श्रक्षिनियम के श्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में असका नाम तुरस्त वर्ज करेगा भीर उसकी बाबत श्रावण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदस्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्कीम के प्रधीन कर्मधारियों को उपलब्ध कायदे बढाए जाते हैं सो, नियोजक सामृहिक भीमा स्कीम के घडीन कर चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के घडीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से प्रधिक धनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के घडीन धनुक्षेय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, याँव किसी कर्मचारी की मृथ्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्वेय रक्षम उस रक्षम से कम है, जो कर्मचारी को उस दक्षा में संवेय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन हीना तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतीकर के खप में दोनों रकमों के प्रन्तर के बराधर रक्षम का संदाय करेगा।
- 8. सामूहिक कीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई मी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि झांयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व झनुमोवन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष्ण प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि झायुक्त, झपना झनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को झपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन श्रीमा निगम की उस सामूहिक श्रीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहुले प्रपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाने फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं सो वह छूट रव्द की जा सकसी है।
- 10. यदि किसी कारणवंश, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर,जी भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने में प्रसक्त रहता है, प्रीर पालिसी को व्यपगन ही जाने विया जाता हैं तो, छूट रख्व की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गए किसी ध्यक्तित्रम की वशा में उन मृत सवस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिमों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अस्तर्गत होते, बीमा फाययों के संवाय का उक्तरवायिस्य नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन झाने बाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्नेशातियो/ विधिक वारिसो की बीमाक्कत रकम का संदाय तत्परता से भीर प्रत्येक वणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाक्कत रकम प्राप्त होने के सात विन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सक्या एस०-35014/256/82-पी० एफ०-2]

S.O. 4086—Whereas Messis Genelec Ltd., Jogeshwari East Bombay (MH/609) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insulance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Imployees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said. Act and subject to the condutions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the sail establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The emplyer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the sid Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme apporpriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nomince of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtru und where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 1001 GI/82—10

- as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Lafe Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members, who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nomince/legal hous entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. \$-35014(256)/82-PF.[I]

का० आ० 4087:--मैसर्स सूजाता टैक्सटाईलम मिल्स डाक्घर तात-जंगड (के एन०/89) (जिसे इससे इसके पण्चात उक्त रक्षापत कहा गया है) ने कर्मचारी भिवास निधि और प्रकीर्ण उपसन्ध श्रीधितसम 1952 (1952 का 19) जिसे इससे इसके पण्चाम् उक्त श्रीधित्सम नहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन् छूट विण् जाने के लिए श्रीस्टन किया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक श्रानिदाय या श्रीमियम का गंदाय किए विना ही भारतीय जीवन कीमा निगम की सामहिक बीमा स्त्रीम के श्रुवीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं श्रीर ऐसे कर्मचारिया के लिए ये पायदे उन फायदों से श्रीधक श्रान्त है जो कर्मचारी निक्षेप सहबंद बीमा स्त्रीम, 1976 (जिसे इसमे उसके पण्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रुवीन उन्हें श्रुवेश है,

श्रव, केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क्) हारा प्रदन्त शिववयों का प्रयाग करने हुए श्रीर इससे उपायड़ अनुमुखी में विनिविष्ट शर्तों के श्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को नीन वर्ष की श्रवधि के लिए उन्त स्कीम के सभी उपवधी के प्रवर्तन से छूट दती है।

अमृसुषी

- 1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि प्राय्वत कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा ध्रीर ऐसे लेखा रखेगा तथा निर्मक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करगाओं केर्न्डाय सरकार, समय-समय पर निरिष्ट करे।
- 3. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समान्ति के 15 दिन के भीतर, मंदाय करें जो केस्टीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधार। (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदाट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुन किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागें का मंदाय प्रादि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वाग किया जायेगा।
- 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा धन्मीदिन सामूहिक नीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, भीर जब कभी उत्तमें संगोधन किया जाए तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का प्रनृवाद, स्थापन के सूचना-परट पर प्रदर्शित करेगा।

- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त ऋधिनियम के मधीन छूट प्राप्त कियी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियाजित किया जाता है ती, नियाजिक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्य के रूप में उसका नाम सुरुन वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन कीमा निगम की संदश्य करेगा।
- म यदि उक्त स्कीम के मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बहाए जाते हैं तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के मधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदा में समुचित रण से यदि की जाते की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के मधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से मधिक मनुकृष्य हों, जो उक्त स्कीम के मधीन मनुष्रेय है।
- ्र सामृहिक बीमा स्कीम में किसी वात के होते हुए भी , यदि किसी कार्मकारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन मन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मकारी को उस दणा में संदेय होती, जब वह उकत स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मकारों के विधिक बारिस/नामनिवीं जिति को प्रतिकर के स्पर्भ दोनों रकमों के अस्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।
- य सामाहेक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेणिक भियाप निधि प्रायुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा होंग जहां किसी अशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रिक्ति प्रभाव पटन की सक्षाबना हो, बलो प्रावेणिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपत्ना प्रान्थोंदन देने में पूर्व कर्मचारियों का प्रप्रता दृष्टिकोण स्पाट करने का प्राप्तविषय अवसर देगा।
- ्यदि किमी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन श्रीमा निगम की उस सामृष्टिक वीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाल कायदे किमी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रव्व की जा सकती है।
- 10 यदि किसी क,रणवण, नियात्रक उस नियन ताराख के भीतर, जो भारतीय जीवन बामा निगम नियत करें, प्रामियम का सदाय करने में झमफल रहता है, और पालिसी की व्यागत हो जाने दिया जाता है तो. छुट रदद की जो सकरी है।
- 11 नियोजक जारा प्रेमियम के सदाय में किए गए किसी व्यक्तित्रम की दला में उन मन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जी प्रदि यह छूट न दा गई होती तो उक्त स्त्रीम के अन्दर्शत होते, बीमा कायदी के सदाय का उन्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
- 1.2. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के स्रधीन स्राने बाल किसी सबस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/ शिधिक बारिसो की बीमाकृत रकम का सदाय तत्यरता से और प्रत्येक वंशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से कीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के सीवर सुनिश्चन करेगा।

[सर्या: एस०-35014/259/82-पी/० एफ०-II]

S.O. 4087.—Wherea, Messis Sujatha Textile Mills, P.O. Nanjangud, Karnajaki (KN/89) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under subsection (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment, are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE -

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Kainataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said' Scheme, the employer shall pay the difference to the legal beir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium etc the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/

legal $\neg \in r_S$ entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Lite Insurance Corpotation of India.

[No. S-35014(259)]82-PF. II]

चार आरं ४०८८ — सैसर्ज श्री रामालिया मिल्स प्राह्मवेट लिमिटेड, 212, रामासामी, तगर, ब्रह्मकांद्राई-626101 (तिमिल नाडू स्टेंट), (टी० एन०/5252) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने समेच्यर अविच्य निश्चि और प्रकीण उपबन्ध प्रधित्तियम, 1952 (1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रधित्तियम कहा गया है) की धार्य 17 की उपधारा (2क) के ब्रधीन छूट दिए जाने के लिए ब्रावेदन किया है:

र्जीय केन्द्रीय सरकार को समाधान हो गया है कि उबन स्थापन ने कर्मकारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रामियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन दोमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं भीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मकारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुक्षेय है;

अन्ः केर्न्याय, सरकार उक्त मिश्रितियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवत्त गिस्तयों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध मनुसूची मे विनिर्विष्ट गर्तों के मधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की भ्रमधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धी के प्रवर्तन से खूट देती है।

अनुसूची

- 1. उक्त स्थापन के संबंध में नियाजक प्रादेशिक भविष्य निश्चि प्रायुक्त, निम्निनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरी-क्षण के लिए ऐसी मुनिधाएं प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।
- 2 नियोगक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की घारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।
- 3. सामृहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रस्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवर्णण्यों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियन का मवाय, लेखाओं का घंतरण, तिरीक्षण प्रभारों का संदाय घोदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा भनुमोदिन सामृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, घौर जब कभी उनमें संशोधन किए आए. तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मच।रिया की बहुसच्या की भाषा में उसकी मुख्य बाको का भनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
- 5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जी कर्मचारी अविजय निधि का या उक्त अधि-नियम के प्रधीन पूट प्राप्त किसी स्थापन की अविज्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन से नियाजित किया जाता है तो, नियाजक सामृहिक बीमा स्वीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबन जायण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सदस करेगा।
- 6 यदि उसन स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदे बडाए जाने है तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध फायदों में समुचिन रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुक्ल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनु-जेय है ।
- त्र सामृहिक बीमा स्कीस के किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के प्रधीन संदेय रक्तम उस रक्तम से कम है

जा कर्मचारी को उस दथा में सदेय होंती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीत होता तो, नियोजक कर्मचारी विधिक घारिय/नाम निर्देणिसी को प्रशिकर के रूप में दानों रकमों के प्रतर के बराबर रकम का संदाय करेगा !

- ४ सामृहिक बीसा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन, प्रादे-गिक भीवष्य निधि प्रायुक्त, तिमलताइ के पूर्व प्रन्मोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगोधन से कर्मभानियों के हित पर प्रति-कृल प्रनाव पड़ने की सनावना हो बहा, प्रादेशिक शीवष्य निधि प्रायुक्त प्रपत्ता प्रन्मोदन देने से पूर्व कर्मणारियों को प्रपत्ता दृष्टिकीण स्पष्ट करने का यक्तियक्त प्रवसर देशा ।
- ५ यदि किसी कारणवंश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामृद्रिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना सुवा है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी रोति से कम हो जाते हैं, तो यह रह की जा सकती है !
- 10 यद्धि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत त.रीख़ के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियम कर, प्रोमियय का संदाय करने में ग्रमफल रहता है, ग्रार पालिसी को व्यवगत हो जाने दिए जाता है तो, छूट रह की जा सकती है ।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दाना में, उन मृत मदस्यों के नामनिर्देणितियों या विधिक वारिसों की जो, यदि छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत हाते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरवायित्व नियोजक पर होगा।
- 12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक, इस स्कीम के अश्रीन भाने वाले किसी मदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकुत रकम का सदाय तत्परता से भौर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा ।

[सं॰ एस-3501 1/437/82-पी॰ एफ॰-L]]

S.O. 4088.—Whereas Messrs Shri Ramalinga Mills Private Limited, 212, Ramasamy Nagar, Aruppukottal-626101 (Tamil Nadu State) (TN|5252) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereipafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said. Act, within 15 days from the close of every month.

- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(437)]82-PF. II]

करं अर. 4089:— मैसर्स मार्क्स-केकरीज (घाई) लिमिटेड, ग्रहीयार महास-(टी० एत/10387), (जिसे इसमें इसके पश्चात एकत स्थापत कहा गया है) ने कर्सवारी भिवष्य निश्चि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उकत अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के बाधीन छट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्ज-चारी, किसी पृषक प्रश्निदाय या प्रीमियन का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा की सामूहिक बीमा स्कीम के प्राधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कमेशारियों के लिए ये फायदे उन कायदों से मधिक अनुकृत है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध दीमा स्नीम 1975 जिसे इससे इसके पण्नान उपन स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञाय है,

मन केन्द्रीय सरकार, उनन प्रधिनियम की धारा 12 को उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करने हुए और इसमें उनाबद्ध भनुसूर्वी में वितिर्दिष्ट गर्नों के सन्नीन रहते हुए उनल स्थापन का तान वर्ष की प्रविध के लिए उनन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती हैं।

अनुसूची

- 1 उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक भिवष्य प्रोद्यांक निश्चि प्रायुक्त, मद्रास की ऐसी विवरणिया भेजेशा और ऐसे लेखा रखेगा तथा विरोधण के लिए ऐसी सुविधाए प्रवान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-सस्य पर निविष्ट करें।
- 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समानित के 15 दिन के भीतर संदाय करना जो केन्द्रीय सरकार, उक्त भीवित्यम की धारा 17 की उपधारा (उक्त) के खण्ड (क) के प्रधान समय-पस्य पर निर्दिष्ट करें !
- 3 सामृहिक बीमा स्कीम के प्रणासन में, जिसके प्रन्तर्गत लेखायों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियस का नंदाय, लेखायों का प्रतरण, निरीक्षण प्रभारों का सदाय आदि भी है, होने करि सभी क्यायों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय मरकार द्वारा धनुमोदित सामृहिक बीमा स्काम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनसे संशोधन किया जाए, जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमख्या की साथा में उसके मुख्य बातों का धनुवाद, स्थापम के सूचना पट्ट पर प्रवीगत करेगा।
- 5. यदि काई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निश्चिका मा उत्त प्राधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निश्चिक पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, टिप्जिक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दज करेगा धौर उसकी दावत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगंध का संदरत करेगा।
- 6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मकारियों को उपलब्ध फायदे बढाए जाने है तो, नियोजक माम्हिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उप-लब्ध फायदों में समुखित रूप से बुद्धि की जाने की ब्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों ने अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुक्षेय है।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सदेय रकम उस रकम में कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेश होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, तियोंजक कर्मकारी के विश्विक वारिस/नाम तिर्देशिती की प्रिमिक्त के कप में वानों रकमों के अत्तर के बरावर रकम के सदीय करेगा।
- 8. सामृहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों से काई भी सणोधन , प्रादेशिक भीवण्य निधि प्रायुक्त, महाम के पूर्व प्रानुभावन के बिना नहीं किया नाएगा और जहां किसी सणोधन से कर्मवारियों के हिन पर प्रतिकृत प्रभाव उड़ने की संभावना हो वहां , प्रावेशिक भीवण्य निधि प्रायुक्त, प्रपना मनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवस्त देवा ।
- 9 यदि किसी कारणवा, स्थापना ने कसंवारी, भारतीय जीवन बीसा निगम की उस सामृहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले श्रपना जुका है धर्मन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के धर्मन कर्मवारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो बह रद् की जा सकती है।

10: यदिः,क्रिक्सं कारणवण, नियोजकः उस नियत नारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रमानन रहता है. भीन पालिमा का क्यान हो जाने दिया जाता है तो, खंट रहे की जा सकती है।

- 1.1 नियाजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में फिए गए किसी व्यक्तित्रम की दक्का में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विश्विक वारिमों का जा, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्वीम के अन्तर्गत होते, स्वीम फायदी के सदाय का उत्तरदायित्व नियाजक पर होगा ।
- 12 उन्त स्थापन के संबंधन्मे नियोजक, इस स्कीम के श्रक्षीत श्रान किली किली सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशित्यों/विधिक बारिसों को श्रीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से भीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन श्रीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीनगर सुनिश्चित करेगा ।

[म॰ एम॰-35014/438/82-पी०एफ०-3]

S.O. 4089.—Whereas Messrs Modern Bakeries (1) Limited, Adyar, Madras-20 (TN/10387) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Link Insurance Soleme, 1976 (hereinatter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.
- 4: The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Pan, on the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary prominum in respect of him to the Life Insurance Corporation, of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available 1001GI/82—11

under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

بلداء الداء للساء فبالاقتلام فباتنف لق

- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employee shall pay the difference to the legal heirmominee of the employee as compensation.
- 8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the sail establishment, or the benefits to the employers under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premimum within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(438)[82-PF, 11]

कार आर 40.90.— मैमर्स केर एसर शिर पस्पम लिमिटेड, बोम्बे-पूर्ता रोडे, प्ना-411018 (एस ए/6471), (जिसे एसमें इसके पर्ण्यात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मकारी अविषय निधि और प्रकीष उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 10) (जिसे इसमें इसके पर्ण्यात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क्त) के अधिन छूट दिए जाने के लिए धायेदन किया है;

शीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के बर्मचारी, किसी पृथक श्रीभदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, शरमीय जीवन बीमा निगम की सामृहिक कीमा स्वीम के इसीन जीवन बीमा के क्या में फायदे उटा रहे है शौर ऐसे बर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से श्रीशंक श्रमकृत है जो कर्मचारी निलेप सहब्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पण्चान् उक्त स्कीम कहा गया है) के श्रीन उन्हें श्रमकृत्य हैं ,

प्रत केन्द्रीय सरकार. उक्त प्रधिक्षिय की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवस प्रक्षितरों का प्रयोग करते हुन उपाबद्ध प्रमुक्षी से विलिदिंग्ट मार्नी के प्रधीन रहते हुन, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की श्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपवस्थी के प्रवतन से छूट देती है ।

अनुसूची

- ा उक्त स्थापन के सबंधु में नियोजक प्रावेशिक भाविष्य सिंध भ्रायुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवारणियां भेजेंगा और ऐसे लेखा रखेश तथा निर्देशण के लिए ऐसी सृविध् ए प्रदान करेगा जो केन्द्रिय सरकार, समय समय पर निर्देश्ट करें।
- तियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति
 तित के भीतर सवाय करेगा जा केन्द्रीय सरकार, उत्तम प्रधिनियम की

भारा 17 की उपभारा (3क) के खण्ड (क) के ग्रधीन समय-समय पर निविष्ट करें।

- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रस्तर्गत लेखाणों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीनियम का संदाय, क्षेखाओं का धंतरण, निरीक्षण प्रभारो का संवाय धादि भी है, होने वाले सभी क्यां का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा धनुमोदिश सामृहिक भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, घौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का धनुवाद, स्थापन के सुचना-पटट पर प्रविधत करेगा।
- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मकारी भविष्य निधि का या उक्त मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और असकी बाबत आवश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदक्त करेगा।
- 6. यदि उक्त स्कीम के भ्रश्लीन कर्मवारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों को उपलब्ध कायदों में समृजित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मवारियों के लिए सामृहिक बीमा सकीम के भ्रधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक भनुकृत हों, जो उक्त स्कीम के भ्रधीन धनुकीय हैं।
- 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवैय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिवेशिती की प्रतिकर के छप में दोनों रकमों के प्रंतर के बराबर रकम का संवाय करेगा।
- 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व भनुमीवन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संजोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृत प्रमाव पढ़ने की संसावना हो वहां, प्रादेशिक शविष्य निधि भायुक्त, भपना मनुमीवन देने से पूर्व कर्मचारियों को ग्रंपना दृष्टिकीण स्पष्ट करने का प्रकित्युक्त भवसर देगा।
- 9 यदि किसी कारणवण, स्थापना के कर्मकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भपना चुका है मधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने बाले फायरे किसी रिति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती हैं।
- 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में मसफल रहता है, तो पालिसी को व्यपगंत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम, की बशा में, उन मृत सवस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो, यवि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के घरनगैत होते.
 बीमा कायवों के सवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा !
- 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के श्रधीन झाने वाले किसी सबस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों /विधिक वारिसों को बीमाइत रकम क. संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाइत रकम प्राप्त होने के सात विन के भीतर सुनिष्चित करेगा ।

[सं॰ एस-35014/439/82-पी एफ-2]

S.O. 4090.—Whereas Messrs K. S. B. Pumps Limited, Bombay, Poona Road, Pimpri, Puna-411018 MH/6471, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including Maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employers.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Irsurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees,
- 5. Where the employee, who is already a member of the Fmployees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to

the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

- 10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is hable to be cancelled.
- 11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.
- 12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(439)/82-PF, II]

कां आं 4091 --- मैंसर्स वी कर्नीटका है दी डिविलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, हसन हेरी, पार्क रोड, संग्लोर (के मनः | 6736), (जिसे इसमें इसके पण्डात उनत स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पण्डात उनत मधिनयम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट विए जाने के लिए धावेदन किया है;

धौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उनत स्थापन के कर्मनारी, किसीपृथक धिमदाय या प्रीमियम का संवाय किए धिना ही, भारतीय जीवन भीमा निगम की सामृहिक भीमा स्कीम के ध्रधीन जीवन भीमा के रूप में कायवे उठा रहे हैं धौर ऐसे कर्मनारियों के लिए ये कायवे उन कायधों से अधिक अनुकूल है जो कर्मनारी निक्षेप सहबद्ध भीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्यात् उपत स्कीम कहा गया है) के प्रधीन उन्हें धनुकेय हैं;

मतः केन्द्रीय सरकार, उनत मधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) ग्रारा प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए भीर इससे उपाव्य मनुसूची में बिनिधिन्ट शर्ती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की भवधि के लिए उनते स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट वेती है।

अनुमूची

- उन्हर्न स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि भायुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां चेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निरिष्ट करे ।
- 2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त घछिनियम की भ्रारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के घछीन ममय-समय पर निर्दिट्ट करें।
- 3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रमासन में, जिनके घन्सर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का धंतरण, निर्दाक्षण प्रभारों संवाय प्रावि भी है, होने वाले सभी क्यया का बहुन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
- 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रमुमोदिन सामूहिक बीमा रकीम के शियमों का एक प्रति, भीर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस सनोधन की प्रति तथा कर्मजारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मृज्य वानों ना श्रमुखाद, स्थापन के सूचमा-पट्ट पर प्रवर्धित करेगा।

- 5. यदि कोई ऐसा कर्मकारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या जनत अधिनयम के अधीन भूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजिक नामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत प्रावण्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबक्त करेगा।
- 6. यदि उनत स्वीम के अधीन कर्मवारियों की उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध कायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामृहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से प्रधिक अनुकूल हों, जो उनत स्कीम के अधीन अमृ-कीय हैं।
- 7. सामृहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय रक्तम उस रक्तम से कम है जो कर्मचारी की उन धशा में संदेम होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ती, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्वेशिती की प्रतिकर के इप में दोनों रक्तमों के घंतर के बराबर रक्तम का संदाय करेगा।
- 6. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संघोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि मायुक्त, कर्नाटका के पूर्व मनुमोबन के जिना महीं किया जाएगा भीर जहां किसी संघोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृष प्रभाव पढ़ने की संभावना हो वहां, प्रावेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपना मनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को भवना वृष्टिकोण स्वष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा।
- 9. यदि किसी कारणवण, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बौमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले भपना चुका है भधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के भधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते हैं, सो यह रद्द की जा सकती है।
- 10. यदि किसी कारणवय, नियोजक उस नियत सारीख के भी सर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में भसफस रहता है, भीर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है सो, छूट रज्ज की जा सकती है।
- 11. नियोजक द्वारा प्रीमिथम के संदाय में फिए गए किसी व्यक्तिकार की दशा में, उन मृतसदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न ही गई होती सो उक्त स्कीम के भन्तगंत होते, बीमा फायदों के संदाय का उस्तरदायिस्व नियोजक पर होगा।
- 12, उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के घाधीन ग्राने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार नामनिवंशितियों/ विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से ग्रीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[सं॰एस-35014/442/82-पी॰एक-2] ए० के॰ भट्टराई, श्रवर संभित्र

S.O. 4091.—Whereas Messrs The Karnataka Dairy Development Corporation Limited, Hassan Dairy, Park Road, Bangalore (KN/6736), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than

the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked insurance Scheme, 1976, (hereinalter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Crovernment hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULL

- 1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bangalore, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Covernment may direct from time to time.
- 2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Covernment may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3.A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
- 3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
- 4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Schome as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.
- 5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India
- 6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
- 7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation,
- 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Karnataka and there any amendment is likely to allect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.
- 9, Where, for any reason, the employee, of the said establishment do not remain envered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already dopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
- 10. Where, for any reason, the empoyer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.
- 11. In case of default, it my made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assulance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Schome but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal-heirs entitled for it and in my case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

1No. S-35014(442)/82-PF.II] A. K. BHATTARAI, Under Secy. तई विक्ली, 13 नवस्त्र 1982

्काल्काल 4092 — के.हीय मरकार प्रभव खान श्रम कर्मणा निधि अधिनियम, 1946 (1946 का 22) की धारा 3 की उत्थारा (4) के अनुसरण में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने जान वर्ष के दौरान ब्राधक खान श्रम कल्याण निधि में बित्त-पोषित क्रियाक्तराणों की सिम्मिक्बिन रिपोर्ट उस वर्ष के लेखा बियरण तथा उक्त निधि के वर्ष 3982-83 की प्राप्तियों और स्पर्यों के प्राक्कियन सहित प्रकाधिक कर्मों है।

श्लीग-।

()) सामान्य

भ भक्त जान अस कल्याण निधि का गठन प्रभक्त जान अन कल्याण निधि धिविनियम, 1946 (1946 का 22) के प्रधीन अभक्त जान उद्योग में नियोजित श्रीमको के कल्याण से मंबीधन क्कीमों के विस्त पोषण के लिए किया गया है।

2 अधितियम में, निर्यात की गई सभी अध्यक पर मृत्यान्यार सवा छ प्रतियान की अधिकतम वर पर सीमाशुल्क के उद्यह्म क लिए उपलब्ध किया गया है 2 उपकर की दर, जो कि पहने मृत्यानुसार 2ई प्रतिकात की, 15 जुलाई, 1974 में 31/3 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई। संग्रहणों का प्रामटन विभिन्न प्रधिक उत्पादन मारने वाले क्षेत्रों में उनके ग्रीसत उत्पादन के प्रमुखान में कल्याणकारी उनायों में समित वान की लिए किया जाता है।

暦17~ 2

क्यबस्थित मुक्किश्वर

(क) चिकित्साः

श्रभक खान श्रम कत्याण सगठन द्वारा घानक श्रमिको ग्रीर उनके श्राधिमों के लिए विधिनन प्रकार की निकित्स सुविधाओं की तिःशुक्क व्यवस्था की जाती है उनके श्रम्भांत श्रम्पताली, प्रसूति एव शिष्मुक करवाण केन्द्री का प्रावधान श्रीर श्रमुद्रकण गृहोपनार सहित क्षयोग के उपवार की मुश्रिक्षाए, भ्राध्युर्वेदिक श्रीवधालय सहित श्रीवधालय मंत्राए श्रीर अन्य मुश्रिक्षाए श्रामिल है। रिपोर्ट से सर्वेद्रिक श्रीवधालय स्थाए श्रीर अन्य मुश्रिक्षाए श्रामिल है। रिपोर्ट से सर्वेद्रिक श्रीवधालय स्थाप स्थाप स्थाप श्रीवधालय स्थाप स्थाप स्थाप श्रीर अन्य श्रीक्षा श्रीर के निए कल्याण स्थापनी श्रीरा निम्मिलिकान केन्द्रीय भया श्रीकृष्य श्रम्पताल क्षत्राए जाने रहे:----

ऋम सङ्गा	अस्पताल का नाम	- पक्तंगों की न् संख् य।
1	केन्द्रीय श्रम्थताल, कमी (बिहार)	100
2	केम्द्रीय भ्रस्यताल, संगापुर (राजस्थान)	30
3	केन्द्रीय प्रस्थताल, कालीचेड् (ग्रान्त्र प्रदेग)	30
-1	भौक्षीय अस्पनाम, भिमरी (बिहार)	30
5	क्षेत्रीय अस्पताल, तालपुर (आम्ध्र प्रवेश)	10
'n	केन्द्रीय भस्पताल, कालीचेडु (प्रान्ध्र प्रदेश)	20
	से सलग्न क्षयरोग बार्ड	
7	क्षयरोग भ्रम्पताल, कर्मा, बिहार	50
8	विक्रीय भग्पताल, मईवाप्रम	10 (भाहार के
		साथ)

क्रमके अलावा अभ्रक उत्पादन करने वाले तीन राज्यों में निम्निलिखित ग्रम्थ प्रकार के जिकित्सा संस्थान भी जगतार कार्य करने रहें --

'विकित्स। सम्बान का नाम	आश्रम प्रवेग	विहार	राजस्थान	শূল
 एसोपेथिक श्रीवद्यालय		5	3	7 ^{a)t}
ग्रामुर्वेदक स्रोवधालय	2	8	4	14
प्रसृति भौर जिलु कल्याण केन्द्र	3		3	G
चलते-फिरतं चिकित्सालय एकक	1	3	. 2	6
होस्योपैधिक एकक	1		-	1
सब् समुदाय बेन्ट	-~	5	 -	5

^{*}भ्रात्म्य प्रदेश में एक एखो**पैश्विक भीवधाल**य को 1-9-80 से केब्द्रीय अस्पराज, - कालीबेड्रेके साथ मिला विवा गया है।

्कल्याण नगठन अयरोग से पीडिन कानिकों के उक्कार के जिल् प्रयाणि मृत्वधात्री की व्यवस्था करने के प्रयास करने रहा। अयरोग अस्पनानी भीर क्लिनिकों की स्थापना में प्रजान का अयरोग/सिलिकोसिस से पीडिल प्रभक्त किलिकों के विशेष उपचार की व्यवस्था करने के लिए अयरोग सैनेटेरियम, मदार (प्रजानर) में चार पर्लग प्रार्थित किए गए। इसके मितिस्क, इस प्रयाजन के लिए केन्द्रीय अस्पताल गंगापुर में 10 पर्लगों के प्रथम बार्ब हैं। कल्याण निध अयरोग और छाती के रोगों के सरवारी अस्पताल, नैन्वीर में बार पर्लगों का वेवल अभक कानिकों भीर उनके परिवारों के प्रयोगके लिए आरक्षण जारी रहा।

क्षत्ररोग के ऐसे रोगी को 9 माम की प्रविध तक के लिए 50 स्पये प्रितिमाम का निर्वाह भक्ता दिया जाता है, यदि बहु परिवार के लिए स्वयं निर्माने बाला सदस्य हो। प्रालोच्य क्योर्ट की प्रविध के वौरान बिहार, में 32 मरीजो, राजस्थान में एक मरीज को निर्वाह भन्ता मजूर किया गया। बिबिध विकिस्सा सुविधाए:

षातक हुकैटना लाभ योजना के भन्तमंत, निधि ने व्यक्ति की पत्नी को 250 रुपये की अब 500 रुपये नक संजीधित एक मृश्त भरायगी भीर पांज वर्ष की सबधि के लिए देय 25 रुपये अतिमास के भत्ते की भ्रदायनी भीर प्रत्येच स्कूल जाने बाल बच्चे के लिए उसके 15 वर्ष के झोने कक या विवाह करने तक, जो भी पहने हो, 15 रुपये की मामिक छान्नवृत्ति की श्रवायनी के रूप में विकास सहायना देना जारी रखा।

प्रालोभ्य रिपोर्ट की सर्वाध के दौरान इस योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा राजस्वान में दो मामलों में 600 इपये और कर्मा (बिहार) में मृतको ∗के दो प्राश्चिनों को 700 प्रपये की राणि का खुगतान किया गया।

तेहुलमारी कोव प्रस्पताल में कोव से पीड़ित बिहार के अश्वक खिनकों के उपचार के लिए व्यवस्था जारी रहीं। कैंसर में पीडित प्रश्नक खिनकों के उपचार के लिए के क्षिय प्रस्पताल के लिए (प्रास्ततील) प्रीर राजी में का के में मानसिक रोगों के प्रस्पताल में भाग्तिक रोगों से पीडित खिनकों की उपचार व्यवस्था जारी रहीं। कैंसर से पीड़ित प्रश्नक खिनकों के उपचार की प्रत्नों के प्रस्ताल में पत्रों के पारक्षणों की प्रतुपति जी गई है, जिसमें सामान्यत 9 माम से प्रवाधिक प्रवधि के लिये मुक्त उपचार की व्यवस्था की गई बीर कुछ प्रयाव वाले मामलों में यह प्रवधि 9 माम से प्रविकान हो सकती है, प्रांव उपचार कर रहे चिक्रिया प्राधिकारी ऐसा चाहते हैं।

एसे रोगी, जिन्हें हम प्रावन मही है, सम्मक स्थान अस-करवाण संगठन द्वारा चलाए जा नहें प्रस्तानानों में उनकार भी प्राप्त करते हैं। उनके उनकार के लिए संबंधित राज सरकारों द्वारा निधि सगठनों को महायक सनुदान दिया जाता है। सम्बक्त खान श्रीमकों को 30 द्वारी प्रति जोड़ा ऐनक स्रायिक नागा पर है। के सन्नार्थ की जाती है।

(च) शिक्षा और सनोरंजन सुविधाएं:

शक्षक अभिकों चीर उस्के आश्रियों को जिला चीर मनोरण पृतिशाधों की व्यवस्था करने में लिए, कल्याण संगठमों द्वारा बहुव्येषीय संस्थान जलाए जाते हैं। प्रेरवेक मस्थान में एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र घीर एक रहिना कल्याण केन्द्र जामिल है प्रौढ़ जिला कार्यक नामे का विस्तार करने हेनु जल्याण संगठन ने सहायक घीर प्रौढ़ जिला केन्द्र भी खोले हैं। मनोरजन के प्रयोजनार्थ प्रभक्त खनन केन्द्रों में रेडियों सेट स्थापन किए गए है घीर प्रभक्त अम कल्याण संगठन के प्रयंगित मनोरंजन बनन, पुस्तकालय घीर रिश्चिंग कक्त कार्य रहे हैं। शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कल्याण संगठनों द्वारा प्राथमिक स्कूल/मिडिल स्कूल/हाई स्कूल खलाए जा रहे हैं। इस सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु कल्याण संगठनों द्वारा प्राथमिक स्कूल/मिडिल स्कूल/हाई स्कूल खलाए जा रहे हैं। इस सुविधाओं की व्यवस्था करने वाले संस्थानों की संब्या इस प्रकार है .----

त्रमां	ह संस्थाक्रों का भ्यौरा	ग्रान्ध प्रदेश	बिहार	राज- स्वान	कुल
i	2	3	4	5	6
1.	बहुद्देणीय संस्थान (प्र णिक्षा केन्द्र भीर महिलाकत				
	केन्द्र सहित)	. ~-	y	5	1.4
2	प्रीकृ शिक्षा केन्द्र	. ~-		7	7
3	प्राद्दमरी/प्रारम्भिक स्कृष		4 3 [*]	*	7
4,	मिडिल स्कूल	,	· (4)*	ksk	4
5.	हाई स्कूल	. :	2 1		3
ь.	सहायक केन्द्र		. 1		1
7.	खनिकों के बच्चों के लिए	ζ.			
	छात्रावास/होस्टल .		2 (4)	k## 1	7
8	. चलते फिरते सिनेमा एकक		1 3	1	5
9.	विभागीय रेबियो सेट	. 20	16	8	4.4
10	मनोरंजन वलव .	. h	.		14
11	. भजन-मंबली .	- (9		18
12	. पुस्तकालय ग्रीर वाचनालय		- 15	10	25

^{*1-10-1981} से राण्य सरकारो को हस्तांरित।

चलते फिरते सिनेमा एकक के साध्यम से ग्रीक्षक एवं धार्मिक महुस्व की फिल्में दिखाई जाती हैं।

स्कूली घौर कालेजो में प्रश्नक चानिकों के प्रश्न रहे पुत्रों/पुत्रियो के प्रश्नयन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाली है।

मध्यक खिनकों के लिए मनीरंजन की व्यवस्था करने के लिए समय-समय पर खेल-कृद मार्थोजिल किए जाते हैं भीर विजेताओं को पुरस्कार दिये जनते हैं।

(ग) पेय कल की मुक्किएं

प्रकार अनत असे में पैय जल की असी एक विस्कालिक समस्या है। इस समस्या को हुन करने के लिए कुएं सोवने क्की एक योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के प्रत्यांत प्रमुमानित लागत का 75 प्रतिसंत या वास्त्रविक लागत का 75 प्रतिसंत जो भी कम हो, मालिकों को कुएं खोवने के लिए विया जाता है। प्रान्ध प्रदेश में कालीबेडु गांव में एक स्भागी जल प्रदास योजना चल रही है। प्रभी तक भासा ब्रदेश में 26 कुभों और राजस्थान क्षेत्र में 16 कुभों को खोदा गया है। नुकारवान क्षेत्र में 47 कुभों की सरम्मम की गई है।

^{**} बार में से तीन को पहले ही राज्य मरकार को हस्तातरित किया गया है।

^{***}एक में समामेलित।

(थ) अशिस

दो भ्रायास योजनाएं भ्रमीत् भ्रपना मकान बनाभी योजना भीर टाइप-: भ्रायाम योजना (कम लागत भ्रायाम योजना) चल रही है।

श्रपता सकात बनाओ योजना के श्रन्तर्गन श्रास्येन सकात के लिए 1500 यपये की बिलीय सहायता का भूगतान किया जाता है (600 रुपये श्राधिक महायता के रूप में भीर मासिक किस्तों में बिना ब्याज के रूप में 900 रुपये, जो नौ नर्प से श्रनशिक भवधि में बसूल किए जाएंगे) इस योजना के श्रन्तर्गेत सब तक 718 मकायों को पूरा किया जा सुका है।

टाइप-1 प्रावास योजना के प्रन्तर्गत, साधारण क्षेत्रों में मानक अनु-मानित लागत का 75 प्रतिशत है, जो 6825 रुपये हैं और कपास पैदा करने वाली काली या उभरी हुई मृमि बाले क्षेत्रों में 7825 रुपये या मकानों के निर्माण की धास्तविक लागत का 75 प्रतिशत इनमें जो भी कम है, प्राधिक सहागता दें: जाती है। कार्य घादेश जारी होने के साब बान प्रबन्धकों को माधिक सहायता का 20 प्रतिशत मिप्ति रूप में दिया जाता है। इस योजना के प्रन्तर्गत मब तक 72 मकानों का निर्माण किया भा सुका है।

इससे पूर्व विद्यागीय कालोनी योजना के अन्तर्गत 98 मकान और आधिक सहायता आप्त आधास योजना के अन्तर्गत 12 मकान बनाए गए थे। आवास कार्यक्रमों की भनि को तेज करने के लिए और योजनाओं को अधिक आवर्षित बनाने के लिए एक आधास उप गर्मित गठित को गई थी, जिसने अपनी रियोर्ट अस्तुत कर दी है। इसकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

सॉग-- 3

वर्ष 1981-82 की ब्राप्तियां और क्यय इस प्रकार हैं '---' प्राप्तियो

पहुली भ्रमेल, 1981 को सबसेब	1,92,29,453.88
वर्ष 1981-82 के दौरान प्राप्तियां	1,16,93,000,00
भर्व 1981-82 के दौराम व्यय	84,91,824.00
3 । मार्च, 1982 को भन्त शेन	2,24,30,629.88

भाग--- 4

अर्थ 1982-83 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय

बजट मनुमान		(मपदे लाख	तें में)
प्राप्तियां		10	0 0 0
ध्यय े		9:	2 95
	_		_

[६ क्या जेंड-16016/1/82-ए.स०-3/ डब्स्यू०-2] टी० थी० सल्होला, सबर सचिव

New Delhi, the 13th Nov., 1982

S.O. 4092.—In pursuance of Sub-Section (4) of Section 3 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (XXII of 1946) the Central Government hereby publish the following report of the activities financed from the Mica Mines Labour Welfare Fund during the year ending 31st March, 1982 together with a statement of accounts for that year and an estimate of receipts and expenditure of the said fund for the year 1982-83.

PART-I

1 General

The Mica Mines Labour Welfare Fund has been constituted under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946, (22 of

1946) for financing schemes relating to the Welfare of labour employed in the mica mining industry.

2. The Act provides for the levy of a duty of customs; on all mica exported, upto a maximum rate of 6-1/4 per cent ad-valorem. The rate of cess, which was 2-1/2 per cent ad-valorem previsouly, has been increased to 3-1/2 per cent with effect from the 15th July, 1974. The collections are allocated for exponditure on welfare measures among the various mica producing areas in proportion to their average production.

PART-II

Facilitles provided

A. Medical

Various types of medical facilities for mica workers and their dependents are provided free of cost by the Mica Mines Labour Welfare Organisations. These include provision and maintenance of hospitals, maternity and child welfare centres, facilities for treatment of T.B. including domiciliary treatment dispensary services including Ayurvedic dispensaries and other facilities, etc. The following Central and Regional hospitals continued to be maintained by the Welfare Organisations for the treatment of mica miners and their dependents during the year under report:—

Sl. Name of the Hospitals No	Bed Strength
1. Central Hospital, Karma (Bihar)	100
2. Central Hospital, Gangapur (Rajasthan)	30
3. Central Hospital, Kalichedu (Andhra Pradesh)	30
4. Regional Hospital, Tisri (Bihar)	30
5. Regional Hospital, Talupur (Andhra Pradesh)	10
6. T. B. Ward attached to Central Hospital, Kaliched (Andhra Pradesh).	u 20
7. T. B. Hospital, Karma, (Bihar)	50
8. Regional Hospital, Sydapuram	10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Dietary)

In addition, the following other medical institutions also continued to function in the three mica producing States.

States :

Medical Institutions	Andhra Pradesh	Bihar	Rajas- than	Total
Allopathic Dispensaries		5	3	* 7
Ayurvedic Dispensaries	2	8	4	14
Maternity and child welfare centres.	3		3	6
Mobile Medical Unit	1	3	2	6
Homoeopathic Unit	1		_	1
Small Community Centres		5	– .	5

One Allopathic Dispensary in A. P. region has been merged with Central Hospital, Kalichedu w.e.f. 1-9-1980.

The Welfare Organisations have been endeavouring to provide adequate facilities for treatment of the miners suffering from T.B. Apart from setting up of T. B. Hospitals and clinics, four beds remained reserved at T.B. Sanatorium, Madar (Ajmer), for providing specialized treatment to mica miners suffering from T.B./Silicosis. Besides, there is a 10 bedded segregated wards in the Central Hospital, Gangapur, for the purpose. Four beds in the Govt. Welfare Fund T.B. & Chest Disease Hospital, Nellore, continued to be reserved for the exclusive use of mica miners and their families.

A subsistence allowance of Rs. 50 per month is granted to a T.B. patient for a period upto 9 months where he happens to be the only earning member of the family. During the period under report 32 patients in Bihar, one patient in Rajasthan were sanctioned Subsistence Allowance.

Miscellaneous Medical Facilities

Under the Fatal Accident Benefit Scheme, the Fund continued to provide financial assistance to the spouse of a miner in the form of a lumpsum payment of Rs. 250/- (since revised to Rs. 500/-) and a monthly allowance of Rs. 25/- payable for a period of five years and a monthly scholarship of Rs. 15/- payable in respect of each school going child till he/she attains the age of 15 or is married, whichever is earlier.

During the period under report, an amount of Rs. 600/to two cases in Bhilwara, Rajasthan and Rs. 700/- to two dependents of the deceased in Karma, Bhiar, was paid under this Scheme.

Arrangements continued for the treatment of mica miners of Bihar suffering from Leprosy at the Tetulmari Leprosy Hospital. For the treatment of mica miners suffering from cancer, arrangements continued at the Central Hospital, Kalla (Assansol), and for mental diseases at the Mental Hospital, Kanke, Ranchi. Under the scheme for the treatment of mica miners suffering from cancer, reservation of beds in a hospital have been allowed which provides free treatment generally for a period not exceeding 9 months and in exceptional cases, this period can be more than 9 months if the treating medical authority so desire.

The non-entitled patients also get treatment from the hospitals run by the Mica Mines Labour Welfare Organisation. For their treatment, Grant-in-aid is paid by the concerned State Govts. to the Fund Organisations. Spectacles are supplied to the Mica Mines Workers at a cost not exceeding Rs. 30/per pair of spectacles.

(B) Educational and Recreational facilities

For providing educational and recreational facilities to mica workers and their dependents, various Multipurpose Institutes, each comprising of an Adult Education Centre and Women's Welfare Centre, are run by the Welfare Organisations. In order to expand the Adult Education activities, Feeder and Adult Education Centres have also been opened by the Welfare Organisations. For recreational purpose, Radio Sets have been installed in mica mining areas and recreation clubs as well as Library and reading rooms have been functioning under the Mica Mines Labour Welfare Organisations. In order to provide educational facilities, Primary Schools/Middle Schools/High Schools are run by the Welfare Organisations. The number of Institutions providing the above facilities are as under:

Sl. Partic	culars of itutions	A.P.	Bihar	Rajas- than	Total
1	2	3			- 6
(with Edu c s	on's Welfare		9	5	14
2. Adult	Education Cen-			7	7
 Prima School 	iry/Elementary vis	4	3*		7
4. Midd	le Schools		4@1	.,	4
5. High	Schools	2	1		3

1 2	3	4	5	6
6. Feeder Centre		1	, .	1
 Boarding Houses/Hos- tels for miners' child- ren. 	2	4**	1	7
8. Mobile Cinema Units	1	3	1	5
 Departmental Radio Sets. 	20	16	8	44
10. Recreation Clubs	14			14
11. Bhajan Mandalies	9	9		18
12. Library & Reading Rooms.		15	10	25

- *Since transferred to the state Govt. w.e.f. 1-10-81.
- @Out of four, three have already been transferred to State Govt.
- **Amalgamated into one.

Films of educational and religious value and exhibited through a mobile cinema Unit.

Scholarships are awarded to the sons/daughters of mica miners studying in schools and colleges for their studies.

Games and Sports are organised periodically, to provide recreation to mica miners and prizes are also awarded to the winners.

(C) Drinking Water facilities:

Scarcity of drinking water is a chronic problem in mica mining areas. With a view to resolve this problem, a scheme for sinking of wells has been introduced. Under this scheme, 75% of the estimated cost or 75 per cent of the actual cost, whichever is less, is paid to the mine owners for sinking wells. In Kalichedu village in Andhra Pradesh, a permanent water supply scheme is in vogue. The two Water Supply Schemes i.e. Talupur and Sudapuram are also under consideration. Twenty six wells in Andhra Pradesh region and 16 in Rajasthan region have been sunk so far. Forty-seven wells in Rajasthan region have also been renovated.

(D) Housing

Two schemes, viz. Build Your Own House Scheme, Low cost Housing Scheme are in vogue.

Under Build Your Own House Scheme, financial assistance to the tune of Rs. 1,500/- per tenement (Rs. 600/- in the form of subsidy and Rs. 900/- in the form of interest free loan recoverable in monthly instalments spread over a period not exceeding 9 years) is paid. 718 houses have so far been completed under this scheme.

Under Type I Housing Scheme, subsidy payable is 75% of standard estimated cost, which is Rs. 6,825/- in ordinary area and Rs. 7825 in black cotton or swelly soil area or 75% of actual cost of construction of houses, whichever is less. 20% of the subsidy is payable in advance to the mine management, with the issue of work order. 72 houses have so far been completed under this scheme.

Earlier, 98 houses were built under the Departmental colony scheme and another 12 houses under subsidized house scheme were constructed. With a view to accelerate the pace of housing programmes and to make the schemes more attractive, a Housing Sub-Committee was constituted, which has since submitted its report. This is being examined in the Ministry.

PART-III

The receipts and expenditure for the year 1980-81 are as follows:—

Receipts

Opening balance as on 1st April, 1981 Receipt during the year 1981-82	1,92,29,453.88 1,16,93,000.00
Expenditure during the year 1981-82 Closing balance as on 31st March, 1982	84,91,824.00 2,24,30,629.88
PART-IV	

Estimated receipts and expenditure for the

year 1982-83	-						
Budget Estimates				(Rs.	in	lakhs	
Receipts						100	,00
Expenditure						92	.95
	ſĖ.	No.	Z-16016/1/	82-M	. 11	I/W.	11]

T. D. SALHOTRA, Under Secy.